प्रेरणा

जो है उसके लिए धन्यवाद कहना, खुशी की शुरुआत है। -विलियम आर्थर वार्ड

संपादकीय

मादुरो वाला तर्क मुनीर पर क्यों लागू नहीं करते ट्रम्प?

दुनिया के कुल तेल भंडार का 18.17% हिस्सा और प्रचुर रेयर अर्थ मटैरियल का स्वामी वेनेजुएला अचानक अमेरिका का दास बन गया। इसके मुखिया मादुरो को सैनिक अभियान में पकड़कर अमेरिकी जेल में डाल दिया गया। वेनेजुएला के पास तेल शोधन की क्षमता न होने के कारण अमेरिकी कंपनियों की गिद्ध-दृष्टि उन पर लग गई। अपने पहले कार्यकाल से ही ट्रम्प मादुरो से नाराज रहे थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाते हुए 5 करोड़ डॉलर कर दिया। मादुरो ने प्रतिक्रिया में चीन से तेल और रूस से हथियार खरीद की नीति बनाई तो ट्रम्प की नाराजगी और बढ़ गई। माना जा रहा है कि वेनेजुएला सरकार के अंदर के लोगों ने ही बड़ी इनामी रकम के लालच में अमेरिकी सेना को मादुरो के महल तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर ड्रग कार्टेल चलाने की सजा यह है तो जिस पाकिस्तान को सबूत सहित यूएन से लेकर स्वयं अमेरिका ने आतंकी पनाहगार माना है, उसके सबसे मुखर चेहरे मुनीर को किस जेल में होना चाहिए? मुनीर को पाकिस्तान का अघोषित तानाशाह बनाने में मदद किस प्रजातांत्रिक मूल्य की रक्षा कही जाएगी? ट्रम्प के मागा का एक साल पहले नारा था- अब और युद्ध नहीं, जबकि आज नारा है- वेनेजुएला पर हमला। अगर यही दोहरा रवैया चलता रहा तो फिर रूस के यूक्रेन पर हमले या चीन के ताइवान पर दावे को कैसे गलत ठहराया जा सकेगा?

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

सत्संग सुनने जाएं तो तन के साथ मन को भी स्नान कराएं

सत्संग सुनने का भी अपना प्रोटोकॉल है। गरुड़ जी जब काकभुशुंडि जी के यहां गए तो सत्संग हो रहा था वटवृक्ष के नीचे। तुलसीदास जी लिखते हैं- करि तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गयउ हृदयँ हरषाना। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वटवृक्ष के नीचे गए। अब तीन बातें यहां लिखी हैं। पहला, स्नान किया, फिर जलपान किया और फिर प्रसन्नचित्त हुए। जब भी सत्संग सुनने जाएं, तन की शुद्धि करें, कुछ खा-पीकर भी जाएं क्योंकि भूखे भजन न होय गोपाला और प्रसन्नचित्त रहें। दुनियादारी की चिंता जूते-चप्पल के साथ ही बाहर उतार कर आएं। यहां स्नान का एक और गहरा अर्थ है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को मंत्र-स्नान भी करना चाहिए। तन को हम पानी से स्नान कराते हैं, पर मन को स्नान कराने के लिए प्राणवायु लगती है। तो कोई मंत्र लें, सांस में उसको उतारें और शरीर में ऐसे बहाएं जैसे हम अपने मन को धो रहे हैं। फिर सत्संग में बैठिए। इतना करने के बाद जो सत्संग में हमें मिलेगा, वो अनूठा, अद्भुत और बहुत उपयोगी होगा।

•Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने मनमानी की

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का कोई कानूनी आधार नहीं है

अमेरिका

मनोज जोशी

विदेशी मामलों के जानकार

manoj1951@gmail.com

वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया, उसकी कानूनी वैधता को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को मादुरो की गिरफ्तारी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सैन्य समर्थन देने की तरह बताया है। मादुरो पर 2020 में नार्को-आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में अभियोग लगाया गया था। लेकिन मजे की बात है कि मादुरो की पत्नी सेलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और संशोधित अभियोग का हिस्सा बना दिया गया है। जबकि 2020 के मूल अभियोग में उनका नाम शामिल नहीं था।

अधिकांश अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों, यूएन और कई देशों की सरकारों का कहना है कि अमेरिका की ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उनकी दलीलों की बुनियाद में राज्यसत्ता की सम्प्रभुता है। जबकि ट्रम्प प्रशासन इस ऑपरेशन का बचाव एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में करता है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कानून के तहत नार्को-आतंकवादी घोषित एक व्यक्ति को मुकदमे के लिए कठघरे में लाना है।

प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सम्प्रभु देश के राष्ट्राध्यक्षों को विदेशी अदालतों में इम्युनिटी प्राप्त होती है। स्वयं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1812 में इस विषय पर दिए एक निर्णय में इसे मान्यता दी थी। लेकिन ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि मादुरो वैध राष्ट्रपति नहीं हैं। तथ्य तो यही है कि उन्होंने बार-बार चुनाव जीते हैं और वे अपने देश की राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद द्वारा निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इसलिए चुनावों में धांधली का दावा भी किस अमेरिका के बूते किया जा सकता है?

दूसरा, और अधिक गंभीर पहलू वेनेजुएला पर कब्जा करके उसके तेल संसाधनों का नियंत्रण अपने हाथों में लेने की अमेरिकी योजना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि उन्होंने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अमेरिकी निर्देशों का पालन करने के लिए मना लिया है। हालांकि इसके बाद रोड्रिगेज ने अमेरिकी कार्रवाइयों की निंदा की।

ट्रम्प यह भी कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में एक ऑक्युपेशन-फोर्स के साथ ही तेल विशेषज्ञों को भी भेज सकता है, ताकि उसके तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में लिया जा सके। लेकिन किसी देश पर कब्जा करने और उसके संसाधन को वैश्विक बाजार में बेचने के लिए न तो अमेरिकी कानून और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून ट्रम्प को कोई कानूनी इजाजत देते हैं।

यूएन चार्टर का अनुच्छेद 2(4) आत्मरक्षा के औचित्य या यूएन की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग करने या इसकी धमकी देने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इन अर्थों में वेनेजुएला पर किया गया हमला यूएन चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन है। नार्को-तस्करी का आरोप भी केवल इन अवैध अमेरिकी कार्रवाइयों को जायज ठहराने के लिए ही लगाया गया है। वास्तव में, अमेरिका की आधिकारिक नेशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025 में मादुरो के बारे में बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, इसमें मैक्सिको, कोलंबिया और कुछ अन्य लैटिन अमेरिकी देशों को मादक पदार्थों के प्रमुख स्रोत के रूप में चिह्नित किया गया था।

अमेरिकी कानून के तहत भी इस कार्रवाई की वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, लेकिन ट्रम्प प्रशासन इसे महज एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई बता रहा है। जबकि ऐसी कार्रवाइयों में पूरे नौसैनिक बेड़े, 150 विमानों और हजारों कर्मियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रम्प तो यह भी संकेत दे चुके हैं कि यदि पहली कार्रवाई विफल होती तो अमेरिका दूसरा और बड़ा हमला करने जा रहा था।

19वीं-20वीं सदी में अमेरिका ने मैक्सिको, क्यूबा, निकारागुआ, होंडुरास, पनामा पर हमले किए थे। चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, पेरू, ब्राजील में तख्तापलट भी कराए। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल का पुराना अतीत है।

यह तो साफ है कि ट्रम्प की नजर वेनेजुएला के 350 अरब बैरल के तेल भंडार पर है। पिछले लगभग बीस वर्षों में, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला का उत्पादन प्रतिदिन 32 लाख बैरल (बीपीडी) के उच्च स्तर से गिरकर मात्र 10 लाख बीपीडी रह गया है। अब ट्रम्प के अनुसार अमेरिका उसके तेल उद्योग को अपने नियंत्रण में लेगा, उसका पुनर्गठन करेगा और तेल का निर्यात करेगा। ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि इससे मिलने वाला धन न केवल वेनेजुएला के लोगों के भले के लिए इस्तेमाल होगा, बल्कि अमेरिका को हुए नुकसान की भरपाई भी करेगा।

लेकिन हकीकत यह है कि अगर अमेरिका वास्तव में ही वेनेजुएला के तेल उद्योग का संचालन शुरू कर देता है, तो वहां के लोगों को अपने तेल से मुनाफा मिलने में अभी बहुत समय लगने वाला है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • दोनों देश नई हकीकत को स्वीकार रहे हैं

पाकिस्तान को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं अब बदल रही हैं

कूटनीति

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अस्थिरता कायम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही दोनों में कोई बड़ी लड़ाई, कूटनीतिक संबंधों में नाटकीय विच्छेद या लंबा सैन्य तनाव नहीं हुआ है, फिर भी रणनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। जो नियम कभी संकट के वक्त लागू होते थे- वे बदल रहे हैं। दोनों देश इस नई वास्तविकता के प्रति खुद को ढाल भी रहे हैं।

भारत के लिए वही सवाल आज भी कायम है कि पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा अगली बार बर्दाश्त से बाहर हुई तो हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे? हाल में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह षड्यंत्र और व्यापक रूप ले सकता था, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। ऐसे में उपरोक्त सवाल का जवाब घोषणाओं नहीं, हालिया अनुभवों और पाकिस्तान में हो रहे बदलावों में छिपा है।

इसे समझने के लिए ऑपरेशन सिंदूर सबसे अहम संदर्भ है। इसने हमारे माइंडसेट को उजागर किया। भारत ने दिखाया कि वह परमाणु सीमा में रहते हुए संतुलित सैन्य बल इस्तेमाल करने को तैयार है। इसमें राजनीतिक मंजूरी जल्द मिल जाती है और लक्ष्य भी सीमित होते हैं। संदेश यह था कि आतंकवाद के जवाब में भारत अब महज संयम पर ही निर्भर नहीं रहेगा।

उतना ही महत्वपूर्ण यह जानना भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कौन-से संकेत नहीं दिए। भारत छोटे ऑपरेशन, तय समय सीमा और सैन्य तनाव में बढ़ोतरी के ऐसे तरीकों में नहीं बंधा, जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता हो। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि भविष्य में सैन्य कार्रवाई प्रतीकात्मक या निश्चित अवधि वाली होगी। यह अस्पष्टता भी मायने रखती है। यदि विरोधी पहले ही जान ले कि जवाबी कार्रवाई कैसे, कब और कितनी देर में होगी तो वह उसे अपने आकलन में शामिल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानबूझकर ऐसे सवालों को अनुत्तरित छोड़ा गया था।

जब भारत प्रतिक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहा था तो पाकिस्तान के भीतर भी बदलाव चल रहे थे। पाकिस्तानी संविधान में प्रस्तावित 27वां संशोधन महज एक कानूनी बदलाव नहीं है। सेना प्रमुख को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना, सेना के सामूहिक ढांचे को समाप्त करना और परमाणु कमान को पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में लाना- यह बताता है कि सारा नियंत्रण अब शीर्ष पर केंद्रित हो रहा है।

भारत के लिए चुनौती यह है कि वह पाकिस्तान के इन संकेतों का जवाब कैसे दे, जिससे तनाव भी ना बढ़े और यह भी नहीं दिखे कि वह चुपचाप बैठा है। परमाणु धमकियों के कारण यदि पारंपरिक और मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी रोक दी जाएं तो यह पाकिस्तान की प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति को और प्रभावकारी बनाता है। इसलिए प्रतिरोध का मतलब है कि भारत दिखाए परमाणु हमले की धमकियां उसके विकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगातीं। इसका मतलब अनावश्यक तनाव बढ़ाना नहीं, कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखना है।

कश्मीर इस पूरे बदलाव का केंद्र बना हुआ है। हाल के वर्षों में कश्मीर घाटी की तुलना में जम्मू, खासकर रजौरी, पुंछ और कठुआ में अधिक हिंसा हुई है। यह मायने रखता है। पाकिस्तान का सियासी नैरेटिव और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति जम्मू के बजाय कश्मीर के इर्द-गिर्द घूमती है। घाटी में लंबे समय की शांति उस मुद्दे पर पाकिस्तान की प्रासंगिकता घटाती है, जिसे वह अपनी पहचान का मूल मानता है। पहलगाम हमला इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह किसी सतत अभियान की शुरुआत से ज्यादा ऐसे वक्त में कश्मीर में फिर से मौजूदगी दिखाने का प्रयास लगता है, जब वहां पर्यटन, नागरिक गतिविधियां और सामान्य स्थिति की भावना मजबूत हो रही थी। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तान को कश्मीर में अपनी प्रासंगिकता घटती महसूस हुई, उसने खुले टकराव के बजाय सीमित तौर पर व्यवधान पैदा करने वाली हरकतों का सहारा लिया।

आज पाकिस्तान के प्रतिरोध का मतलब है भारत यह दिखाए कि परमाणु हमले की धमकियां उसके विकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगातीं। इसका मतलब अनावश्यक तनाव बढ़ाना नहीं, बल्कि कार्रवाई की अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना है।

स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान रिश्ते किसी जरूरी टकराव की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वे बदली हुई मान्यताओं के तहत संचालित हो रहे हैं। भारत ने बिना कोई सीमा तय किए जवाबी कार्रवाई की इच्छाशक्ति दिखाई है तो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी रणनीति पर निर्भरता समाप्त किए बिना केंद्रीकरण के जरिए ताकत दिखाने का प्रयास किया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दैनिक भास्कर

अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

रिसर्च

वैक्सीनों से बुजुर्गों को कई अन्य बीमारियों में फायदे

पाउलास्पैन

कई अध्ययनों से पता लगा है कि विभिन्न बीमारियों की वैक्सीन लगवाने से बुजुर्गों को दूसरे फायदे हो सकते हैं। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉ. विलियम स्काफनेर कहते हैं, जिन बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है, उसके अलावा दूसरे फायदों की सूची लंबी है। नेशनल रिसर्च काउंसिल इटली की डॉ. स्टीफेनिया मैगी कहती हैं, वैक्सीन बढ़ती आयु में शारीरिक और मानसिक गिरावट रोकने का अच्छा टूल है।

यूरोप,एशिया और उत्तर अमेरिका में 10 करोड़ 40 लाख लोगों पर किए गए 21 विभिन्न अध्ययनों का निष्कर्ष है कि त्वचा की बीमारी शिंगल्स (दाद) की वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में मानसिक बीमारी डिमेंशिया का जोखिम 24% कम पाया गया है। फ्लू की वैक्सीन में यह गिरावट 13% रही। निमोनिया इंफेक्शन से बचाव की वैक्सीन से अल्जाइमर में 36% कमी का खतरा रहा। फ्लू की वैक्सीन लगवाने वाले स्वस्थ बुजुर्गों में दिल की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खतरा कम पाया गया है। इंफ्लूएंजा की वैक्सीन का संबंध दिल के दौरे और ब्रेन स्ट्रोक के कम खतरे से है। डेनमार्क में एक बड़ी स्टडी में वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों में दिल और सांस की बीमारियों की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में 10% गिरावट पाई गई है। शिंगल्स की वैक्सीन लेने वाले लोगों में डिमेंशिया कम पाई गई है।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी भारत में भी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को चैटबॉट मिलेंगे, यूएई, अमेरिका में भी इस पर काम

कई देशों के स्कूलों में एआई टूल्स से पढ़ाई, लेकिन इनसे बच्चों की मूल्यांकन करने की क्षमता घटने की आशंका

नताशा सिंगर

अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियों के अभियान से प्रभावित होकर अब कई देशों की सरकारों ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में एआई टूल्स की मदद से पढ़ाई शुरू कर दी है। दुनियाभर में सरकारें एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। भारत में भी ओपनएआई कंपनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए चैटजीपीटी मुहैया कराएगी।

कुछ टेक कंपनियों के प्रमुखों का कहना है कि एआई चैटबॉट्स सीखने के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। उनकी दलील है कि इन टूल्स से शिक्षकों का समय बच सकता है। इसके साथ ही छात्रों को एआई से चलने वाली अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। लेकिन नए एआई प्रोडक्ट्स के तेजी से फैलाव से युवाओं के लिए कई खतरे भी पैदा हो सकते हैं। कुछ बाल और स्वास्थ्य समूहों की चेतावनी है कि इससे बच्चों का विकास प्रभावित होने का जोखिम है।

माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी में पाया गया कि पॉपुलर एआई चैटबॉट्स से बच्चों की मूल्यांकन करने और विश्लेषण करने की सोच कम हो सकती है। एआई बॉट्स गलत जानकारी दे सकते हैं। कुछ शिक्षकों को बड़े पैमाने पर एआई के जरिए चीटिंग करने वाले छात्रों से जूझना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सिलिकॉन वैली वर्षों से लैपटॉप और लर्निंग एप्स को क्लासरूम में लाने के लिए अभियान चला रही है।

पेरू में प्रोफेसरों और अर्थशास्त्रियों द्वारा सैकड़ों स्कूलों में किए गए अध्ययन के मुताबिक स्कूलों में कंप्यूटर की पहुंच बढ़ाने के 'हर बच्चे को एक लैपटॉप' प्रोग्राम से बच्चों की चीजों को समझने, संज्ञान की क्षमता और रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ है।

यूनिसेफ जैसी बच्चों की एजेंसियां सावधानी बरतने और स्कूलों को जरूरी दिशा-निर्देश देने की सलाह दे रही हैं। यूनिसेफ के डिजिटल पॉलिसी विशेषज्ञ स्टीवन वोसलू ने एक पोस्ट में लिखा है, हर बच्चे को एक लैपटॉप प्रोग्राम का नतीजा बेकार खर्च और सीखने में गिरावट के रूप में सामने आया है।

© The New York Times

एस्टोनिया ने अपने हिसाब से बदला एआई चैटबॉट

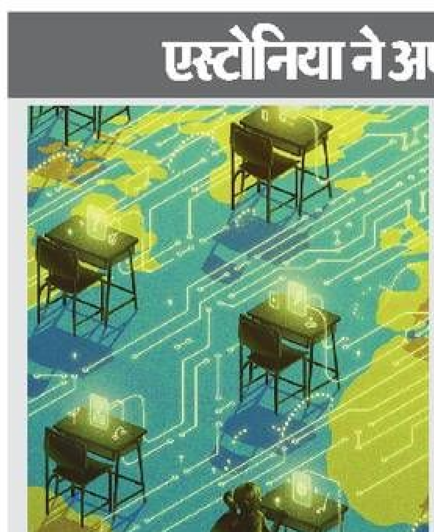

एस्टोनिया और आइसलैंड जैसे देशों में भी बड़े पैमाने पर शिक्षा के लिए एआई बॉट्स का उपयोग हो रहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया में 90 प्रतिशत हाईस्कूल छात्र स्कूल की पढ़ाई ओपनएआई के चैटजीपीटी से कर रहे हैं। वहीं कुछ छात्र एआई से होमवर्क भी करने लगे हैं। लिहाजा, एस्टोनिया सरकार ने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव कराए हैं। चैटबॉट एस्टोनिया की भाषा में छात्रों के सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय सवाल भी पूछता है। वहीं आइसलैंड में स्कूलों ने अपना एआई पायलट शुरू किया है। शिक्षक गूगल के जेमिनी और एंथ्रोपिक के क्लॉड चैटबॉट से लेसन प्लान करते हैं। इसके नतीजों का अध्ययन अब किया जाना है।

लाखों छात्र और शिक्षक चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे

- माइक्रोसॉफ्ट संयुक्त अरब अमीरात में दो लाख छात्रों, शिक्षकों के लिए एआई टूल्स की सप्लाई करेगी। साथ ही कंपनी थाईलैंड में शिक्षकों छात्रों को एआई ट्रेनिंग देगी
- कजाखस्तान में ओपनएआई कंपनी एक लाख 65 हजार शिक्षकों के लिए चैटजीपीटी एजुकेशन सेवा देगी।
- इलॉन मस्क की कंपनी का ग्रोक चैटबॉट अल सल्वाडोर के स्कूलों में दस लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाने में उपयोग किया जाना है ।
- अमेरिका के फ्लोरिडा में एक लाख हाई स्कूल छात्रों को गूगल का जेमिनी चैटबॉट दिया गया है। ब्रोवाड काउंटी के पब्लिक स्कूलों में हजारों शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट चैटबॉट मिला है।

इस हफ्ते चर्चा में...

सिनेमा टिकटों की बिक्री में दो फीसदी बढ़ोतरी

80 हजार करोड़ रुपए
के टिकट बेचे हैं, अमेरिका और कनाडा में मूवी थिएटरों ने 2025 में। यह पिछले साल के मुकाबले दो फीसदी ज्यादा है।

01 करोड़ छात्र
अमेरिका में अब तक स्टूडेंट लोन नहीं चुका पाए हैं। सरकार डिफाल्टर छात्रों को राहत देने की योजना चला रही है।

9 लाख बैरल प्रतिदिन
रह गया है अब वेनेजुएला का तेल उत्पादन। 1997 में ये 35 लाख बैरल रोजाना था।

बिजनेस

ट्रम्प टैरिफ का वैसा प्रभाव नहीं जैसे की उम्मीद थी

एनास्वांसन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल विदेशी सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे। लेकिन विशेषज्ञों ने टैरिफ का जैसा प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया था, वैसा अब तक सामने नहीं आया है। हार्वर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के एक रिसर्च पेपर में बताया गया कि ट्रम्प ने जितना टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, उससे कम टैरिफ आयातकों को चुकाना पड़ा है। दरअसल कई देशों और उद्योगों को टैरिफ में छूट के कारण ऐसा हुआ है। सरकार की टैरिफ आय और कुल आयात के मूल्य का विश्लेषण कर अर्थशास्त्री इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सितंबर के अंत में अमेरिकी टैरिफ की वास्तविक दर 14.1% रही। यह आंकड़ा सरकार द्वारा घोषित टैरिफ दर का आधा है। पेपर के अनुसार सितंबर में टैरिफ की दर 27.5 प्रतिशत रही। यह अप्रैल में सबसे अधिक 32.8 प्रतिशत थी।

© The New York Times

ओपिनियन पुतिन अपने मन मुताबिक यूरोप पर कब्जा करना चाहेंगे

वेनेजुएला पर हमले से पुतिन का हौसला बढ़ेगा

एमगेसेन, न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण के बाद कई टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया कि यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आघात है क्योंकि वेनेजुएला और रूस सहयोगी देश हैं। लेकिन इसके उलट यह पुतिन की विजय है। ट्रम्प की इस कार्रवाई से पुतिन को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी सरकार कुछ भी सोचे पर वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हुए अपहरण से इंसाफ नहीं होगा। किसी देश पर कब्जा करने और उसे उपनिवेश बनाने से आजादी नहीं आएगी। शनिवार को ट्रम्प ने चार बार कहा कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे।

पुतिन ने दावा किया था कि यूक्रेन पर हमला वहां की जनता को आजाद करने का मिशन है। उनका कहना था कि यूक्रेन ने उनके देश द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे का अवैध इस्तेमाल किया है। ट्रम्प ने भी इसी तरह दावा किया है कि मादुरो ने अमेरिकी कंपनियों की मदद से बनी तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर अमेरिकी संपत्ति की सबसे बड़ी चोरी की है।

चुनावों में धांधली कर सत्ता में रहने वाले तानाशाह मादुरो और यूक्रेन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच जमीन, आसमान का अंतर है। लेकिन आक्रांताओं-ट्रम्प और पुतिन के बीच की समानताओं पर गौर कीजिए। पुतिन वर्षों से कुछ शक्तिशाली लोगों के प्रभाव क्षेत्र में विभाजित दुनिया का सपना देखते रहे हैं। ट्रम्प भी विश्व को इसी तरह देखते हैं।

© The New York Times

ट्रम्प-पुतिन के बीच कई समानताएं

सहयोग, न्याय और मानव अधिकारों के यूरोपीय मूल्यों को ट्रम्प-पुतिन हिकारत की नजर से देखते हैं। पुतिन के भाषणों में यह तेवर नजर आता है। वहीं ट्रम्प राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत वेनेजुएला और क्यूबा पर कब्जा कर सकते हैं। लगता है, वे जल्द ही कनाडा को 51 वां राज्य बनाने की चर्चा करने वाले हैं। इन हालातों में पुतिन भी मर्जी मुताबिक यूरोप पर कब्जा करना चाहेंगे। ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद यूरोप के खिलाफ रूस का अप्रत्यक्ष युद्ध बढ़ गया है।

कूटनीति इजराइल, अमेरिका का भी डर

ईरान लोगों के विरोध व बाहरी सैनिक हमलों के दोहरे खतरे से जूझ रहा

फरनाजफसीही

ईरान के शासक घरेलू असंतोष और बाहरी सैनिक खतरे का सामना कर रहे हैं। दोनों मामलों में सरकार अंधे मोड़ पर है। उसके पास जनता के गुस्से का कारण बनी कमजोर आर्थिक स्थिति को बदलने की रणनीति नहीं है।

ईरान में एक सप्ताह से अधिक समय से आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि ये पिछले वर्षों में हुए दो बड़े जनविरोधों के समान उग्र नहीं हैं। 2022 में महिलाओं की अगुआई में विरोध भड़का था। 2019 में पेट्रोल-डीजल- गैस की कीमतों के विरोध में जनता सड़क पर आ गई थी। मौजूदा असंतोष के बीच अमेरिका और इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुक्रवार को धमकी दी थी कि यदि ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि अन्य देशों को इस पर गौर करना चाहिए।

उग्रपंथी ईरानी विशेषज्ञ अली गोलहाकी ने फोन पर इंटरव्यू में कहा कि वेनेजुएला और सीरिया के शासकों के पतन में अर्थव्यवस्था की खराब हालत की मुख्य भूमिका रही है। ईरान के लिए सबक है कि वैसी ही स्थिति यहां न होने पाए। जब पुलिस, सुरक्षा बल जीवन चलाने के लिए संघर्ष करते हैं तब बचाव की पंक्ति ध्वस्त हो जाती है। © The New York Times

बिज़नेस ब्रीफ

टोरेंट फार्मा एनसीडी से जुटाएगी 12,500 करोड़

नई दिल्ली | टोरेंट फार्मा नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड जारी कर 12,500 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। ये बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बेचे जाएंगे और प्रत्येक की फेस वैल्यू 1 लाख रुपए होगी। बॉन्ड की अवधि, अलॉटमेंट और मैच्योरिटी इश्यू के समय तय होगी। ये एनएसई के होलसेल डेट मार्केट में लिस्ट होंगे।

पेटीएम ने 16.6 करोड़ रु. के ईसॉप जारी किए

मुंबई | पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने 1,23,908 ईसॉप (कर्मचारी स्टॉक विकल्प) को मंजूरी दी है। इन ईसॉप का मूल्य मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से करीब 16.6 करोड़ रुपए है। कंपनी का यह कदम कर्मचारियों को प्रेरित करने और कंपनी में बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है।

बड़े करदाताओं के लिए स्वचालित टैक्स अनुपालन

नई दिल्ली | कॉरपोरेट, विदेशी संस्थागत निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे देश के बड़े करदाताओं को जल्द ही पूरी तरह से स्वचालित टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस की सुविधा मिल सकती है। सरकार ने अपने टैक्स पोर्टलों की एपीआई पहुंच को तीसरे पक्ष के लिए खोल दिया है। इससे एआई-आधारित ऑटोमेटेड उपकरणों के लिए राह खुलेगी।

निरमा समूह अब होटल बिजनेस में भी उतरेगा

अहमदाबाद | डिटर्जेंट, साबुन, सीमेंट, एजुकेशन और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में कारोबार करने वाला निरमा समूह अब होटल सेक्टर में भी प्रवेश करने जा रहा है। 12,207 करोड़ रुपए का ये ग्रुप एक 555 कमरों वाला फाइव स्टार होटल खोलने की योजना बना रहा है। समूह ने गांधीनगर में होटल बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरियों के लिए आवेदन किया है।

नायकाः कमाई 25% तक बढ़ने की उम्मीद

मुंबई | ब्यूटी प्लेटफॉर्म नायका को चालू वित्त वर्ष की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में अपने राजस्व में करीब 25% तक बढ़ोतरी दर्ज होने की उम्मीद है। नायका की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि जीएमवी (कुल बिक्री मूल्य) और एनएसवी (शुद्ध बिक्री मूल्य) में भी करीब 28% से ज्यादा की बढ़त होने की उम्मीद है।

निवेश • शेयर बाजार में हर 10 में से 4 निवेशक अब जेन जी, 2019 तक 2 ही थे

म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले 32% नए निवेशक 30 से कम के

भास्कर न्यूज | मुंबई

ट्रेंड: 81% युवा निवेशक छोटे शहरों से, आधे से ज्यादा फैसले खुद कर रहे

55 से 61 फीसदी म्यूचुअल फंड निवेश डायरेक्ट प्लान के माध्यम से हो रहे हैं, जिसमें निवेशक स्कीम के फैसले खुद करते हैं।

57 से 90 फीसदी जेन जी एसआईपी के जरिये निवेश पसंद करते हैं, जिसमें छोटी-छोटी रकम निवेश करने की सुविधा होती है।

81% युवा निवेशक बीते साल टॉप-30 शहरों से आए। जोधपुर, रायपुर, पटना और जबलपुर देश के इसी श्रेणी के शहर हैं।

देश की नई पीढ़ी खर्च में समझदारी दिखाते हुए बचत कर रही है और पैसे बढ़ाने के स्मार्ट तरीके अपना रही है। अब एक तिहाई नए निवेशक जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवा हैं। ये निवेश की पुरानी शैली (जैसे बैंक एफडी) बदल रहे हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म्स की मदद से खुद निर्णय ले रहे हैं और एसआईपी के जरिये शेयरों में पैसे लगाकर बड़ा फंड तैयार करने में जुटे हैं।

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (कैम्स) के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 4 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशकों में से लगभग 82 लाख यानी 21% अब जेन जी के हैं। 2025 में अक्टूबर तक 32% नए निवेशक जेन जी से आए। सीधे शेयरों में भी इनका निवेश बढ़ रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में 30 साल से कम उम्र के निवेशक अब 38% हो गए हैं, जो मार्च 2019 तक 22.6% थे। यानी शेयर बाजार में अब हर 10 में से 4 निवेशक जेन जी हैं, पहले 2 थे।

युवा शक्तिः शेयर बाजार में अब 38% निवेशक जेन जी, फंड्स में भी 82 लाख

कुल म्यूचुअल फंड निवेशक	3.92 करोड़
जेन जी निवेशक	81.8 लाख
जेन जी की हिस्सेदारी	21%
2025 में नए निवेशकों में जेन जी	32%
एनएसई में 30 से कम उम्र के निवेशक	38%

(2025 के आंकड़े अक्टूबर तक, स्रोत: कैम्स, एनएसई)

असरः युवा निवेशकों का मिला सपोर्ट, फिनटेक कंपनियां तेजी से उभरने लगीं

म्यूचुअल फंड्स के संगठन एम्फी के मुताबिक, बैंक और बड़े वितरक अब भी सबसे ज्यादा एसेट्स मैनेज करते हैं। लेकिन, युवा निवेशकों की पसंद के चलते नई एसआईपी रजिस्ट्रेशन और निवेश में फिनटेक कंपनियां आगे हैं। अक्टूबर 2025 में टॉप-21 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 8 और टॉप-50 में से 14 फिनटेक थे।

बेचैनीः निवेश के तरीके दे रहे संकेत, युवाओं में बढ़ रही पैसे बढ़ाने की भूख

इक्विटी फंड पहली पसंदः फोनपे वेल्थ के मुताबिक, जेन जी शेयरों से जुड़े निवेश पसंद करते हैं। करीब 95% जेन जी इक्विटी फंड से निवेश यात्रा शुरू करते हैं। ज्यादा रिटर्न के लिए वे ज्यादा रिस्क लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे।

बाजार में जल्द प्रवेशः पेटीएम मनी के एमडी और सीईओ संदीप भारद्वाज कहते हैं कि जेन जी शेयर बाजार में पिछली पीढ़ियों से जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। उनमें पैसे बढ़ाने की बड़ी भूख है। इसीलिए शेयर और म्यूचुअल फंड अब जटिल नहीं लगते। ये निवेश के स्वाभाविक विकल्प बन गए हैं।

25% एसआईपी जेन जी सेः कैम्स के आंकड़ों के मुताबिक, बीते साल एक-चौथाई (25%) नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन जेन जी से आया। ये दिखाता है कि युवाओं के बीच लंबी अवधि में नियमित निवेश से बड़ा फंड जुटाने की सोच आम हो रही है।

2025 • तीन नई वाहन कंपनियां 1 लाख करोड़ क्लब में शामिल

देश में एक लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली कंपनियां 97 से बढ़कर 111 हुईं

फाइनेंस की सर्वाधिक 12 कंपनियां 1 लाख करोड़ी

सुंदर सेतुरामन | मुंबई

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद 2025 बड़ी कंपनियों के लिए शानदार रहा। बीते साल देश में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां 97 से 14% बढ़कर 111 हो गईं। इसकी बड़ी वजह रिकॉर्ड पैमाने पर आईपीओ आना और अधिकांश की शानदार लिस्टिंग रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज 21 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। 15 लाख करोड़ के साथ एचडीएफसी बैंक दूसरे और 12 लाख करोड़ के साथ भारती एयरटेल तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। एक लाख करोड़ के क्लब में शामिल सेक्टर भी 36 से बढ़कर अब 40 हो गए। इसमें फाइनेंस सेक्टर की सबसे ज्यादा 12 कंपनियां शामिल हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की 3 नई कंपनियां भी इसमें जुड़ी हैं। इन्हें जीएसटी में कटौती का सीधा फायदा मिला है। इसके चलते इनकी बिक्री, आय और मुनाफा बढ़ा। इससे शेयरों में तेजी आई और मार्केट कैप बढ़ा।

असामान्यः टाटा कैपिटल, एलजी समेत 3 की सीधी एंट्री

2025 में तीन नई लिस्टेड कंपनियों ने सीधे 1 लाख करोड़ के क्लब में जगह बनाई। इनमें टाटा कैपिटल, आईसीआईसीआई एएमसी और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। अन्य कंपनियां तो पहले से लिस्टेड थीं। इक्विनॉमिक्स के संस्थापक जी. चोकालिंगम के मुताबिक, नई कंपनियों का इतनी जल्दी इस क्लब में शामिल होना असामान्य है। पिछले दो साल में आईपीओ बाजार की तेजी ने बहुराष्ट्रीय और बड़े औद्योगिक घरानों को आकर्षित किया है। इसके अलावा बीएसई, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान जिंक ने भी शानदार वापसी की है।

रणनीतिः अब छोटे शेयरों में खरीदारी का बड़ा मौका

स्वतंत्र बाजार विशेषज्ञ अंबरीश बालिगा के मुताबिक बड़ी कंपनियां और बड़ी होती गईं, जबकि छोटी कंपनियों को नजरअंदाज किया गया। म्यूचुअल फंड्स के पास एसआईपी के जरिये काफी पैसा आया, जिसे उन्होंने टॉप-300 कंपनियों में निवेश किया। इससे स्मॉल और मिड-कैप शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा। अब निवेशकों का ध्यान फिर से छोटे शेयरों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इन शेयरों में 30-70% तक गिरावट आ चुकी है, जिससे निचले स्तरों पर खरीदारी की संभावना बन रही है।

कमजोरीः आईटी, स्टील सेक्टर की चमक फीकी

आईटी, फार्मा और पावर जनरेशन सेक्टर की 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनियों की संख्या में बीते साल कमाई आई। इसके कई कारण रहे, मसलन डॉलर में आईटी सेक्टर की आय महज 2-4% बढ़ी। इसके साथ ही चीन और रूस के कारण अमेरिका से छिड़े टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर स्टील इंडस्ट्री पर पड़ा है। इन वजहों से टीसीएस, इंफोसिस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और सन फार्मा जैसी दिग्गज कंपनियों के मार्केट कैप में कमी आई है। हालांकि ये सभी अब भी टॉप कंपनियों के क्लब में हैं।

इक्विटी • सबसे प्रभावशाली शेयर एचडीएफसी 2.4% टूटा

आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बीच सेंसेक्स 322 अंक गिरा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारतीय शेयर बाजारों में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही नतीजों के पूर्वानुमानों का बड़ा असर दिखाई दिया। सोमवार को सेंसेक्स 322.39 अंक या 0.38% गिरकर 85,439.62 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 78.25 अंक या 0.30% गिरकर 26,250.30 पर बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले एचडीएफसी बैंक के दिसंबर तिमाही के कारोबार अपडेट के बाद उसके शेयरों में 2.4% की गिरावट आई। अमेरिका से कमाई का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाले आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने मिली। एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस में 2.2% से ज्यादा, टीसीएस और टेक महिंद्रा में 1% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। एफएमसीजी शेयरों में अधिकतर तेजी दिखी।

इस साल 15% तेजी की उम्मीदः मोबियस

उभरते बाजारों में 'निवेश का इंडियाना जोन्स' कहे जाने वाले मार्क मोबियस, इस साल भारत को लेकर काफी आशान्वित हैं। पोर्टफोलियो का करीब 30% हिस्सा भारत में रखने वाले मोबियस को इस साल भारतीय शेयर बाजारों में 12-15% की वृद्धि की उम्मीद है। उनके मुताबिक आर्थिक सुधारों और सोर्सिंग में बदलाव के कारण भारत चीन से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच सावधानी बरतने की सलाह है।

तिमाही आय से तय होगा रुझानः एक्सपर्ट

वैश्विक स्तर पर, निवेशक प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेड के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ जापान ने अपने सख्त रुख की पुष्टि की है। आगे देखें तो, तीसरी तिमाही की आय पर विशेष ध्यान रहेगा और यह निकट भविष्य के बाजार रुझानों को निर्देशित करेगा।'

- विनोद नायर, रिसर्च हेड, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स

संयुक्त उद्यम • एथेन शिपिंग में कदम

ओएनजीसी जापान की कंपनी मित्सुई में 50% हिस्सा खरीदेगी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

भारत की सरकारी तेल-गैस कंपनी ओएनजीसी जापान की मित्सुई ओएसके लाइंस (एमओएल) में 50% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस नए संयुक्त उद्यम के तहत दोनों कंपनियां एथेन ले जाने वाले बड़े जहाजों का संचालन करेंगी। ये जहाज अमेरिका से एथेन लाकर ओएनजीसी की पेट्रोकेमिकल इकाई ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे। साझेदारी के अनुसार गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में दो संयुक्त उद्यम कंपनियां, भारत एथेन वन आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड और भारत एथेन टू आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड बनाई जाएंगी। ओएनजीसी दोनों कंपनियों में 100 रुपए प्रति शेयर के 2,00,000 इक्विटी शेयर खरीदेगी। इससे उसे प्रत्येक कंपनी में 50% हिस्सेदारी मिलेगी। बाकी हिस्सेदारी मित्सुई के पास रहेगी।

इस साझेदारी से ओएनजीसी की ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स मजबूत होगी। यह पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम ओएनजीसी के वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क को बढ़ाएगा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।

नीति • महंगाई का लक्ष्य 2021 से समान

आरबीआई के लिए 4% महंगाई का लक्ष्य कायम रहने के आसार

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आरबीआई के लिए तय 4% महंगाई लक्ष्य को फिलहाल बदले जाने की संभावना नहीं है। सरकार और आरबीआई इसे 2% से 6% की तय सीमा के साथ ही जारी रख सकते हैं। यह जानकारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दी गई है। मौजूदा महंगाई लक्ष्य व्यवस्था 2016 से लागू है और इसे आखिरी बार 2021 में नवीनीकृत किया गया था। आरबीआई का लक्ष्य हर पांच साल में निर्धारित किया जाता है और मार्च में इसे जारी करना होता है। अगली समीक्षा मार्च 2026 में होनी है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक बाजार और नीति विशेषज्ञ मौजूदा ढांचे से संतुष्ट हैं। ऐसे में आरबीआई और सरकार स्थिरता बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए इसी लक्ष्य को जारी रख सकते हैं।

पिछले एक दशक में, महंगाई लगभग तीन-चौथाई (75%) समय तक निर्धारित सीमा के भीतर रही है, हालांकि कोविड महामारी के दौरान हालात बिगड़ने से महंगाई में तेज उतार-चढ़ाव देखने मिला। भारत की खुदरा महंगाई नवंबर 2025 (0.71%) में पिछले महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर (अक्टूबर-0.25%) से बढ़ी, लेकिन लगातार तीसरे महीने केंद्रीय बैंक के लक्ष्य सीमा से नीचे रही।

बदलाव • टाटा संस प्रदर्शन से नाखुश

कैम्पबेल विल्सन की जगह एअर इंडिया के नए सीईओ की तलाश

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एअर इंडिया का बोर्ड कैंपबेल विल्सन की जगह लेने के लिए एक नए सीईओ की तलाश कर रहा है। जून 2025 में हुए विमान हादसे में 260 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा संबंधी चूक को लेकर एयरलाइन की गहन जांच जारी है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक टाटा संस और बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी कैम्पबेल से नाखुश हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने संभावित उम्मीदवारों के रूप में दो प्रमुख ब्रिटेन और अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के सीईओ से संपर्क किया है। चंद्रशेखरन कैम्पबेल के जमीनी स्तर पर कार्यों और सुधारों की धीमी गति से असंतुष्ट हैं। चंद्रशेखरन ने पिछले कुछ महीनों में नियमित रूप से विल्सन के प्रदर्शन की समीक्षा की है। सिंगापुर एयरलाइंस में 26 साल के करियर के बाद विल्सन ने जुलाई 2022 में एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में पदभार संभाला था।

विल्सन का कार्यकाल जून 2027 में समाप्त होगा, लेकिन उन्हें पहले हटाया जा सकता है। कम लागत वाली एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस में भी इसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है। वर्तमान सीईओ आलोक सिंह का कार्यकाल भी 2027 में समाप्त होगा। उन्हें भी समय से पहले हटाने की अटकलें हैं।

क्रिप्टो • गिरावट के बाद 50 दिन का औसत पार

बिटकॉइन तीन हफ्ते के उच्च स्तर पर, इस साल 6% चढ़ा

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

बिटकॉइन की कीमत सोमवार को 2.3% बढ़कर तीन हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ये 93,000 डॉलर (83.7 लाख रु.) के नीचे ट्रेड करती रही। विश्लेषकों का कहना है कि अक्टूबर मार्केट क्रैश से शुरू हुई गिरावट के बाद बिटकॉइन ने पहली बार 50-दिन के औसत को पार किया है। इसे बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। 2026 में बिटकॉइन अब तक करीब 6% चढ़ चुका है। इससे संकेत मिल रहा है कि बाजार में स्थिरता लौट रही है। बिटकॉइन पिछले कई हफ्तों से एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान शेयर बाजार में आई तेजी का फायदा

फिलहाल बिटकॉइन में सुधार के संकेत

पिछले साल की चौथी तिमाही में बिटकॉइन की कीमत में करीब 24% की गिरावट आई थी, लेकिन मौजूदा तेजी से इसमें दोबारा सुधार के संकेत मिल रहे हैं। निवेशकों की नजर 94,000 डॉलर (84 लाख रुपए) के स्तर पर है, जबकि 88,000 डॉलर (79 लाख रुपए) को मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है।

इसे नहीं मिला और 2025 के अंत तक इसमें 6.5% की गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिका में लागू की गई उद्योग-अनुकूल नीतियों के बावजूद पिछले साल प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा।

पीआरबी की पहली बैठक में भुगतान साधनों पर चर्चा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड (पीआरबी) की पहली बैठक में घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणालियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) के कार्यों की समीक्षा की गई और ड्राफ्ट पेमेंट्स विजन 2028 प्रस्तुत किया गया। इस विजन पर सदस्यों ने रणनीतिक सुझाव दिए। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नागराजू मद्दीराला, आईएएस (सेवानिवृत्त) अरुणा सुंदरराजन, उपराज्यपाल टी. रबी शंकर और कार्यकारी निदेशक विवेक दीप उपस्थित थे। बोर्ड को हाल ही में किए गए डिजिटल पेमेंट्स सर्वे के प्रमुख निष्कर्षों की भी जानकारी दी गई।

तैरता शीश महलः 2 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी गीगायाट, रफ्तार 93 किमी प्रति घंटा

न्यूयॉर्क | यह तस्वीर करीब 500 फुट लंबी एक विशाल गीगायाट की है। यह दो फुटबॉल मैदानों जितनी बड़ी है, फिर भी पूरी तरह तैयार होने पर 50 नॉट्स (93 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार से समुद्र को चीरती हुई दौड़ेगी। इसका कांसेप्ट मॉडल अमेरिकी डिजाइनर गैरी ग्रांट ने तैयार किया है। इसका ढांचा पैनोरमिक ग्लास का बना है, जिसकी लंबी एरोडायनामिक सतहें शानदार कांच से लिपटी हुई हैं। यह पारंपरिक याट से अलग, आधुनिक क्लिफ-टॉप विला जैसी दिखती है।

• अंदर मुख्य सलून में फ्लोर-टू-सीलिंग ग्लास और 5.2 मीटर ऊंची छत है, जो इसे डबल-हाइट लॉफ्ट जैसा बनाती है।
• आम याट के 2.3 मीटर हेडरूम के मुकाबले दोगुना। इसके आउटडोर में कन्वर्टिबल बीच क्लब जैसी अन्य खूबियां भी हैं।

रिपोर्ट • एसएंडपी 'ग्लोबल बैंक्स आउटलुक 2026'

चुनौतीपूर्ण हालात में भी भारत के बैंकों का भविष्य उज्ज्वल

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की 'ग्लोबल बैंक्स आउटलुक 2026' रिपोर्ट के अनुसार, भले ही 2026 तक भू-राजनीतिक तनावों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, लेकिन वैश्विक बैंकों का भविष्य स्थिर बना हुआ है। एसएंडपी ग्लोबल ने चार प्रमुख बाधाओं की पहचान की है जो बैंकिंग प्रणाली को बाधित कर सकती हैं। इनमें भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि, अमेरिकी व्यापार नीतियों की अनिश्चितता, नियामकीय बदलाव के अलावा जेनरेटिव एआई-साइबर जोखिम और जलवायु परिवर्तन जैसी बातें शामिल हैं जो बैंकों के बीच 'क्रेडिट असमानता' पैदा कर रही हैं। हालांकि बैंक की रिपोर्ट में कहा गया

बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार आगे भी जारी रहेगा

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत के बेहतर एसेट क्वालिटी रेश्यो अनुपात बने रहेंगे, और एनपीएल (नॉन परफॉर्मिंग लोन) अनुपात ऐतिहासिक मानकों के मुकाबले कम और प्रबंधनीय रहेगा। इसके अलावा, जीडीपी वृद्धि के मामले में भारत एक क्षेत्रीय अग्रणी देश के रूप में उभरा है।

है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में समग्र मंदी के बावजूद, भारत एक उज्ज्वल पक्ष के रूप में उभरा है। एसएंडपी का कहना है कि अगस्त 2025 में भारत का आर्थिक जोखिम स्कोर '6' से मजबूत होकर '5' हो गया है।

बिज़नेस एंकर नई तकनीक, हुनर और विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में भारतीयों की मजबूत मौजूदगी

जर्मनी में भारतीय प्रोफेशनल हर माह औसतन 5.7 लाख रु. कमा रहे; ये अन्य विदेशियों से 68% और जर्मन पेशेवरों से 29% ज्यादा

सुरभि ग्लोरिया सिंह | नई दिल्ली

जर्मनी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारी अन्य विदेशी कर्मचारियों के साथ ही जर्मनी के स्थानीय कामगारों से भी ज्यादा कमाते हैं। भारतीय पेशेवरों की यह ज्यादा कमाई उनकी तकनीकी शिक्षा, उच्च कौशल और विज्ञान आधारित क्षेत्रों में मजबूत मौजूदगी का नतीजा है। जर्मन अखबार हैंडेल्सब्लाट में जर्मन अर्थव्यवस्था संस्थान (आईडब्ल्यू) की रिसर्च के हवाले से यह रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में भारतीय कर्मचारियों का 2024 में मीडियन ग्रॉस मासिक वेतन करीब 5.69 लाख रुपए (5393 यूरो) रहा, जबकि जर्मन कामगारों का औसत मासिक वेतन 4.40 लाख रुपए (4177 यूरो) के करीब रहा। वहीं सभी विदेशी कर्मचारियों की औसत आय करीब 3.38 लाख रुपए (3,204 यूरो) दर्ज की गई। यानी भारतीयों की मासिक कमाई विदेशी कामगारों की तुलना में 68.34% ज्यादा है वहीं स्थानीय जर्मन कामगारों से भी करीब 29.32% ज्यादा है।

जर्मन विश्वविद्यालयों में इस समय 43,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे

जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जर्मनी के संघीय सांख्यिकी कार्यालय (फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस) के अनुसार, लगभग 43,000 भारतीय छात्र जर्मन विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्र वहीं रहकर रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं। साल 2000 से 2022 के बीच भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और पेशेवरों द्वारा दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या 12 गुना बढ़ चुकी है, जो उनके नवाचार में योगदान को दिखाता है।

भारतीयों के बाद कमाई के मामले में ऑस्ट्रिया (5.61 लाख रु.), अमेरिका (5.59 लाख रु.) और आयरलैंड (5.51 लाख रु.) के कामगार आते हैं। जर्मनी में गणित, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रकृति विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 2012 के बाद करीब 9 गुना बढ़कर 32,800 से ज्यादा हो चुकी है। जर्मनी के एक तिहाई भारतीय फुल-टाइम कर्मचारी 25 से 44 वर्ष की उम्र के हैं।

जर्मनी में मासिक आय के मामले में भारतीयों के बाद ऑस्ट्रिया के लोग

कामगार	औसत मासिक आय
भारतीय	5.69
ऑस्ट्रिया	5.61
अमेरिका	5.59
आयरलैंड	5.51
जर्मनी	4.40
अन्य विदेशी कामगार	3.38

(आंकड़े लाख रु. में, स्रोत- फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जर्मनी)

इन्वेंट्री • कंपनियों के सामने पुराना स्टॉक खपाने की चुनौती

गर्म कपड़ों की बिक्री कम, स्टॉक ज्यादा, लिवाइस-एचएंडएम पर 50% तक छूट

अक्षरा श्रीवास्तव | नई दिल्ली

इस साल गर्म कपड़ों की बिक्री उम्मीद से काफी कम रही। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बावजूद ऊनी कपड़ों की मांग नहीं बढ़ी। इससे कंपनियों पर स्टॉक का बोझ बढ़ गया। नतीजतन, एचएंडएम, यूनिक्लो, लिवाइस और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे बड़े फैशन ब्रांड्स को 50% तक डिस्काउंट पर माल खपाना पड़ रहा है। इन्हें ईयर-एंड सेल भी दो हफ्ते पहले, यानी 15 दिसंबर से ही शुरू करनी पड़ी। आमतौर पर यह सेल क्रिसमस या नए साल के आसपास शुरू होती है, लेकिन इस बार ब्लैक फ्राइडे के तुरंत बाद से ही भारी छूट देनी पड़ी। अब कंपनियों के सामने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की सेल और नए कलेक्शन से पहले पुराने स्टॉक को क्लियर करने की बड़ी चुनौती है। सप्लाई चेन का संतुलन बनाए रखने के लिए कंपनियों को डिस्काउंट देकर कम से कम 50% विंटर स्टॉक बेचना होता है। जनवरी में ब्रांड्स अपना 'स्प्रिंग-समर कलेक्शन' लॉन्च करते हैं। स्टोर्स में पुराने स्टॉक के रहते नई रेंज के लिए जगह बनाना मुश्किल होता है। इसी दबाव के कारण 50% तक डिस्काउंट के साथ सेल जल्दी शुरू की गई, ताकि नए सीजन की शुरुआत बेहतर हो सके।

जीएसटीः कटौती का नहीं दिखा उम्मीद मुताबिक असर

पिछले साल कपड़ों पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) की दरों में बदलाव किया गया था। 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर टैक्स में 6% की कमी आई, जबकि इससे महंगे कपड़ों पर यह 12% से बढ़कर 18% हो गया। कंपनियों को उम्मीद थी कि इस बदलाव से मध्यम वर्ग की खरीदारी बढ़ेगी, लेकिन बाजार में इसका कोई खास असर नहीं दिखा और गर्म कपड़ों की मांग दिसंबर के आखिर तक कमजोर बनी रही।

नई दिल्ली, मंगलवार
6 जनवरी 2026

हरिभूमि

सहेली

आज हर कोई प्रोग्रेसिव कहलाना चाहता है, यह भी चाहता है कि वह पॉजिटिव पर्सनालिटी पाए। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अपनी खूबियों के साथ अपनी सीमाओं को भी समझें। ऐसा व्यवहार न करें, जिससे लोग हर्ट फील करें। आप अपने सधे व्यक्तित्व के साथ अपना व्यवहार, अपनी भाषा शालीन रखें। सोच पॉजिटिव रखें। अपनी अट्रैक्टिव-प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी के लिए आप और कौन से गुण अपनाएं, जानिए।

ऐसे बनेगी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव-प्रोग्रेसिव

कवर स्टोरी

डॉ. मोनिका शर्मा

इस नए दौर में प्रोग्रेसिव होने का अर्थ मन की करने और कुछ अलग तरह के खुलेपन को जीने के अंदाज से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में कई बार प्रगतिशीलता संग अहंकार का भाव भी जुड़ जाता है, जिससे मन ही नहीं, जीवन भी कई उलझनों में घिर जाता है। यही वजह है कि पर्सनल स्पेस को मनचाहे ढंग से जीने और प्रोग्रेसिव होने की राह में कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। आज के दौर में महिलाओं को सजग-सशक्त व्यक्तित्व बनाने की राह पकड़ने के मोर्चे पर भी सोच-समझकर डटना होता है। यह समझ, सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बचाती है, दिशाहीन भी नहीं होने देती। अभिमान के घेरे में लाने के बजाय मानवीय अनुभूतियों से जोड़े रखती है। महिलाओं को समझना होगा कि यह संतुलन ही सही मायने में स्वतंत्र और प्रभावी अस्तित्व गढ़ने जैसा है। प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी के लिए हर आयुवर्ग की महिलाएं कुछ बातें जरूर अमल में लाएं-

भाषा की सभ्यता ना भूलें

चिंतनीय है कि प्रोग्रेसिव होने के नाम पर अब बहुत से लोग भाषाई मर्यादा को भूल जाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हुए अजब-गजब भाषा बोलने लगते हैं। उपहास उड़ाने वाले अपमानजनक शब्द घर-परिवार में भी बोले-सुने जा रहे हैं। तकलीफदेह है कि रील वीडियो से लेकर आम जिंदगी तक महिलाएं भी अभद्र शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। असभ्य शब्दों का यह घेरा मॉडर्न ट्रेंड या प्रोग्रेसिव होने के नाम पर कस रहा है। जिसके चलते पॉजिटिव सोच और सधे व्यक्तित्व के मायने ही गुम हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव होने के नाम पर असभ्य भाषा बोलने से बचें। प्रगतिशील बनने के लिए नकारात्मक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। न ही किसी का अपमान या उपहास करने की। अच्छे और सधे शब्दों में भी विरोध जताया जा सकता है। किसी बात की शिकायत की जा सकती है। हंसी-मजाक करने के लिए भी असभ्य भाषा की जरूरत नहीं होती। न ही अपना रुतबा दिखाने के लिए नकारात्मक भाषा बोलना जरूरी है। अपने शब्दों को लेकर सजग रहना, इंप्रेसिव पर्सनालिटी का सबसे अहम पहलू है। इसीलिए भाषा की सभ्यता कभी ना भूलें।

जुड़ाव और बंधन का फर्क समझें

हर परंपरागत चीज बंधन नहीं है। कामयाबी की खुशी अपनों के साथ और बढ़ जाती है। हर मामले में ही बड़ों की समझाइशें पुरानी सोच नहीं होती हैं। अभिभावकों की सहज रोक-टोक जीवन की जद्दोजहद के प्रति सजग करने वाला स्नेह भी माना जा सकता है। मौजूदा दौर में हर जुड़ाव को बंधन मानने की सोच बढ़ रही है। छोटी-छोटी बातों के प्रति भी स्वीकार्यता नहीं दिखती। तकलीफदेह है कि यह बर्ताव बहुत-सी गलतियां करने के रास्ते खोलने वाला साबित होता है। यह न भूलें कि अपनों के साथ सधा-सा गठजोड़ खुद आपके ही जीवन को सही दिशा देता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। अनुभवी अपनों का मार्गदर्शन सही निर्णय ले पाने की बुनियाद बनाता है।

विश्वास हो, अंधविश्वास नहीं

यह हैरान ही नहीं बेहद परेशान करने वाली बात है कि आज सजग-शिक्षित युवतियां आपराधिक मामलों में ज्यादा फंस रही हैं। कहीं अपने अतिवादी बर्ताव के कारण खुद अपराध की राह पकड़ रही हैं तो कहीं अंधे विश्वास के कारण दूसरों के बिछाएं जाल में फंस रही हैं। ऐसे में दूसरों पर आंख मूंद कर यकीन करने को सही मायने में प्रगतिशील होना तो नहीं कहा जा सकता। आधुनिकता के नाम पर बिना जाने-समझे लिव इन रिश्तों में ऐतबार कर जान गंवाने वाली युवतियां हों

या वैवाहिक जीवन को सही ढंग से जाने, जिए बिना खारिज कर देने वाली बेटियां। न तो अपनी पूर्वाग्रह भरी सोच पर विश्वास करना सही होता है, ना ही बिना दायित्वबोध वाले रिश्तों को जीना। इस बात को हम समझें कि आपसी विश्वास के बिना परिवार और समाज नहीं चल सकता। परिचितों-अपरिचितों का अनकहा-सा भरोसा ही तो पूरे परिवेश को जोड़ता है।

बनाएं पॉजिटिव पर्सनालिटी

आप चाहती हैं कि पॉजिटिव पर्सनालिटी पाएं तो इसके लिए अपनी खूबियों के साथ अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। विचार हों या व्यवहार, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना आपको मजबूत नहीं बनाता। दूसरों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति का आपके

आत्मविश्वास से कोई लेना-देना नहीं होता। देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया कंटेंट से लेकर सड़क तक बहुत सी महिलाएं, घमंड को ही कॉन्फिडेंस समझ रही हैं। बहुत सी युवतियों में दूसरों के विचारों का सम्मान करने की सोच से दूरी बढ़ रही है। 'मैं ही सही हूं' की सोच स्त्री-पुरुष किसी के लिए सही नहीं कही जा सकती। पॉजिटिव पर्सनालिटी के बहुत से अच्छे गुणों में फ्लेक्सिबिलिटी और एडॉप्टिबिलिटी दोनों ही अहम और जरूरी गुण हैं। दिनचर्या में सहज स्वीकार्यता और समझ भरे व्यवहार से जुड़ी ऐसी बातें, आपकी भावनाएं भी बदलने लगती हैं। मन और जीवन दोनों पॉजिटिव बनने लगते हैं।

जब ऑफिस में बढ़ने लगे स्ट्रेस

कॉरपोरेट ऑफिसेस में वर्क लोड इतना बढ़ चुका है कि महिलाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। बढ़े हुए वर्क लोड की वजह से वे मेंटल स्ट्रेस में रहती हैं, इसका असर इनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इससे वर्किंग वूमेन कैसे बचें, बहुत जरूरी सलाह।

वर्किंग वूमेन

निकिता चौहान

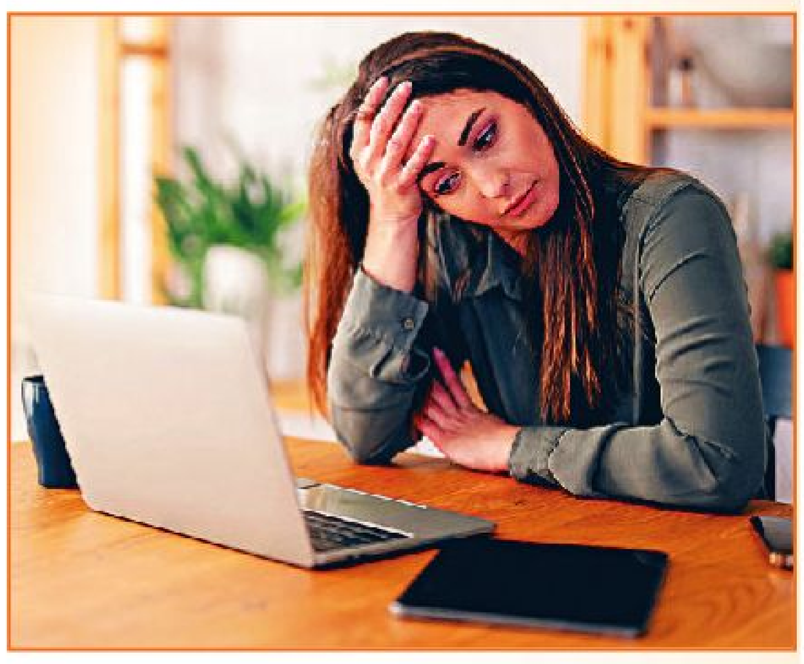

आज कॉरपोरेट सेक्टर में वर्कलोड इतना अधिक बढ़ चुका है कि इसका असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ने लगा है। ऑफिस स्ट्रेस से न सिर्फ प्रोडक्टिविटी कम होती है, मेंटल हेल्थ के साथ रिश्तों पर भी नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है, जितना ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी निभाना। आप कुछ सरल आदतें अपनाकर अपना स्ट्रेस नियंत्रित कर सकती हैं।

हेल्दी रुटीन बनाएं

दिन की शुरुआत रोजाना तय समय पर करें और एक बैलेंस रुटीन अपनाएं। नियमित समय पर उठना, निश्चित समय पर खाना और सोना शरीर और मन दोनों को स्थिरता देता है। इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होता है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

डिहाइड्रेशन शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी बढ़ाता है। ऑफिस में काम करते हुए हर एक-डेढ़ घंटे में पानी पीने की आदत डालें। यह स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है।

अच्छा स्लीप रूटीन अपनाएं

सात-आठ घंटे की नींद मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, कैफीन से बचें और शांत वातावरण में सोएं। अच्छी नींद तनाव को काफी कम करती है।

डीप ब्रीदिंग-माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें

पांच से दस मिनट की गहरी सांस लेने की तकनीक या माइंडफुलनेस एक्सरसाइज तुरंत तनाव कम करती है, इससे दिमाग शांत रहता है। ऑफिस के बीच में भी दो मिनट का 'ब्रीदिंग ब्रेक' काफी असरदार होती है।

हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अपनाएं

स्ट्रेस के समय ओवरईटिंग, गुस्सा या सोशल मीडिया में डूबे रहना स्थिति को और खराब करता है। इसकी जगह छोटे ब्रेक लें, वॉक करें, पसंदीदा संगीत सुनें या किसी आत्मीय और भरोसेमंद सहकर्मी से अपने मन की बात करें।

फेवरेट एक्टिविटी करें

सिर्फ काम से मानसिक थकान बढ़ती है। वीकेंड पर या काम के बाद अपनी पसंद की गतिविधियां जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, रीडिंग या परिवार के साथ समय बिताना, मन को रिफ्रेश करती हैं और बर्नआउट से बचाती हैं।

वर्क-डे में छोटे ब्रेक लें

लगातार कई घंटों तक काम करने से दिमाग थक जाता है, प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। हर साठ से नब्बे मिनट में दो-तीन मिनट का छोटा ब्रेक लें, खड़े होकर स्ट्रेच करें, थोड़ा चलें या गहरी सांस लें। यह माइक्रो-ब्रेक्स मानसिक ऊर्जा को री-सेट करते हैं, आपके मानसिक तनाव के प्रभाव को भी काफी कम करते हैं।

(फोर्टिस हेल्थकेयर, दिल्ली के साइकिएट्रिस्ट डॉ. आस्तिक जोशी से बातचीत पर आधारित)

एक्सपर्ट से करें कंसल्ट

स्ट्रेस मैनेजमेंट एक स्किल है, जिसे निरंतर अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। यदि ऑफिस स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित कर रहा है तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें। काम के साथ-साथ अपने मन का भी ध्यान रखना आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में सफलता और बेहतर जीवन का मूल मंत्र है।

पौधों को पानी की जरूरत हर मौसम में होती है। लेकिन इसकी मात्रा तापमान और धूप की अवधि पर निर्भर करती है। जरूरत से कम या ज्यादा पानी देने पर पौधे मुरझा सकते हैं। सर्दी के मौसम में कैसे-कितना पानी दें, यहां बता रहे हैं।

सर्दियों में पौधों को कब-कितना पानी दें

गार्डनिंग

अनु

सर्दी के मौसम में पौधों की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। दरअसल, सर्दी के दिनों में गर्मी या बरसात की तुलना में पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। तापमान और धूप कम होने की वजह से पौधों को पानी की भी कम जरूरत महसूस होती है। उन्हें अगर दिन में एक बार पानी दे दिया जाए, तो उनकी मिट्टी में नमी बनी रहती है। अगर इनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए या इन्हें कई दिन तक बिना पानी के रखा जाए, तो पौधे सूखने लगते हैं, सूखकर मुरझा सकते हैं और कई बार पौधे नष्ट भी हो सकते हैं। दरअसल, ठंड के दिनों में बालकनी या शेड में रखे पौधों को कम धूप मिलती है। कम धूप के कारण उन्हें कम पानी की जरूरत होती है।

होती है कम पानी की जरूरत: जब पौधों को प्रकाश मिलने की अवधि कम हो जाती है, तो पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण के अलावा दूसरी जैविक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। सर्दियों में दिन का छोटा होना, कम रोशनी और ठंडे तापमान के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है और घर के भीतर रखे पौधे पानी ज्यादा नहीं सोखते हैं। उनकी क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। अगर ठंड ज्यादा हो रही है तो उनको पानी देने का तरीका भी उसी के अनुकूल होना चाहिए।

वातावरण का रखें ध्यान: गार्डन एक्सपर्ट्स के अनुसार जहां हम रहते हैं, वहां की जलवायु, मौसम, वहां आने वाली धूप, तापमान और आर्द्रता के आधार पर ही यह निर्धारित होता है कि पौधों को इस सीजन में कितनी बार और कितना पानी देना चाहिए? ज्यादा प्राकृतिक नमी और ठंडे तापमान वाले वातावरण में पौधों को कम पानी देना चाहिए। लेकिन जो लोग ज्यादा ठंड के दिनों में अपने घर के भीतर हीटर चलाते हैं, उनके पौधों के पानी की जरूरत शुष्क वातावरण के कारण अलग तरह की होती है। इस तरह हर पौधे की जरूरत अलग-अलग तरह की होती है और उनकी पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर ही उन्हें पानी देने की भी जरूरत होती है। भले ही सर्दियों के मौसम में पौधे सुप्त अवस्था में होते हैं, इसके बावजूद उन्हें अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए पानी की जरूरत तो होती ही है। पानी की बदौलत ही पौधे जीवित रहते हैं लेकिन ज्यादा पानी देने से वो नष्ट होने लगते हैं। इसलिए अगर आपके गार्डन में लगे पौधे की पत्तियां भूरे रंग की हो गई हों या उनकी पत्तियां झड़ गई हों तो भी थोड़ी मात्रा में उन्हें पानी चाहिए होता है। उन्हें हाइड्रेट रखने से वो पौधे आने वाले दिनों में बचे रहेंगे।

इन बातों का रखें ध्यान: सर्दी के दिनों में अपने पौधों को पानी देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें।

- जब ज्यादा ठंड हो यानी जब तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाए, तो पौधों को अधिक पानी न दें।
- जहां तक संभव हो सुबह के समय पानी दें ताकि पौधों को पानी को अवशोषित करने और रात्रि के समय ठंड से बचने का सुरक्षा कवच मिल सके।
- सर्दी के मौसम में पौधों को रात के समय कभी पानी न दें। इससे पानी जड़ों में जमा हो जाता है और पौधों में सड़न, कीड़े और फंफूद हो जाती हैं।
- सर्दी में वाटर टैंक में अगर ज्यादा ठंडा पानी हो, तो उसकी बजाय ताजा, भूमिगत जल देना चाहिए।
- अपने पौधों को धूप की जरूरत पर ध्यान दें। पत्तियों और पौधे की धुलाई करती रहें।

यूज करें बॉडी बटर स्किन बनी रहेगी सॉफ्ट

स्किन केयर

अंजू जैन

विंटर सीजन में स्किन के रूखेपन, रैशेज, डल हो जाने से अधिकतर महिलाएं परेशान रहती हैं। ऐसे में बॉडी बटर, लेटेस्ट ऑप्शन के रूप में स्किन केयर का सबसे इफेक्टिव रूप सामने आया है। गाढ़ी, स्मूद और प्लस टेक्सचर्ड यह क्रीम त्वचा में गहराई तक जाकर उसे मॉयश्चराइज और हाइड्रेशन का डोज देती है। ऐसा इफेक्ट कोई नॉर्मल मॉयश्चराइजिंग क्रीम नहीं दे सकती। इसे लगाने से स्किन सिल्की, लचीली और नम रहती है, जिससे उसमें ग्लो नजर आता है।

क्या करता है बॉडी बटर: बॉडी बटर स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके इस्तेमाल से स्किन के भीतरी हिस्से में नमी पहुंचती है और टिकती भी है। नमी के अभाव में स्किन की बाहरी सतह की सेल्स सूख कर सिकुड़ने लगती हैं। इसके बाद स्किन की भीतरी लेयर्स का भी यही हाल होने लगता है। स्किन संवेदनशील बनने लगती है और इसमें झुर्रियां और सिलवटें पड़ने लगती हैं। इसकी वजह से त्वचा की प्री-मैच्योर एजिंग, इंफेक्शन, क्रैक और ड्राई स्किन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला बॉडी बटर स्किन सेल्स के निर्माण की प्रक्रिया को भी तेज करता है। इसमें मौजूद सामग्री स्किन को विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स से पोषण देती है। सनबर्न, रैशेज, सोरायसिस, एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है। कोहनी और एड़ियों जैसी कठोर त्वचा वाले हिस्सों को भी बॉडी बटर के प्रयोग से इंप्रूव किया जा सकता है। कई तरह के नट्स और सीड्स इन्हें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण देते हैं।

ऐसे करें यूज: बॉडी बटर भी मॉयश्चराइजर की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूरे शरीर पर लगाया जा सकता है। नहाने के बाद, शरीर को तौलिए से थपथपा कर सुखा लें और फिर बॉडी बटर लगा लें। इसका इस्तेमाल आप होंठ, नाखून और बालों पर भी कर सकती हैं।

तरह-तरह के बॉडी बटर: बाजार में कई तरह के बॉडी बटर मिलते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी यूज कर सकती हैं।

शिया बटर: अफ्रीकन शिया ट्री के फल से बनाया गया यह बॉडी बटर, स्ट्रॉन्ग मॉयश्चराइजर है और स्किन को मखमली लुक देता है। इसमें फैटी एसिड होता है, जिसमें सुपर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।

कोकोआ बटर: इनमें कोकोआ बीन का एडिबल फैट होता है। यह विटामिन-ई से समृद्ध होता है। इसके प्रयोग से स्किन को अच्छा हाइड्रेशन मिलता है और स्किन की सूदिंग होती है।

(ब्यूटीशियन अनुमिता पाल से बातचीत पर आधारित)

अगर इस मौसम में आपका वजन बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए अपनी डाइट में आप क्या-क्या शामिल कर सकती हैं, जानिए।

ऐसे वेट रहेगा कंट्रोल

डाइट एडवाइस

डॉ. स्वप्ना चतुर्वेदी
सीनियर डाइटीशियन, एम्स-दिल्ली

सर्दी के मौसम में भूख बढ़ने, कम एक्टिविटी करने और फैटी चीजें खाने को कई लोगों का वेट बढ़ने लगता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना होगा। इससे बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि शुरुआत से ही हेल्दी डाइट लेने की आदत डालें और तले-भुने फूड्स से परहेज करें। जहां तक संभव हो बाहर खाने से बचें। घर का बना ताजा भोजन ही करें।

संतुलित आहार लें: यदि आप इस मौसम में भी स्वयं को फिट और अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहती हैं, तो अपने आहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। दिन की शुरुआत अकसर चाय से की जाती है, लेकिन खाली पेट चाय पीने से कई लोगों को गैस की समस्या हो जाती है। इसलिए चाय पीने से पहले एक-दो कप पानी अवश्य पीना चाहिए। इसके साथ मखाना, नट्स, आटा या ओट्स के बिस्कुट ले सकती हैं। नाश्ते में बेसन या दाल का चीला लेना बेहतर होता है। दलिया और किनोवा भी ले सकती हैं। इसके अलावा पनीर, दूध, छाछ और अंडा भी लिया जा सकता है। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नाश्ते के बाद सुबह 10 से 11 के बीच में सेब या पपीता जैसे फल लेना फायदेमंद होता है। दोपहर और रात के खाने में हेल्दी अनाज अपने भोजन में जरूर शामिल करें। बाजरा, मक्का की रोटी, ब्राउन राइस, दाल, मौसमी सब्जियां, दही और सलाद जरूर खाएं। इसके साथ ही बाजरे की खिचड़ी भी ले सकती हैं। यह बहुत ही पौष्टिक होती है और इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर्स भरपूर मात्रा में होते हैं। रात का भोजन सोने से कम से कम दो घंटे पहले कर लेना चाहिए। रात के खाने में सूप अवश्य लें। इसके अलावा सोने से पहले दूध भी लिया जा सकता है। बहुत अधिक गर्म खाना खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्म खाने से भोजन की नली पर इसका बुरा असर पड़ता है। इससे मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं।

तला-भुना न खाएं: ठंड के मौसम में तला-भुना खाने का मन बहुत करता है। जैसे समोसा, कचौरी, छोले-भटूरे, आलू, गोभी और बथुआ के परांठे खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन इनके अधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है। वजन बढ़ाना तो बहुत आसान है, जबकि उसे कम करना उतना ही कठिन होता है। इस तरह के भोजन में कैलोरी की मात्रा बहुत अधिक होती है जबकि इस मौसम में हमारी शारीरिक गतिविधियां बहुत कम होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में फैट जमा होने लगता है। एक व्यक्ति को महीने में तेल और घी मिलाकर आधा लीटर से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों का ज्यादा उपयोग करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दिन और रात के भोजन को मिलाकर कुल दो चम्मच तेल का उपयोग करना ही बेहतर होता है।

प्रस्तुतिः संध्या रानी

रेग्युलर करें एक्सरसाइज

सर्दियों में अपने को हेल्दी, फिट रखने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। ठंड से बचने के लिए अगर आप बाहर जाकर वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, तो घर के अंदर ही योगा, प्राणायाम और कुछ हल्की एक्सरसाइज जरूर कर सकती हैं। इससे एक तो थकान और आलस से बच सकती हैं और आपका मूड भी अच्छा रहेगा।

चिंतन

बहकावे में आकर देशविरोधी साजिश रचना गंभीर मसला

आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली दंगा मामले में आरोपित उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं देकर दिल्ली पुलिस की मजबूत चार्जशीट और सरकार की आतंक विरोधी नीति पर अपनी मुहर लगा दी। यह फैसला आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सरकार की नीति को और मजबूत करता है। अदालत ने कहा कि आतंकी कृत्यों को केवल हिंसा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें आवश्यक सेवाओं में व्यवधान और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी शामिल है। यह फैसला दर्शाता है कि किसी के बहकावे में आकर देशविरोधी गतिविधियां चलाने और साजिश रचने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 'आतंकवादी कृत्य' केवल अंतिम परिणाम नहीं है, बल्कि इसमें साजिश और उकसावे की पूरी प्रक्रिया भी शामिल होती है। इससे आर्थिक असुरक्षा और नागरिक जीवन में अस्थिरता पैदा होती है, भले ही इस प्रक्रिया में हिंसा न की गई हो। शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली दंगों 'बड़े षड्यंत्र' मामले में आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर अपने फैसले में, 1967 अधिनियम की धारा 15(1) (ए) का उल्लेख करते हुए किसी अन्य माध्यम से वाक्यांश के अवशिष्ट अर्थ को रेखांकित किया और बम, डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों, आग्नेयास्त्रों, अन्य घातक हथियारों, जहरीली, हानिकारक गैसों, अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) के उपयोग से किए गए आतंकी कृत्यों को परिभाषित किया है। हालांकि अदालत ने पांच अन्य आरोपितों को 12 शर्तों के साथ जमानत भी दी है। इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। उमर और शरजील मामले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, सभी आरोपितों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। दोनों एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। यह फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश के मामले में आया है, जिसमें दोनों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने कहा, उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर प्रकृति की है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं। लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकता। यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में जमानत के मानकों को स्पष्ट करता है। यूएपीए की धारा 43डी(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। इसमें न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह फैसला आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ सरकार की नीति को मजबूत करता है। आतंकी कृत्यों को केवल हिंसा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें आवश्यक सेवाओं में व्यवधान व अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी शामिल है। हालांकि, यह फैसला कई सवाल भी खड़े करता है। क्या खालिद व शरजील को जमानत नहीं मिलने से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? क्या यूएपीए का इस्तेमाल सरकार द्वारा विरोधियों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब देना हालांकि मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बहकावे में आकर देशविरोधी साजिश रचना एक गंभीर मसला है। देश की सुरक्षा और एकता को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

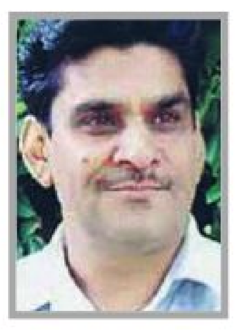

वेनेजुएला घटनाक्रम
डॉ घनश्याम बादल

अचंभित दुनिया, बेलगाम ट्रंप

जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में बैठकर कोलंबिया और मेक्सिको के राष्ट्रपतियों को भी धमकी दी वह और भी ज्यादा चिंताजनक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। ट्रंप का यह अभियान उसी 'रूल्स-बेस्ड ऑर्डर' का शव परीक्षण है, जिसकी दुहाई पश्चिम दशकों से देता आया है। भले ही ट्रंप मादुरो पर ड्रग तस्करी एवं आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। यदि ऐसे आरोप के आधार पर अमेरिका यह कार्रवाई करता है तो फिर उसका पहला टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन आतंकिस्तान का नाम पा चुके इस देश को वह गोद में बैठाकर रखता है। वहां के सेना अध्यक्ष को लोकतांत्रिक सरकार को एक तरफ करते हुए लंच पर बुलाता है। ऐसे में वह दोहरी नीति क्यों अपनाता है।

लोकतंत्र के स्वयं भू ठेकेदार और दुनियाभर में थानेदारी करने वाले अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलविया फ्लोरेस के साथ बेडरूम से घसीट कर, बंधक बनाकर हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर डिटेंशन सेंटर में रखा है वह एक तानाशाह, वैध या अवैध राष्ट्रपति का अपहरण मात्र नहीं बल्कि वेनेजुएला के प्रतीक रूप में दुनिया भर के लोकतंत्र की आत्मा का अपहरण एवं प्रताड़ना है। इसके अलावा वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी देना और समर्थन करने वाले राष्ट्रों को धमकाना भी ट्रंप की तानाशाही को दर्शाता है। बेलगाम ट्रंप के इन कदमों से पूरी दुनिया अचंभित है।

जब किसी संप्रभु देश का राष्ट्रपति खुले तौर पर यह कहता है कि उसने दूसरे संप्रभु देश में सैन्य या अर्धसैन्य अभियान चलाकर वहां के राष्ट्राध्यक्ष को बंधक बनाया, तो यह केवल एक देश की कार्रवाई नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वैश्विक व्यवस्था की सामूहिक अवहेलना बन जाती है। यह वही अमेरिका है जो दुनिया को लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून का पाठ पढ़ाता रहा है। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अमेरिका का ताकत प्रदर्शन का यह चेहरा पहले भी कई बार सामने आ चुका है। चिली, पनामा, ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान, वियतनाम, ईरान व इराक जैसे कितने ही देश में अमेरिका ने मनमाने आरोप लगाकर वहां के शासकों को सत्ता से बेदखल किया।

एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन नाम के इस अभियान के बाद जिस तरह ट्रंप ने अमेरिका में बैठकर कोलंबिया और मेक्सिको की राष्ट्रपतियों को भी धमकी दी वह और भी ज्यादा चिंताजनक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है। ट्रंप का यह अभियान उसी 'रूल्स-बेस्ड ऑर्डर' का शव परीक्षण है, जिसकी दुहाई पश्चिम दशकों से देता आया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप मादुरो पर ड्रग तस्करी एवं आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच कुछ और ही है। यदि ऐसे आरोप के आधार पर अमेरिका यह कार्रवाई करता है तो फिर उसका पहला टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन आतंकिस्तान का नाम पा चुके इस देश को वह गोद में बैठाकर रखता है। वहां के सेना अध्यक्ष को एक तरफ करते हुए लंच पर बुलाता है। अमेरिका की कथनी करनी में यह फर्क कोई पहली बार परिलक्षित नहीं हुआ है यह उसकी बहुत पुरानी फितरत रही है। यदि गहराई में जाया जाए तो इस अभियान का मूल राजनीतिक कारण है अपनी मनमाफिक सत्ता-परिवर्तन की ज़िद। और साथ ही साथ पेट्रोलियम, सोने एवं हीरे जैसे बहुमूल्य खनिजों की संपदा से मालामाल इस देश पर कब्जा करने की उसकी गिद्ध दृष्टि है। वैसे वेनेजुएला के साथ अमेरिका का संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है। ह्यूगो चावेज़ के समय से ही वाशिंगटन की असहजता जगज़ाहिर रही है। निकोलस मादुरो उस असहजता की निरंतरता हैं। अमेरिका को समस्या केवल मादुरो से नहीं, बल्कि उस राजनीतिक

मॉडल से है जो अमेरिकी प्रभाव से बाहर निकलकर संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण और सामाजिक राज्य की बात करता है।

ट्रंप के कृत्य से साफ है कि लोकतंत्र का सवाल केवल एक औज़ार था, असली लक्ष्य सत्ता-परिवर्तन। जब चुनाव, प्रतिबंध और कूटनीति काम नहीं आए, तो सीधा हस्तक्षेप ही अमेरिकी राजनीति का नंगा सच है।

इस घटनाका आर्थिक पक्ष तेल, डॉलर और सत्ता पर नियंत्रण है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है। यह तथ्य इस पूरे घटनाक्रम की चाबी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक हैसियत तेल, डॉलर और नियंत्रण के त्रिकोण पर टिकी है। वेनेजुएला का अपने तेल संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और चीन-रूस जैसे देशों से बढ़ता सहयोग, अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती था। ट्रंप का अभियान दुनिया भर के देशों को खुला धमकी भरा संदेश है कि ऊर्जा संसाधनों पर स्वतंत्र नीति अपनाने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह संदेश केवल वेनेजुएला के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए है जो वैश्विक आर्थिक ढांचे में अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अमेरिकी हस्तक्षेप के पीछे केवल राजनीति और अर्थशास्त्र नहीं, एक गहरी सांस्कृतिक मानसिकता भी है। उसके पीछे की धारणा है कि अमेरिका को जो उचित लगे, वही वैश्विक नैतिकता है और जो उसे चुनौती दे उसे नेस्तनाबूद करना उसके लिए अनैतिक नहीं है। लैटिन अमेरिका का इतिहास इस मानसिकता का शिकार रहा है चिली, ग्वाटेमाला, पनामा, निकारागुआ और अब वेनेजुएला। हो सकता है इसके बाद कोलंबिया और मैक्सिको की भी बारी आए। जिसकी झलक ट्रंप के उस अभियान भरे बयान के बाद मिल रही है, जिसमें उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति को अपनी जान की परवाह करने की खुली धमकी दी है। ख़ैर कल जो होगा सो होगा। अभी तो वेनेजुएला के घटनाक्रम का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा है इसका आकलन करना जरूरी है

राष्ट्रपति को बंधक बनाना केवल एक व्यक्ति का अपहरण नहीं, पूरे राष्ट्र की संप्रभुता का अपहरण है। इससे वेनेजुएला के भीतर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, सामाजिक ध्रुवीकरण गहराएगा और हिंसा की आशंका प्रबल होगी। वहां का आम नागरिक जो पहले ही प्रतिबंधों, महंगाई और अभावों से जूझ रहा है अब और असुरक्षित महसूस करेगा। लोकतंत्र का दावा करने वाली ताक़तों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आम जनता उनके एजेंडे में सबसे आख़िर में आती है। भले ही तात्कालिक रूप से रूस चीन ब्रिटेन व यूरोपीय यूनियन के देश ने इस घटनाक्रम की आलोचना की है, लेकिन सच यह भी है कि यह आलोचना केवल शाब्दिक निंदा तक ही सीमित रहने वाली है। इस घटनाक्रम ने भारत के सामने भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत परंपरागत रूप से संप्रभुता, गैर-हस्तक्षेप और बहुध्रुवीय विश्व का पक्षधर रहा है। वेनेजुएला के साथ भारत के ऊर्जा संबंध भी रहे हैं। नैतिकता की दृष्टि से भारत के लिए चुप रहना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी पक्ष का अंध समर्थन भी भारत की गुटनिरपेक्ष रणनीति के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन यह सोचकर कि वेनेजुएला हमसे बहुत दूर का देश है इस मुद्दे पर चुप्पी खींच लेने से भारत की इमर्जिंग वर्ल्ड पावर की छवि पर भी एक बड़ा निशान खड़ा होगा। अमेरिका के इस दबंग कृत्य से संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति सब हाशिये पर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि वेनेजुएला की घटना केवल एक देश की त्रासदी नहीं, वैश्विक लोकतंत्र की परीक्षा की घड़ी है। जब सेना हथियार और आर्थिक ताक़त को नीति और अपहरण को कूटनीति बना दिया जाए, तो दुनिया अराजकता की ओर बढ़ती है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। सवाल यह नहीं कि अगला कौन, सवाल यह है कि क्या दुनिया इसे रोकने का साहस दिखाएगी?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

इंदौर की चेतावनी
सुनील कुमार महला

प्रदूषित जल से जन-जीवन पर गहराता जा रहा संकट

कहा गया है कि 'जल ही जीवन है।' लेकिन जल किसी की जान ले लें तो यह बहुत दुःखद ही कहा जाएगा। हाल ही में देश के सबसे साफ शहर माने जाने वाले इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल शहर के 41 अस्पतालों में कुल 203 मरीजों का इलाज चल रहा है और इनमें से 34 लोगों को आईसीयू में रखा गया है। अच्छी बात यह है कि गंदे पानी पीने से उल्टी-दस्त फैलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और मरीजों को जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। हालांकि, लोकल लोगों का दावा है कि गंदे पानी से छह महीने के एक बच्चे समेत कुल 17 लोगों की जान गई है। यह घटना मुख्यतः शहर के कुछ इलाकों में हुई, जहां सीवर लाइन और जलापूर्ति पाइपलाइन में लीकेज/क्रॉस-कनेक्शन के कारण दूषित पानी घरों तक पहुंचा। इस पानी के सेवन से लोगों को तेज दस्त, उल्टी, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याएं हुईं तथा जांच में पानी में हानिकारक बैक्टीरिया (जैसे ई-कोलाई) पाए गए, जो मानव मल से फैलते हैं। भारत ही नहीं, आज विश्व स्तर पर दूषित जल एक गंभीर मानव-स्वास्थ्य और विकास समस्या बना हुआ है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि विश्व तथा भारत-दोनों स्तरों पर दूषित जल (वाटर पोल्यूशन) के कारण लगभग समान हैं, हालांकि जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकीकरण और प्रबंधन की कमी के कारण भारत में इनका प्रभाव अधिक गंभीर रूप में दिखाई देता है। प्रमुख कारणों में प्रमुख रूप से औद्योगिक अपशिष्टों, घरेलू सीवेज और मलजल,कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग,ठोस कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण,धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां, खनन और निर्माण गतिविधियां तथा भूजल का प्राकृतिक व मानवजनित प्रदूषण आदि को शामिल किया जा सकता। यह बहुत ही दुखद है कि आज विभिन्न कल-कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, भारी धातुएं (सीसा, पारा, आर्सेनिक), रंग, एसिड और विषैले तत्व बिना पर्याप्त शोधन के नदियों, झीलों और भूजल में छोड़ दिए जाते हैं। इससे जल न केवल पीने योग्य नहीं रहता, बल्कि जलीय जीवन भी नष्ट होता है।

जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा और गंभीर कारण प्लास्टिक माना जा रहा है। आधुनिक जीवनशैली में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है जैसे पॉलीथिन बैग, बोतलें, पैकेजिंग सामग्री और डिस्पोज़ेबल वस्तुएं आदि। जिसके परिणामस्वरूप आज हमारी नदियों, झीलों और समुद्रों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पहुंच रहा है। पाठक जानते हैं कि प्लास्टिक जैव-अपघटित नहीं होता, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक जल में बना रहता है। धीरे-धीरे माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है। ये सूक्ष्म कण जलीय जीवों द्वारा निगल लिए जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होती है और अंततः यही विषैले कण खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक जल प्रवाह को बाधित करता है, नालों को जाम करता है और जल स्त्रोतों की प्राकृतिक शुद्धता को नष्ट करता है। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। आज दूषित जल की समस्या वैश्विक है, लेकिन भारत में कचरा प्रबंधन की कमजोरी इसे और गंभीर बनाती है। हमारा देश एक धार्मिक देश है और हमारे यहां नदियों, झीलों, पानी के विभिन्न स्त्रोतों आदि में मूर्तियों का विसर्जन, पूजा सामग्री, अस्थि विसर्जन और सामूहिक स्नान जैसी गतिविधियां जल में रसायन, रंग और जैविक कचरा बढ़ाती हैं, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। निष्कर्षतः, हम यहां यह बात कही सकते हैं कि आज विश्व और भारत दोनों में दूषित जल की समस्या मानव गतिविधियों का ही परिणाम है। यदि समय रहते प्रभावी जल प्रबंधन, अपशिष्ट शोधन और जन-जागरूकता नहीं बढ़ाई गई, तो यह समस्या भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकती है। यदि हम यहां जल से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूनिसेफ के अनुसार आज भी दुनिया में लगभग 2.2 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवा से वंचित हैं, यानी उन्हें ऐसा पानी नहीं मिल पाता जो घर पर उपलब्ध, निरंतर और दूषण-मुक्त हो। इनमें से करीब 1.7 अरब लोग ऐसे जल स्त्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनमें मल-जनित प्रदूषण का जोखिम रहता है, जबकि लगभग 115 मिलियन लोग सीधे नदियों, तालाबों और झीलों जैसे सतही जल पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि दूषित पानी के सेवन से हर वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जो एक गंभीर समस्या है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

संकलित
दर्शन

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असत दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छापूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देगी, जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्र में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाली संभावित प्रतिक्रिया से हर दम चिंता में डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो, जिसकी बराबरी धरती का कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी न कर सके और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला न हो सके। रावण से लेकर कंस आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन में अपनी ऐसी ही मानसिक विकृतियों से कभी भी पार नहीं पा सके।

कोयल- अपनी वाणी को मधुर बना लेना

संकलित
प्रेरणा

एक बार वसंत ऋतु में एक कोयल वृक्ष पर बैठी कूक रही थी। आते-जाते लोग उसकी कूक को सुनते और उसकी सुरीली आवाज का आनंद लेते हुए उसकी तारीफ के पुल बांधते। कुछ देर बाद कोयल के सामने एक कौआ तेज गति से आया। कोयल ने उससे पूछाः इतनी तेज गति से कहां जा रहे हो? कुछ देर बैठो, बातें करते हैं। कौए ने उत्तर दियाः कि वह जरा जल्दी में है और देश को छोड़कर परदेस जा रहा है। कोयल ने इसका कारण पूछा तो कौआ बोलाः यहां के लोग बहुत खराब हैं। सब तुम्हें ही चाहते हैं। सभी लोग सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं। वह यही चाहते हैं कि तुम हमेशा की तरह इसी प्रकार से उनके क्षेत्र में गाती रहो। वहीं जहां तक मेरी बात है तो मुझे कोई देखना तक नहीं चाहता। यहां तक कि मैं किसी की मुंडेर पर बैठता हूं तो मुझे कंकड़ मारकर वहां से भगा दिया जाता है। मेरी आवाज भी कोई नहीं सुनना चाहता। जहां मेरा अपमान हो, मैं ऐसे स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। ज्ञानियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि अपमान की जगह पर नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर कोयल बोली, परदेस जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ। यह पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक बात का सदैव ध्यान रखना कि वहां जाने से पहले अपनी आवाज को बदल लेना। अपनी वाणी को मधुर बना लेना। यदि तुम्हारी वाणी ठीक वैसी ही कठोर रही, जैसी यहां पर है तो परदेस में भी लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो अभी हो रहा है। संसार जो है, जैसा भी है, उसे बदला नहीं जा सकता।

अंतर्मन

आज की पाती

पानी में भी भ्रष्टाचार का जहर तो नहीं मिल गया?

प्राणी जाति के लिए साफ-सथुरा पानी अमृत है तो दूषित पानी जहर होता है, इसका सेवन करने से बचें। अक्सर देश के विभिन्न राज्यों में दूषित पानी लोगों की सेहत का दुश्मन बन जाता है। आजकल वो शहर इंदौर जिसे स्वच्छ भारत अभियान में नंबर वन का खिताब मिला है, वहां दूषित पानी से लोगों की मौत सुर्खियां बनी हुई हैं। अगर सबसे स्वच्छ स्थान का ही यही हाल बेहाल है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर पानी दूषित कैसे हो जाता है? क्या पानी की सप्लाई के लिए जो व्यवस्था है, उसकी समय-समय पर जांच नहीं की जाती? या फिर संबंधित विभाग के बाबुओं को मोटी सैलरी से ही मतलब है? कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? *- विवेक पटनायक, रायगढ़*

ट्रेंड

हमारी महान संस्कृति

हमारी महान संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत अनगिनत हमलों की भी साक्षी रही है। यह देशवासियों की सामूहिक शक्ति ही है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमेशा अक्षुण्ण रखा है।
वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः।
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सौहृदम्॥

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

समुद्र सुरक्षित

एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी देता है। ऐसे में 'समुद्र प्रताप' जैसे प्लेटफॉर्म समुद्री सुरक्षा को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करते हैं।

-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

जनता की पैरवी करूंगी

चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। जब से एसआईआर शुरू हुई है, डर के मारे 70 लोगों की मौत हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी। जनता की आवाज उठाउंगी।

-ममता बनर्जी, सीएम पश्चिम बंगाल

यह हमारा निजी मामला

धर्मेंद्र के निधन के बाद मेरे परिवार द्वारा दो अलग-अलग प्रार्थना सभाएं आयोजित करने का निर्णय निजी मामला था। हमने आपस में बात की थी। मैंने अपने घर पर एक प्रार्थना सभा रखी, क्योंकि मेरे करीबी लोग अलग हैं और उनके अलग।

-हेमा मालिनी, अभिनेत्री व सांसद

करंट अफेयर

इमरान से जुड़ा गाना गाने पर गायक के खिलाफ मामला दर्ज

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा गाना गाने के आरोप में एक पेशेवर गायक और उसकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया। पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया, 'शनिवार रात लाहौर के शालीमार गार्डन में सरकार द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान 'कैदी नंबर 804' गाना गाने के आरोप में जाने-माने कव्वाल फराज अमजद खान और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।' उन्होंने बताया कि गायक और उनकी टीम ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर 'जनता को भड़काने' की कोशिश की क्योंकि यह गाना जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान से जुड़ा है। प्राथमिकी के मुताबिक, "विवादित गीत से अशांति और हिंसा भड़कने का खतरा था। संगीत और सांस्कृतिक संध्या 'चांदनी रातें' का आयोजन लाहौर प्राधिकरण द्वारा किया गया था। दूसरी ओर, गायक फराज अमजद खान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें इस 'इमरान समर्थक गीत' को गाने के लिए धमकाया गया था।

ऑफ बीट

कई ग्लुटेन मुक्त उत्पादों में कैलोरी-शर्करा अधिक

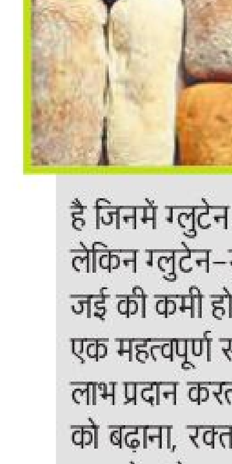

अमेरिकी उपभोक्ता अक्सर ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करते हैं, फिर भी ये उत्पाद आमतौर पर ग्लुटेन युक्त विकल्पों की तुलना में कम प्रोटीन और अधिक शर्करा एवं कैलोरी प्रदान करने वाले होते हैं। वर्तमान में कई ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके अलावा, ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में आमतौर पर ग्लुटेन युक्त अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक शर्करा पाई जाती है। ग्लुटेन-मुक्त आहार के लंबे समय तक सेवन का संबंध 'बॉडी मास इंडेक्स' (बीएमआई) में वृद्धि और पोषण संबंधी कमियों से है। ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद को अमेरिका में ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें ग्लुटेन प्रति 10 लाख में 20 भाग से कम या उसके बराबर होता है। लेकिन ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद में बड़े पैमाने पर गेहूं, राई, जौ और कभी-कभी जई की कमी होती है, जबकि ये सभी 'रबीनॉक्सिलन' के समृद्ध स्रोत हैं जो एक महत्वपूर्ण स्टार्च रहित पॉलीसेकेराइड है। अरबीनॉक्सिलन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, पाचन को बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और संतुलित आंत माइक्रोबायोटा का समर्थन करना शामिल है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता उमर और शरजील जेल में रहंगे

भाजपा बोली- 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' का समर्थन करने के लिए कांग्रेस मांगे माफी

भाजपा ने शीर्ष अदालत के फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवेशी तंत्र के चेहरे पर 'करारा तमाचा' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 'टुकड़े-टुकड़े के 'पोस्टर बॉय' उमर खालिद और शरजील इमाम को निर्दोष पीड़ित' के रूप में पेश किया

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

शीर्ष अदालत ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी सोमवार को ठुकरा दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने शीर्ष अदालत के फैसले को राहुल गांधी और कांग्रेस के परिवेशी तंत्र के चेहरे पर 'करारा तमाचा' बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 'टुकड़े-टुकड़े के 'पोस्टर ब्वॉय' उमर खालिद और शरजील इमाम को निर्दोष पीड़ित' के रूप में पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत की अदालत और कानून की अदालत में गांधी के 'अर्बन नक्सली' पराजित हुए हैं। भंडारी ने कहा कि क्या कांग्रेस भारत के लिए शत्रुतापूर्ण टुकड़े-टुकड़े ताकतों को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए देश से माफी मांगेगी? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फैसले पर कहा कि 'सत्यमेव जयते।'

कानून की अदालत में गांधी के 'अर्बन नक्सली'

सुप्रीम कोर्ट

कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सीएम रेखा गुप्ता बोलीं

दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर को दंगों की आग में धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दंगों में शामिल लोगों का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए कड़ा संदेश जाना चाहिए जो 'अपराध में भागीदार' थीं। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि फैसले ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दंगे एक ''सुनियोजित साजिश' का नतीजा थे।

अब जेल ही मेरी जिंदगी उमर खालिद ने कहा

जमानत हासिल करने में विफल रहे उमर खालिद ने अपनी दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से कहा कि मैं बाकी लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई! राहत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि मिलने आते रहना, अब जेल ही मेरी जिंदगी है।

फैसले का सम्मान करता हूं: शरजील के चाचा

शरजील के चाचा अरशद इमाम ने कहा कि फैसले से मैं बेहद आहत हूं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार अदालत जमानत देगी, क्योंकि बहस के दौरान हर बिंदु से यही संकेत मिल रहा था कि शरजील निर्दोष है। फिर भी, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भतीजा निर्दोष है।

विपक्षी नेताओं ने कहा

उमर, शरजील को जमानत नहीं राम रहीम को 15वीं बार पैरोल

...और कितनी कैद सहनी होगी: सांसद झा

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने कहा कि जेल में पहले ही बिताया गया समय अभी भी पर्याप्त लंबा नहीं है और मुकदमे में देरी अभी भी चौंकाने वाली या असंवैधानिक नहीं है। अब पहले कितनी कैद सहनी होगी।

ये न्याय का मखौल महबूबा मुफ्ती बोलीं

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि न्याय का कैसा मखौल है! एक तरफ गुरमीत सिंह, जिसे बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया है, उसको बार-बार पैरोल मिल रही है।

खबर संक्षेप

भाजपा नेता सोम को बांग्लादेश से धमकी

मेरठ। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता ठाकुर संगीत सोम को बांग्लादेश से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल मिलने के बाद उन्होंने सरधना थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है।

लालू यादव की याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के निर्णय के खिलाफ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

प्रतिका की ग्रोक से फोटो एडिट न करने की अपील

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने सोशल मीडिया पर खास अपील करते हुए अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने की बात की है। प्रतिका ने ये अपील एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई ग्रोक से की है। प्रतिका की बात पर ग्रोक ने कहा कि मैं समझ गया प्रतिका।

सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, 14 घायल

जयपुर। राजस्थान में दो अलग-अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार रविवार देर रात जालोर जिले में राजमार्ग पर स्लीपर बस पलटने से एक बुजुर्ग दंपत्ति समेत तीन लोगों की मौत हो गई।

किसानों को महंगाई से बचाने मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत

रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर 37952 करोड़ की, डीएपी पर विशेष ध्यान

केंद्र सरकार का यह कदम न केवल बुवाई के आगामी सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि मृदा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है

सब्सिडी खरीफ सीजन के मुकाबले 736 करोड़ रुपए अधिक

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

वैश्विक बाजार में कच्चे माल की कीमतों में अनिश्चितता और किसानों को महंगाई से बचाने के उद्देश्य से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इस सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की अनुमानित उर्वरक आवश्यकता तय की है, जो खरीफ 2025 सीजन के मुकाबले करीब 736 करोड़ रुपए अधिक है। यह कदम न केवल बुवाई के आगामी सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि मृदा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेंगी और इसमें फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पी और के) उर्वरक शामिल हैं, जिनमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड भी शामिल हैं।

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों और कच्चे माल की अस्थिर कीमतों को देखते हुए की गई है। किसानों पर लागत का बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी दरों में, विशेषकर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए, भारी वृद्धि की है।

डीएपी सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी

अमृतसर में किसान अपने खेत में उर्वरक का छिड़काव करता हुआ

डीएपी सब्सिडी बढ़ाकर 29,805 रुपए प्रति टन कर दी गई

डीएपी पर सब्सिडी पिछले वर्ष के 21,911 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 29,805 रुपए प्रति टन कर दी गई है। इस निर्णय का सीधा लाभ गेहूं, तिलहन और दालों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा, क्योंकि रबी सीजन इन फसलों की बुवाई का मुख्य समय होता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीक सीजन के दौरान किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होते रहें।

अधिक उर्वरक से मिट्टी की सेहत बिगड़ती है

वर्षों तक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग ने कई क्षेत्रों में मिट्टी की सेहत को खराब किया है और उपज में वृद्धि को सीमित कर दिया है। एनबीएस योजना द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों (माइक्रोन्यूट्रिएंट्स) के उपयोग को बढ़ावा देकर मृदा क्षरण और पोषक तत्वों के असंतुलन की समस्या का समाधान करती है।

एनबीएस योजना: संतुलित खेती की ओर बड़ा कदम

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एबीएस) योजना, जिसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था। एनबीएस ढांचा उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों- नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस)- के आधार पर सब्सिडी तय करता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

उत्पादकता में वृद्धि हुई

सरकार के अनुसार एनबीएस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। देश में खाद्यान्न उत्पादकता, जो 2010-11 में 1,930 किलोग प्रति हेक्टेयर थी, वह 2024-25 में बढ़कर 2,578 किलोग प्रति हेक्टेयर हो गई है। यह वृद्धि मोटे तौर पर एनबीएस योजना के विस्तार की अवधि के साथ मेल खाती है। दूसरी ओर घरेलू उत्पादन के मोर्चे पर भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

तीन वर्षों में सब्सिडी 2.04 लाख करोड़ रुपए

केंद्र सरकार ने 2022-23 और 2024-25 के बीच राष्ट्रीय उर्वरक प्रणाली (एनबीएस) सब्सिडी के लिए 2.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को किफायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सके हैं। उच्च पैदावार, बेहतर मृदा स्वास्थ्य और आयात पर कम होती निर्भरता इस खर्च को उचित ठहराती है। रबी सीजन के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी न केवल किसानों को वैश्विक महंगाई से राहत देगी, बल्कि यह भारतीय कृषि को वैज्ञानिक और संतुलित खेती की ओर ले जाने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का भी हिस्सा है।

मेनका गांधी का विवादित बयान

पटाखों का इस्तेमाल करने वाले देशद्रोही, दिवाली से ही प्रदूषण

कहा, दिवाली के दिन, दशहरे के दिन, शादियों पर, नए साल पर, क्रिकेट मैच के दौरान या किसी अन्य दिन लोग पटाखे जलाते हैं

पूर्व मंत्री मेनका गांधी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पटाखा जलाने वालों को देशद्रोही कह दिया है और साथ ही इस समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा दिया है। मेनका गांधी ने कहा कि पराली या गाड़ियों से प्रदूषण की बात झूठी है, क्योंकि दिवाली के तीन दिन पहले तक हवा साफ थी। उन्होंने ग्रीन पटाखों की इजाजत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की।सिर्फ दिवाली के दिन यदि 800 करोड़ के पटाखे केवल दिल्ली में उड़ाए जाएं तो उसका नतीजा क्या होगा? उन्होंने कहा कि जब तक बारिश नहीं होती तब तक यह जहरीली हवा नहीं जाएगी। बारिश आएगी भी तो क्या होगा वह सारा जहरीला रसायन जमीन में चला जाएगा।

दिवाली से पहले तक साफ थी हवा

मेनका गांधी ने दिवाली पर होने वाली आतिबाजी को दिल्ली के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन, दशहरे के दिन, शादियों पर, नए साल पर, क्रिकेट मैच के दौरान या किसी अन्य दिन वे लोग पटाखे जलाते हैं नतीजतन हम सांस नहीं ले पाते हैं। देश में हम अन्य चीजों पर दोष डालते हैं कि कोई खेतों को जला रहा है, गाड़ियों की समस्या है लेकिन ये सब झूठ है। क्योंकि दिवाली के तीन दिन पहले तक हवा एक दम साफ होती है और दिवाली से लेकर नए साल तक हम सांस नहीं ले पाते हैं।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा **82 Cr.PC. / 84 BNSS** देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **गुलफाम उर्फ मोनु, पुत्रः** किस्मत अली, **पताः** पाठकपुर, बिठुर, थानाः चौबीपुर, जिला–कानपुर, उ.प्र. **और भीः** ए–1, खसरा न. 26/6, सैक्टर 27, रोहिणी, दिल्ली, ने **FIR No.: 220/2019, U/s: 376/363/506 IPC & 6 POCSO Act, थानाः शाहबाद डेरी, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **गुलफाम उर्फ मोनु,** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **गुलफाम उर्फ मोनु,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 220/2019, U/s: 376/363/506 IPC & 6 POCSO Act, थानाः शाहबाद डेरी, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त, **गुलफाम उर्फ मोनु,** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **12.02.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अजय नागर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (उत्तरी जिला)
एफआईएससी पॉक्सो (उत्तरी जिला)
कमरा न. 308, तीसरा तल
जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

DP/17474/ON/2025
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 CrPC देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सुनीता पत्नी** रमेश गुप्ता, **निवासीः** सुखपाल का मकान, सरकारी स्कूल के पीछे, बेगमपुर गांव, दिल्ली, ने **FIR No. 452/16, U/S 498A/406/506/34 IPC, पुलिस स्टेशन अमन विहार, रोहिणी जिला, दिल्ली,** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सुनीता** मिल नहीं रही है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सुनीता** फरार हो गयी है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही है)
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 452/16, U/S 498A /406/506/34 IPC, पुलिस स्टेशन अमन विहार, रोहिणी जिला, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **सुनीता** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **07.02.2026** को या इससे पहले हाज़िर हो।

आदेशानुसार
सुश्री नेहा गोयल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
(महिला कोर्ट)–02, कमरा नं0 18,
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/251/RD/2026
(Court Matter)

गृह मंत्री शाह ने अरंगनाथ मंदिर में की पूजा

तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु की अपनी दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीरंगम में अरुलमिगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने तिरुवनैकवल स्थित प्राचीन श्री जंबुकेश्वर-अकिलन्देश्वरी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मन्नारपुरम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महिला मोर्चा द्वारा आयोजित भव्य पोंगल उत्सव में भाग लिया। चावल, दाल, गुड़ और घी से तैयार मीठा व्यंजन पोंगल 1,008 सजे बर्तनों में पकाया गया था।

आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मां, भाई-बहन को धतूरा मिला लड्डू खिलाया फिर कर दी हत्या

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक युवक ने आर्थिक तंगी की वजह से अपनी मां, बहन व नाबालिग भाई को धतूरा मिला हुआ लड्डू खिलाने के बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी और फिर थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान यशवीर सिंह (23) के रूप में हुई है, जो लक्ष्मी नगर के सुभाष चौक का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शाम करीब पांच बजे थाने में आत्मसमर्पण कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी ने बताया कि उसके पिता ट्रक चालक हैं और पिछले छह महीने से वह परिवार के साथ नहीं रह रहे हैं। आरोपी के अनुसार, वह सोमवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर में गया, पास के एक पौधे से धतूरे के बीज लिए और लड्डू बनाए। इसके बाद उसने अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) को कथित तौर पर लड्डू खिलाए और अपराह्न डेढ़ से दो बजे के बीच घर पर उनका गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम को घटनास्थल की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए तैनात किया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने तमिलनाडु के ईरोड में किसानों-कामगारों से किया संवाद

शिवराज ने ईरोड में टरमरिक सिटी के लिए टेस्टिंग लैब खोलने की घोषणा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड की प्रसिद्ध हल्दी मंडी का दौरा किया और हल्दी उत्पादक किसानों व व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टरमरिक सिटी ईरोड में टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा करते हुए आईसीएआर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे हल्दी की गुणवत्ता जांच, प्रमाणीकरण और बेहतर विपणन में किसानों को सहायता मिलेगी। चौहान ने सोमवार को तमिलनाडु के ईरोड में कहा कि विकसित भारत–जी राम जी कानून स्वावलंबी गांवों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईरोड में कामगारों और श्रमिकों से संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने ईरोड में हल्दी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के विषय में भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह विषय वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है, लेकिन कृषि मंत्री होने के नाते वह स्वयं इस संबंध में पहल करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे हल्दी किसानों को नीतिगत सहयोग, बाजार तक बेहतर पहुंच और निर्यात के नए अवसर प्राप्त होंगे। चौहान ने कहा कि ईरोड क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जा सकता है और तमिलनाडु सरकार से आरकेवीवाई फंड के उपयोग का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने स्मगलिंग के जरिए लाई जा रही हल्दी पर रोक लगाने का भी आश्वासन दिया और कहा कि इन सभी विषयों पर दिल्ली में बैठक कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने अच्छी गुणवत्ता के बीज को कृषि की बुनियाद बताते हुए आईसीएआर के माध्यम से आवश्यक बीज विकास पर जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि उत्पादों के 100 से अधिक स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों एवं उद्यमियों से उनके उत्पादों, गुणवत्ता और संभावनाओं पर चर्चा की। चौहान ने 1000 से अधिक महिला किसानों से संवाद किया तथा विभिन्न किसान संगठनों और प्रगतिशील किसानों से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सहभागिता की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। अब ग्राम सभाएं स्वयं यह तय करेंगी कि उनके गांव में कौन-कौन से विकास कार्य किए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास से जुड़े फैसले अब चेन्नई या दिल्ली में नहीं, बल्कि गांव स्तर पर लिए जाएंगे। चौहान ने कहा कि कुछ लोग इस योजना को लेकर जानबूझकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना में बदलाव इसलिए किया है ताकि मजदूरों और कामगारों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचे और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान न रहे।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली–6 निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के अंतर्गत ई–निविदा आमंत्रित करते हैं:–

1.	कार्य का नाम एवं स्थान	उप मुख्य अभियन्ता / सी / एसईआरडी–II के अंतर्गत एमबी–जीजेडबी खंड में अतिक्रमण / सीआरओ / एचआरओ मामलों को रोकने के लिए सुरक्षा बाड़, सीमा दीवार, अंडरपास और अन्य प्रावधानों का प्रावधान खंडीय गति को 130 / 160 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए।
2.	अनुमानित / निदेशात्मक परियोजना लागत	रुपये 157,15,27,169.72/-
3.	कार्य पूरा करने की अवधि	12 माह
4.	जमा की जाने वाली जमानती राशि	रुपये 80,07,600.00/-
5.	विस्तृत ई–निविदा सूचना तथा निविदा दस्तावेज	उपर्युक्त निविदा दस्तावेज आई आर ई पी एस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर 05.01.2026 से 03.02.2026 तक उपलब्ध होगी।
6.	बोली पूर्व सम्मेलन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, प्रधान कार्यालय, उत्तर रेलवे, कश्मीरी गेट, दिल्ली तथा ऑनलाइन वीडियों कॉफ्रिंसिंग लिंक के माध्यम द्वारा दिनांक 12.01.2026 को 12:30 बजे बोली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
7.	पूर्वावलोकन प्रश्नों की प्राप्ति की अंतिम तिथि	13.01.2026 18:00 बजे तक
8.	पूर्वावलोकन प्रश्नों का उत्तर	19.01.2026 18:00 बजे तक
9.	ई–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	03.02.2026 को 12.30 बजे तक। निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज 20.01.2026 से 03.02.2026 तक www.ireps.gov.in वेब साइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।
10.	ई– निविदा खुलने की तिथि और समय	03.02.2026 को 12.30 बजे। विस्तृत निविदा सूचना उपरोक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है।

सं0 – 74–डब्लु/4/1/481/डब्लु.ए./एसईआरडी–II दिनांक : 05.01.2026 46/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कल्पमेधा

जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के मनोभावों का तनिक भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उन्माद है, प्रेम नहीं।

- मुंशी प्रेमचंद

मनमानी के बरक्स

विदेशी मामलों में भारत का रुख हमेशा से संतुलित रहा है, जो रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-गठबंधन और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। भारत शीत युद्ध की 'गुटनिरपेक्षता' से आगे बढ़कर अब अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय देशों और वैश्विक दक्षिण के साथ अलग-अलग मुद्दों पर संतुलन बनाता रहा है, जो उसे किसी एक गुट में बंधे बिना वैश्विक मंच पर मजबूत और स्वतंत्र पक्ष बनाता है। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई के मुद्दे पर भी भारत ने बातचीत से मसले को सुलझाने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखने पर जोर दिया है। साथ ही तेल समृद्ध वेनेजुएला में तेजी से बदल रही स्थिति पर करीबी नजर भी रखी जा रही है, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रहित की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। भारत सहित कई देशों ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है और वेनेजुएला की संप्रभुता एवं वहां के लोगों की सुरक्षा की वकालत की है। इस बीच, यह सवाल भी उठ रहा है कि किसी राष्ट्र पर हमला कर वहां के प्रमुख और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाने की अमेरिका की कार्रवाई क्या अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों का उल्लंघन नहीं है?

गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का लगातार आरोप लगाने के बाद शुक्रवार देर रात राजधानी काराकस पर हमला कर दिया था। इस दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयार्क ले जाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मादुरो के खिलाफ न्यूयार्क में मुकदमा चलाया जाएगा। यह कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया है। वर्ष 1965 में अमेरिका ने डोमिनिकन गणराज्य में बड़ी संख्या में अपने सैनिक भेजे, ताकि 1963 में तख्तापलट के तहत हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति जुआन बोश की वापसी को रोका जा सके। वर्ष 1989 में अमेरिकी सैनिकों ने पनामा पर धावा बोला, जिसका मकसद तत्कालीन जनरल मैनुअल नोरिएगा को हटाना था, जिन पर मादुरो की तरह ही मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप थे। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन के लंबे शासन का अंत कर दिया गया। इसी तरह वर्ष 2004 में हैती के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता से हटाकर अफ्रीका भेज दिया गया।

यह बात सही है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में मानव सुरक्षा का गंभीर संकट हो, तो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब यह सब अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों के दायरे में किया जाए। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी हस्तक्षेप की अक्सर निंदा की जाती थी, लेकिन इससे कभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वैधता को सीधे तौर पर खतरा महसूस नहीं हुआ। मगर पिछले कुछ दशकों से यह देखने में आया है कि कुछ शक्तिशाली देश वैश्विक मानव हित के बजाय अपने निजी स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई को भी कुछ देश इसी नजर से देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस खतरनाक चलन को लेकर गहरी चिंता जताई है, जिसे अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि विश्व में शांति एवं स्थिरता के वास्ते सभी देशों ने मिलकर जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए हैं, उनके महत्त्व और प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए संतुलित रुख बेहद जरूरी है।

कठघरे में उदारता

आमतौर पर जघन्य अपराधों के दोषी ठहराए गए कैदियों के प्रति गैरजरूरी और एक सीमा से ज्यादा नरमी बरतना न्याय की अवधारणा के अनुकूल नहीं माना जाता है। मगर हत्या और बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बावजूद किसी खास सजायाफ्ता कैदी के प्रति सरकार का रुख जब जरूरत से ज्यादा उदार दिखने लगे, तो स्वाभाविक ही यह सवाल उठता है कि आखिर कानून और सजा का मतलब क्या रह गया! गौरतलब है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर चालीस दिनों की पैरोल मिल गई। भले ही इस छूट के लिए सरकार की ओर से पेश दलीलों पर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन राम रहीम अगले चालीस दिनों तक जेल के बाहर रहेगा। दरअसल, अदालत में इस पैरोल मिलने के मसले पर हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वह कोई 'पेशेवर अपराधी' नहीं है और जेल में 'अच्छे चाल-चलन' वाला कैदी है।

सवाल है कि जिस कसौटी पर सरकार ने राम रहीम के प्रति लगातार उदारता दिखाई है, क्या वह यही पैमाना जेल में बंद जघन्य अपराधों के अन्य दोषियों के प्रति भी लागू करती है। दो डेरा साध्वियों से बलात्कार के मामले के अलावा राम रहीम को हत्या के अन्य मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है। मगर सजा काटने के लिए जेल में जाने से लेकर अब तक उसे पंद्रहवीं बार 'पैरोल' या फिर 'फरलो' पर बाहर आने की सुविधा मुहैया कराई गई है। अब तक वह कुल चार सौ दिन से ज्यादा वक्त तक जेल से बाहर रह चुका है। जघन्य अपराधों के दोषियों को लेकर कोई सरकार शायद ही कभी इस हद तक उदार होती है। सही है कि पैरोल एक कानूनी व्यवस्था है और इसके तहत कैदी को शर्तों के साथ जेल से कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है, लेकिन इस कानूनी प्रावधान का बेजा इस्तेमाल न्याय की अवधारणा पर चोट पहुंचाने से अलग नहीं है। सरकार को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कानूनों की मनमानी व्याख्या और पीड़ितों के प्रति न्याय की अवधारणा को चोट पहुंचाने को लेकर कैसे उदाहरण बन रहे हैं!

वेनेजुएला पर कार्रवाई से उठे सवाल

कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई का स्पष्ट विरोध किया है। मगर प्रचार की रणनीति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक भी पीछे नहीं है। समर्थन और विरोध से इतर यह सवाल अनुत्तरित रहेगा कि आखिर मादुरो पर ही यह कार्रवाई क्यों की गई!

पुष्परंजन

वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला और वहां के तात्कालिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एवं उनकी पत्नी को हिरासत में लेने के मामले में दुनिया एक बार फिर से बंट गई लगती है। कई देशों ने वेनेजुएला पर अमेरिका की इस कार्रवाई का स्पष्ट विरोध किया है। मगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का प्रचार करने की रणनीति भी पीछे नहीं है। समर्थन और विरोध से इतर यह सवाल अनुत्तरित रहेगा कि आखिर मादुरो पर ही यह कार्रवाई क्यों की गई! यदि नशीले पदार्थों की तस्करी ही उनका गुनाह-ए-अजीम है, तो इसको लेकर तो चीन पर भी सवाल उठते रहे हैं। देखा जाए तो वेनेजुएला के विपुल खनिज और तेल पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण, ट्रंप की नीयत को पूरी तरह से उजागर नहीं करता है।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव का यह सिलसिला पुराना है। वेनेजुएला में वर्ष 1999 में ह्यूगो शावेज के सत्ता संभालने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत हो गई थी। शावेज खुद को समाजवादी और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोधी बताते थे। उन्होंने अमेरिका को आंख दिखाते हुए क्यूबा और ईरान जैसे कई अमेरिकी विरोधी देशों से दोस्ती बढ़ाई। कहानियां यह भी गढ़ी जा रही हैं कि अमेरिका के हमले का मकसद उस 'स्वघोषित समाजवादी क्रांति' को खत्म करना है, जिसे मादुरो के राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 1999 में शुरू किया था। बात फिर नशीले पदार्थों की तस्करी पर आती है कि आखिर वह ऐसा कौन सा पदार्थ था, जिसकी वजह से अमेरिका की नींद हराम हो गई थी? यह गांजा, अफीम, चरस-हशीश, या हेरोइन नहीं, बल्कि सबसे घातक नशीला पदार्थ 'फेंटानिल' है। कहा जा रहा है कि इस पदार्थ की तस्करी ने अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली। इसने ट्रंप की आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी को तबाह कर दिया। कायदे से बहस फेंटानिल के मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन पर और ट्रंप के क्रिप्टो गोरखधंधे पर होनी चाहिए थी।

एक रपट के अनुसार, वर्ष 1999 से अब तक अमेरिका में लगभग दस लाख लोगों की इस नशीले पदार्थ की वजह से मौत हो चुकी है। वर्ष 2020 में नशीले पदार्थों से हुई मौत के कुल मामलों में से 82 फीसद फेंटानिल से जुड़े थे। 2022 में यह संख्या 107,941 पर पहुंच गई। 2025 तक अमेरिका में नशीले पदार्थों से होने वाली मौत की दर दोगुनी से ज्यादा हो गई, इसका मुख्य कारण फेंटानिल की बढ़ती तस्करी को माना गया है। दरअसल, फेंटानिल प्रयोगशाला में बनने वाला एक सिंथेटिक नशीला पदार्थ है, जो मार्फिन से 80-100 गुना और हेरोइन से पचास गुना ज्यादा घातक है। वैसे इसका नियंत्रित इस्तेमाल आमतौर पर अस्पतालों में दर्द कम करने के लिए किया जाता है। इसकी खरीद-फरोख्त के लिए 'डार्कनेट' का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। डार्कनेट बाजार वेब पर एक वाणिज्यिक वेबसाइट है, जिसके जरिए नशीले पदार्थ, हथियार, चोरी किया हुआ डेटा और नकली दस्तावेज का अवैध लेन-देन होता है।

उदाहरण के लिए, 'सिल्क रोड', जो वर्ष 2011 में बना, वह एक डार्कनेट बाजार था। यह बिटकाइन के शुरुआती उपयोगकर्ताओं में से कुछ का ठिकाना था। ज्यादातर डार्कनेट बाजार अमेरिकी कानून प्रवर्तन

एजंसियों से बचने के लिए अपने मंच पर फेंटानिल जैसे नशीले पदार्थों पर साफ तौर पर प्रतिबंध का संकेत देते हैं। बावजूद इसके, कई लोग फेंटानिल पर दिखाई जाने वाली पाबंदी से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। वर्ष 2020 की 'ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन' (डीइए) की रपट

> **अमेरिका के कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस नशीले पदार्थ से जुड़े लेन-देन में शामिल अधिकांश लोग आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करते हैं। कई अमेरिकियों को लगता है कि प्रवासी लोग ही उनके देश में फेंटानिल ला रहे हैं। मगर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फेंटानिल की तस्करी और अवैध बिक्री में प्रवासी लोग केवल पच्चीस फीसद और अमेरिकी नागरिक पचहत्तर फीसद शामिल हैं। अमेरिका का प्रशासन अपने ही घर में इसे रोक पाने में नाकाम रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए फेंटानिल की तस्करी के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।**

में चीन को फेंटानिल का शीर्ष उत्पादक देश बताया गया था। इस संस्था ने फेंटानिल उत्पादन की एक शृंखला का पता लगाया है, जिसमें खतरनाक रसायनों को अवैध रूप से लैटिन अमेरिकी देशों में भेजा जाता है, जहां उनका इस्तेमाल फेंटानिल बनाने के लिए किया जाता है। इसे बाद में बेचने के लिए अमेरिका ले जाया जाता है।

अमेरिका के कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस नशीले पदार्थ से जुड़े लेन-देन में शामिल अधिकांश लोग आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल करते हैं। कई अमेरिकियों को लगता है कि प्रवासी लोग ही उनके देश में फेंटानिल ला रहे हैं। मगर आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि फेंटानिल की तस्करी और अवैध बिक्री में प्रवासी लोग केवल पच्चीस फीसद और अमेरिकी नागरिक पचहत्तर फीसद शामिल हैं। अमेरिका का प्रशासन अपने ही घर में इसे रोक पाने में नाकाम रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए फेंटानिल की तस्करी के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इसका बड़े पैमाने पर विश्लेषण करने के लिए 'चैनालिसिस' ने चीन में सक्रिय फेंटानिल के घटक रसायनों के विक्रेताओं से जुड़े क्रिप्टोकरंसी पते की पहचान की। इनके पास वर्ष 2015 से अब तक 98 मिलियन डालर से ज्यादा की क्रिप्टोकरंसी का पता चला है। चैनालिसिस एक अमेरिकी ब्लाकचेन विश्लेषण फर्म है, जिसका मुख्यालय न्यूयार्क सिटी में है।

सबको इस बात की खलिश है कि भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की कार्रवाई को लेकर संतुलित बयान जारी क्यों किया। भारत ने रविवार को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने पर गहरी चिंता जताई और सभी पक्षों से क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की। मगर, हम एक घटना का विश्लेषण गहराई से करेंगे, तो बात समझ में आ जाएगी कि भारत के इस बयान के क्या मायने हैं। 18 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर एक सूचना जारी की गई कि 'फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में शामिल होने के कारण भारतीय कंपनी के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अमेरिकी वीजा रद्द।' दूतावास ने स्पष्ट किया कि ये व्यक्ति अमेरिका की यात्रा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। साथ ही कहा कि दूतावास उन कंपनियों से जुड़े अधिकारियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है, जिनके बारे में पता चला है कि उन्होंने फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी की है। फेंटानिल के प्रवाह को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। यह दिलचस्प है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी ही मादुरो का मुख्य गुनाह है, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे कि इस अवैध धंधे से उनकी कंपनी की क्रिप्टोकरंसी का कितना नुकसान हुआ है। एक हालिया रपट के अनुसार, वर्ष 2025 के आखिर में क्रिप्टो बाजार में गिरावट के कारण ट्रंप की कंपनी की कुल संपत्ति का मूल्य एक बिलियन डालर से ज्यादा कम हो गया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, इस परिवार की संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 7.7 बिलियन डालर से घटकर 6.7 बिलियन डालर रह गया और यह डिजिटल संपत्ति में गिरावट के कारण हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नशीले पदार्थ फेंटानिल के उत्पादन से जुड़े क्रिप्टोकरंसी-आधारित लेन-देन ने 'ट्रंप मेमेकाइन' को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप अपने इस दर्द को सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई करके एक तीर के साथ कई निशाने साधे हैं।

बाजार का संजाल

दुनिया मेरे आगे

मोनिका भाम्भू कलाना

वर्तमान समय बाजार का समय है। बाजार मनुष्य की सुविधाओं के लिए शताब्दियों से काम करता रहा है। वह मनुष्य के लिए एक जरूरी जरिया है, जिसमें वह अपनी जरूरत की चीजों का लेन-देन करता है। मगर आज यही बाजार किस तरह मनुष्य को अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बनने को विवश करने लगा है, कोई भी व्यक्ति इस साधारण-सी प्रक्रिया पर गौर नहीं करता। हर चीज में, स्थिति में व्यावसायिक अवसर तलाशने की बाजारी प्रवृत्ति ने बाजार को मानव समाज और उसकी संस्कृति के लिए एक ऐसे स्थायी खतरे में तब्दील कर दिया है, जिससे बचने के लिए हर संभव कदम उठाना आवश्यक हो गया है। बिना नियम, नैतिकता, भावना और संवेदना के बाजार मनुष्य को एक ऐसी कठपुतली के रूप में देखता है, जिसे जब चाहे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतम लाभ कमाने के लक्ष्य के साथ बाजार ने मानवीय जीवन के हर पहलू और पड़ाव में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। वह आपदा में अवसर देखने के आर्थिक दृष्टिकोण को मानते हुए ऐसी अंधी दौड़ में मनुष्य को धकेलता है, जिसका कोई अर्थ किसी के लिए नहीं होता।

बाजार हमें आखिर में यही कहता है कि खुद को महसूस करो, खुद की सुंदरता को पहचानो, चीजों को उसके बाह्य दृश्य से नहीं, भावना से परखो। बाजार यही बात सीधे-सीधे नहीं कहता, क्योंकि सीधे कहने से उसका काम नहीं चलता। वह मनुष्य को झूठे स्वप्न दिखाता है, उसमें हीनता पैदा करता है और भ्रमित करने वाली आकांक्षाएं उपजाता है। वह प्रचार के नारों के माध्यम से एक ऐसी हवा बनाता है, जिसमें व्यक्ति महसूस करता है कि वह जो है, वह खुद सही नहीं है। बाकी दूसरी चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। ऐसी हवा पैदा करके ही मनुष्य को दौड़ाया जा सकता है। बाजार 'जो हम हैं' से 'जो हमें होना चाहिए' की ओर लेकर जाता है। हमारे पास जो है, वह हमारे लिए पूरा नहीं है। दूसरे के पास जो है, वह उसके लिए पूरा नहीं है। इसलिए बाजार सबके लिए जरूरी हो जाता है। क्या आज के समय में हम इसे जरूरत तक सीमित कर सकते हैं?

अक्सर हम देखते हैं कि बाजार हमें सुरक्षा के नाम पर हमारी शिक्षा, नुस्खों, पुरातन तरीकों और जड़ों से अलग करता है और फिर उन्हीं चीजों को चलन बनाकर हम तक पहुंचाता है। हमारी दिनचर्या में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जहां लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक तत्त्वों की स्वीकार्यता के लिए बाजार द्वारा चालित सामयिक फैशन की तरफ देखते हैं। इसी वजह से यह संभव होता है कि बाजार उन पुरानी चीजों को, जिन्हें मनुष्य समय के प्रवाह में कई-कई बार छोड़ चुका है, उन्हें भी फैशन के नाम पर चला देता है। अधिकतर लोगों के पास चीजों को देखने का कोई विशेष ढंग नहीं होता, वे दूसरों की हां में हां मिलाते हैं।

हमारे समाज की पूरी मानसिकता 'दूसरे क्या कहेंगे' पर टिकी हुई है, लेकिन जब सब एक जैसा ही हो, तो दूसरे के कहने के लिए कुछ बचता ही कहां है! हम अपने पैसे खर्च करके इसी तरह बाजार का गुणगान भी करते हैं। हम दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह होना चाहते हैं, बाजार सभी को एक सम धरातल पर ले आता है, लेकिन ऐसा कर-के वह उसे व्यक्ति से उपभोक्ता में तब्दील करता है। उपभोक्ता की कोई निजी पसंद नहीं होती और उसका कोई निर्णय नहीं होता। वह उन चीजों का उपभोग करता है, जो उसके लिए बनाई जाती है। इस तरह इस समानता की कीमत अपने व्यक्तित्व और विविधता को खोने के रूप में सभी चुकाते हैं, लेकिन तब भी कोई बेचैनी व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि इस बेचैनी को, सोचने की क्षमता को नष्ट करके ही ये सब चीजें जगह बनाती है। बाजार मनुष्य को उपभोक्ता बनाकर उसकी मूल पहचान को ही एक तरह से संकट में डाल देता है।

> **हम अपने पैसे खर्च करके बाजार का गुणगान भी करते हैं। हम दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह होना चाहते हैं। बाजार सभी को एक सम धरातल पर ले आता है, लेकिन ऐसा करके वह उसे व्यक्ति से उपभोक्ता में तब्दील करता है। उपभोक्ता की कोई निजी पसंद नहीं होती और उसका कोई निर्णय नहीं होता!**

मनुष्य की अस्मिता उसकी बुद्धि, विचारशीलता, नैतिकता और विवेक से बनती है। वह केवल अपने सही-गलत के बारे में ही नहीं पर्यावरण और अन्य प्राणियों के बारे में भी सोच सकता है और सोचता रहा है। संस्कृति और समाज के साथ ही अन्य जैविक-अजैविक सत्ताओं के प्रति उसका दायित्व ही उसे मनुष्य बनाता है। मगर उपभोक्ता बनाकर बाजार मनुष्य के विवेक, विचार, व्यवहार और भावों को नियंत्रित करता है। वह मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों में बदलाव करता है और मनुष्य को उसकी गरिमा से स्खलित कर एक ऐसे पुतले में बदल देता है, जिसे अपने स्वार्थ के अनुसार चलाना संभव होता है। व्यक्ति, व्यक्तिगत नहीं होकर भीड़ का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। अकेले व्यक्ति को नियंत्रित करना जितना मुश्किल है, उसे भीड़ का हिस्सा बनाकर नियंत्रित करना उतना ही आसान है।

बाजार हमारी जरूरतों को संचालित करने वाले केंद्र से कब 'बाजारवाद' की तरफ झुकने लगता है और कब हम बाजारीकरण की प्रक्रिया की गिरफ्त में आने लगते हैं, इन बिंदुओं को समझे बिना हम बाजार के प्रभाव का सही आकलन नहीं कर सकते हैं। जब हम बाजार से परे मानवीय अस्तित्व को समझ पाएंगे, तभी अपने ही बनाए खिलौने के हाथों मनुष्य के कैद होने की त्रासदी को सही मायने में महसूस कर पाएंगे।

गुणवत्ता के बजाय

देशभर के छोटे-बड़े तमाम शहरों और महानगरों में पेयजल की शुद्धता को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं। अधिकांश स्थानों पर पेयजल की लाइनें जमीन के भीतर दबी होती हैं और जब तक कहीं बड़ा रिसाव न हो, उनकी निगरानी नहीं होती है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण मकानों और बहुमंजिला इमारतों की सीवर लाइनें भी भूमिगत पाइपों के माध्यम से ही डाली जा रही हैं। कई बार निर्माण एजंसियां और ठेकेदार लागत बचाने के लिए घटिया गुणवत्ता के पाइप लगाते हैं या नियमों की अनदेखी कर सीवर-नालों की लाइनों को गलत ढंग से जोड़ देते हैं। नतीजा गंदा पानी पेयजल लाइनों के आसपास जमा होकर उनमें मिल जाता है। इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। अब आवश्यकता है कि राज्य सरकारें अपनी पेयजल नीतियों की समीक्षा करें और पेयजल पाइप लाइनों को रिसाव-मुक्त रखने के लिए ठोस और सख्त नियम बनाएं। विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में बने मकानों और बहुमंजिला भवनों की सीवर व्यवस्था की अनिवार्य जांच होनी चाहिए।

- अरविंद रावल, झाबुआ, मप्र

जरूरत और सावधानी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए कई चीजें दी हैं। मगर इनका सावधानी से इस्तेमाल न करें, तो यह हमारे लिए कभी भी खतरनाक बन सकती हैं। सर्दियों में गैस गीजर और गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण प्रायः लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। इन दिनों नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। मगर इसके इस्तेमाल में जरा-सी भी असावधानी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। गैस सिलेंडर स्नानागार से बाहर ही रखें। वहीं बंद कमरे में अंगीठी जला कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना जान पर भारी पड़ सकता है। बिजली से चलने वाले गीजर, हीटर गर्म हवा फेंकने वाले उपकरण का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल घर, दफ्तर और अन्य जगहों पर जरूरत अनुसार ही करना चाहिए।

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

अंधविश्वास का सिरा

'अंधविश्वास की मार' (संपादकीय, दो दिसंबर) पढ़ा। अंधविश्वास की जड़ें आज भी समाज में कितनी गहराई से जुड़ी हैं, इसके प्रमाण समय- समय पर सामने आते रहते हैं। आज कई घटनाएं रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि जागरूकता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद कहीं न कहीं हम अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कुप्रथाएं आज भी कायम हैं। यह दुखद ही है कि अंधविश्वास में डूबी भीड़ घर में घुस कर किसी भी निर्दोष को मार डालती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव निजी तौर पर हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जनमानस को यह समझना होगा कि अंधविश्वास को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, इसे उखाड़ फेंकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। अंधविश्वास की जड़ें विकास क्रम को अवरुद्ध करती हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए।

- साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

सुधार के सामने

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों के जीवन स्तर में समुचित सुधार नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर यह कई बार कहा जा चुका है कि सुधारों को लेकर भारत 'रिफार्म एक्सप्रेस' पर सवार हो चुका है। इसका मुख्य इंजन देश की जनसंख्या, युवा शक्ति और नागरिकों का अदम्य साहस है। सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन, उद्यमियों को नवाचार की स्वतंत्रता और संस्थानों को भरोसेमंद एवं पारदर्शी बनाना है। बीते साल 2025 के सुधार न केवल उनके व्यापक दायरे में महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि नवाचार और सहयोग पर जोर है। इसमें नियंत्रण और नियमन की जगह सुविधा और सहयोग को प्राथमिकता दी गई। इन सुधारों का उद्देश्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है। कई क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए नौकरशाही में प्रत्येक स्तर पर सुधार किया जाना चाहिए।

- युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

आइआरसीटीसी : लालू की याचिका पर सीबीआइ से मांगा गया जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आइआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सोमवार को सीबीआइ से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फिलहाल मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच एजंसी के जवाब पर गौर किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से यादव की याचिका और रोक के आवेदन पर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की। हाई कोर्ट ने मामले में निचली अदालत से रिकार्ड भी मांगा। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान लालू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह ने कहा कि वे निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं और एक महीने में दो गवाहों से जिरह की जा चुकी है। अदालत ने कहा कि वह सीबीआइ से जवाब मिलने के बाद 14 जनवरी को मामले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगी।

अदालत ने सीबीआइ से यादव की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'उन्हें जवाब दाखिल करने दें। आपको पहले आना चाहिए था, आप नहीं आए। इससे पहले ही निचली अदालत आदेश पारित कर चुकी थी।' सीबीआइ के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। निचली अदालत ने 13 अक्तूबर, 2025 को इन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे।

पूर्व रेल मंत्री ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के दो होटलों के परिचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

'कट आफ' ज्यादा तो सामान्य श्रेणी का हकदार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-आफ से ज्यादा नंबर लाते हैं, तो वे सामान्य श्रेणी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के योग्य होंगे। देश में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन में इस फैसले का दूरगामी असर होने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आरक्षण की श्रेणी में आने वाले मेधावी उम्मीदवारों की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले के साथ ही सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की सीटों का मतलब भी नए सिरे से परिभाषित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दायर मामले में सुनाया है। जिसमें एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में यह नियम निर्धारित किया गया था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, चाहे उनके अंक सामान्य कट-आफ से अधिक क्यों न हों।

पीठ ने कहा है कि लिखित परीक्षा में अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-आफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे इंटरव्यू में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। लेकिन, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसे किसी उम्मीदवार का कट-ऑफ सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से कम रहता है तो वह अपनी आरक्षित श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण का फायदा उठाने के योग्य होगा।

राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दलील दी गई थी कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सामान्य सीट भी लेने दिया जाएगा तो इससे उन्हें दोहरा फायदा मिल जाएगा। जिसमें एक आरक्षण के माध्यम से होगा और दूसरा सामान्य श्रेणी के माध्यम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन और उसके रजिस्ट्रार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि योग्यता को उसका उचित महत्त्व देना होगा।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले पर ऐतिहासिक फैसले का भी हवाला दिया। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा- हम मानते हैं कि ओपन शब्द का सीधा अर्थ है ओपन। खुली श्रेणी की सीट किसी भी खास जाति या समूह के लिए आरक्षित नहीं है। यह सभी के लिए है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आरक्षण की उपलब्धता की वजह से एससी, एसटी, ओबीसी या इडब्ल्यूएस श्रेणी के किसी योग्य उम्मीदवार को शुद्ध मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट से चुने जाने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किया है।

पीठ ने कहा है कि लिखित परीक्षा में अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-आफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे इंटरव्यू में सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। लेकिन, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐसे किसी उम्मीदवार का कट-ऑफ सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ से कम रहता है तो वह अपनी आरक्षित श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण का फायदा उठाने के योग्य होगा।

हल्द्वानी : युवक की हत्या, भाजपा पार्षद हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 5 जनवरी।

उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पार्षद ने कथित रूप से गोली मार कर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

घटना के सामने आने के बाद भाजपा ने बिष्ट को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हल्द्वानी के नगर पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि घटना रविवार देर रात करीब साढ़े 11 बजे जज फार्म क्षेत्र में तब हुई जब अपने दोस्त कमल भंडारी के साथ कहीं से वापस आ रहा नितिन लोहनी (22) पार्षद के बेटे से मिलने उसके घर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजाई। उन्होंने बताया कि दरवाजा खुलते ही पार्षद बिष्ट बाहर आया और उसने लोहनी पर कथित रूप से गोली चला दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने से घबराया उसका मित्र भंडारी मौके से भाग गया।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोहनी को तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। इस बीच, मृतक के परिजनों ने पुलिस में पार्षद के खिलाफ तहरीर दी है। इधर, मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने पार्षद अमित बिष्ट को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

सुरक्षा गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित पोत की जानकारी लेते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

'समुद्र प्रताप बढ़ते सामर्थ्य का प्रतीक'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (आइसीजी) के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को बल में शामिल किया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान कहा कि 'समुद्र प्रताप' भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री क्षेत्र में बढ़ते सामर्थ्य का प्रतीक है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया का असली मतलब ऐसी परियोजनाओं में दिखाई दे रहा है। सिंह ने कहा कि इतने जटिल प्लेटफार्म के बावजूद हमने स्वदेशी सामग्री का यह स्तर हासिल किया है, जो दर्शाता है कि हमारा रक्षा औद्योगिक परिवेशी तंत्र अब काफी परिपक्व हो चुका है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में समुद्री प्रदूषण एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरता हुआ देखा गया है। यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे समुद्री प्रदूषण बढ़ेगा, इसका असर मछुआरों की आजीविका, तटीय समुदायों के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा पर पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और आईसीजी के महानिदेशक परमेश शिवमणी उपस्थित थे।

आईसीजी के अनुसार, यह पोत पूरी तरह से भारत में परिकल्पित, डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा निर्मित 114.5 मीटर लंबे इस पोत में 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 4,200 टन वजन वाला यह पोत 22 समुद्री मील से अधिक गति से चल सकता है और 6,000 समुद्री मील का सफर तय कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी 11 को सोमनाथ मंदिर जाएंगे

नई दिल्ली, 5 जनवरी (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी आक्रमणकारियों के बार-बार हमलों के बाद पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अवसर पर सोमनाथ में वर्षभर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई गई है।

भाजपा ने महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पहले विध्वंस की 1,000वीं बरसी पर कहा कि यह दिन ये याद रखने और समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू और वामपंथी इतिहासकारों ने मुस्लिम आक्रमणकारी को केवल एक 'लुटेरा' बताकर और यह दिखाकर कि वह 'धार्मिक कट्टरपंथी' नहीं था, इतिहास को विकृत किया।

राम रहीम को 15वीं बार पैरोल मिलने पर विपक्ष ने मुद्दा उठाया, पूछा

उमर और शरजील को क्यों नहीं मिली जमानत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

विपक्ष के कुछ नेताओं ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत से इनकार किए जाने पर सोमवार को सवाल खड़े किए और कहा कि पांच साल से जेल में बंद लोगों को जमानत नहीं मिल रही, लेकिन बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दी जा रही है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सांसद जान ब्रिटास ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'यह सिद्धांत कि 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' कुछ खास व्यक्तियों के मामले में स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता।' ब्रिटास ने कहा, 'उमर खालिद को कोई जमानत नहीं मिल रही, कठोर यूएपीए कानून के तहत 5 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, जबकि मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है।'

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि जमानत से इनकार करने से कुछ परेशान करने वाले सवाल खड़े होते हैं। अदालतों के पास ऐसे मामलों में जमानत देने की शक्ति है और वास्तव में उनका कर्तव्य भी है जहां कारावास अनावश्यक रूप से लंबा, अनुचित हो जाता है।

उन्होंने कहा, 'इस बीच, बलात्कार के दोषी और हत्यारे गुरमीत राम रहीम सिंह (2017 में सजा सुनाई गई) को अभी 40 दिन की और पैरोल दी गई है, सजा के बाद जेल से उनकी 15वीं अस्थायी रिहाई। एक को बिना मुकदमे के अनिश्चित काल तक जेल में रखा जाता है। दूसरे को बार-बार जेल से छुट्टियों का आनंद मिलता है। माकपा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जमानत से लगातार इनकार स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसने आरोप लगाया कि असहमति को कुचलने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का इस्तेमाल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने कहा कि फिर भी, उमर खालिद और शरजील के मामले में न्यायिक दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि जेल में पहले ही बिताया गया समय अभी भी पर्याप्त लंबा नहीं है और मुकदमे में देरी अभी भी चौंकाने वाली या असंवैधानिक नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री से की मुलाकात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

योगी आदित्यनाथ के तीनों नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।

योगी आदित्यनाथ ने भी 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री से मुलाकात की एक साझा करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। वहीं, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर आए योगी आदित्यनाथ के तीनों नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।

पेज 1 का बाकी

राम रहीम को पैरोल के सवाल पर कन्नी काट गए नायब सैनी

के बाद 15वीं पैरोल है। राम रहीम साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में 20 साल और उम्रकैद की सजा काट रहा है। पैरोल मिलने के बाद वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हो गया।राम रहीम को पैरोल मिलने पर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हैं।

इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री नायब सैनी से प्रेस कांफ्रेंस में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि ये अदालत का मामला है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस को अचानक खत्म कर दिया और वहां से चले गए। इसी दौरान जब उनसे अरावली के बारे में पूछा तो उन्होंने इस सवाल को भी टाल दिया। इससे पहले भी पैरोल के मुद्दों पर मुख्यमंत्री सैनी और भाजपा नेताओं ने कहा है कि इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि डेरा प्रमुख के अनुयायियों का राजनीतिक प्रभाव हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में काफी है, जिस वजह से पैरोल के फैसले पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि पैरोल जेल नियमों के तहत दी जाती है।

उमर, शरजील को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

की धारा 43डी (5) का हवाला दिया, जिसके अनुसार यदि किसी मामले की 'डायरी' या आरोपपत्र की जांच करने पर न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए उचित आधार मिलते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तो न्यायालय को जमानत देने से इनकार करना होगा।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर अपेक्षित एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया साजिश में उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका का प्रमाण मिलता है। पीठ ने कहा कि सामग्री से 'साजिश, लामबंदी और रणनीतिक दिशा-निर्देश के स्तर पर भागीदारी का संकेत मिलता है, जो छिटपुट या स्थानीय कृत्यों से कहीं आगे तक फैला है'। इसके अलावा, यूएपीए की धारा 43डी (5) के तहत यह वैधानिक सीमा इन अपीलकर्ताओं के संबंध में लागू होती है। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान के अनुसार, यदि मामले की डायरी या संहिता की धारा 173 के तहत बनाई गई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर न्यायालय की यह राय हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो ऐसे आरोपी व्यक्ति को जमानत पर या स्वयं के निजी मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब अभियोजन सामग्री प्रथम दृष्टया अपराध को उजागर करती है, तो वैधानिक प्रतिबंध प्रभावी होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है, तो स्वतंत्रता प्रभावी होनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को यह कहते हुए जमानत दे दी कि दे दी कि हर आरोपी की भूमिका का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया है और सामूहिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यद्यपि यूएपीए मामलों में जमानत देना नियमित प्रक्रिया नहीं है, फिर भी कानून के तहत जमानत देने से इनकार करना अनिवार्य नहीं है और यह कानून जमानत देने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित नहीं करता। इमाम को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिए गए भाषणों के लिए 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अगस्त 2020 में उसे एक बड़े षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया। खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया था कि खालिद, इमाम और अन्य लोगों ने 'शांतिपूर्ण विरोध' की आड़ में 'सत्ता परिवर्तन अभियान' चलाकर देश की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करने की साजिश रची थी।कथित अपराधों में देश को अस्थिर करने का जानबूझकर प्रयास शामिल था, जिसके लिए 'जमानत नहीं बल्कि जेल' की सजा होनी चाहिए।

पुलिस ने कहा था कि उसने आरोपियों के खिलाफ प्रत्यक्ष, दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए हैं जो सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रव्यापी दंगों को भड़काने में उनकी अंतर्निहित, गहरी और प्रबल संलिप्तता को दर्शाते हैं। पुलिस ने 900 गवाहों के कारण मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं होने के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि यह बयान न केवल समय से पहले दिया गया है, बल्कि जमानत प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया एक 'भ्रमित करने वाला' बयान भी है।

पुनरीक्षण : संघर्ष कर रहे बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांग

नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई। दूसरे चरण की शुरुआत 27 दिसंबर को हुई, जिसमें 1.67 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच हो रही है। इनमें से 1.36 करोड़ को तार्किक विसंगतियों के कारण चिह्नित किया गया है और 31 लाख के रेकार्ड में समस्या है।

पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा ब्लाक में 87 वर्षीय स्नेहलता भक्त 32 किलोमीटर की यात्रा के बाद एसआइआर कार्यालय पहुंचीं। उनकी नाजुक हालत देख ब्लाक विकास अधिकारी बाहर आए, दस्तावेजों की जांच की और उन्हें वाहन में लौटने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, मैं क्यों इतना पैसा खर्च करूं और कष्ट सहूं, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं एक मतदाता हूं? पास ही में गंभीर रूप से बीमार और चलने में असमर्थ 65 वर्षीय झरना दास को उनके भाई कंधे पर उठाकर सुनवाई केंद्र में लाए। उन्होंने कहा, अगर हम नहीं आते, तो उनका नाम हटा दिया जाता। इस डर के कारण हमें लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।जन्म से दृष्टिबाधित दीपांकर दास का नाम 2002 की मतदाता सूची में था। उन्होंने कहा, मैं देख नहीं सकता, मैं बहुत ध्यान से चलता हूं। फिर भी, मुझे आना पड़ा। साउथ कोलकाता के गरफा में एक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने 2002 की सूची में अपना नाम गायब होने के बाद लगभग 150 किलोमीटर यात्रा की।

उन्होंने कहा, अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार किया। लेकिन इस उम्र में इतनी लंबी यात्रा करना बहुत मुश्किल है।दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को इस सुनवाई के लिए अपना काम छोड़ना पड़ा है। नारायणगढ़ के एक मिस्त्री श्यामल कोटल ने सुनवाई में शामिल होने के लिए काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार का गुजारा मेरी दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। लेकिन अगर मेरा नाम हटा दिया जाता, तो वह इससे भी बुरा होता। पुरुलिया के बलरामपुर में, जन्म से 80 फीसद दिव्यांग श्याम सिंह सरदार को सुनवाई में बुलाए जाने के बाद ब्लाक कार्यालय के फर्श पर रेंगते हुए पहुंचना पड़ा। वहां कोई वीलचेयर उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा, कम से कम हम जैसे लोगों के लिए घर पर सुनवाई की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यह असहनीय उत्पीड़न है। हुगली के तारकेश्वर में 72 वर्षीय एक व्यक्ति सुनवाई पर जाने के दौरान गिर पड़े और सिर में चोट लग गई।

एक ओर निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों में घर पर सुनवाई और छूट दी गई है, फिर भी संवेदनशील मतदाताओं को बुलाए जाने के मामले बार-बार सामने आने से कार्यान्वयन में खामियां उजागर हुई हैं। इस दौरान परिवारों को मौखिक आश्वासन मिलता है लेकिन लिखित नोटिस में भौतिक रूप से पेश होने के लिए कहा जाता है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन मुद्दों को उठाते हुए आरोप लगाया कि एसआइआर के कारण वास्तविक मतदाता 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट देने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि, भाजपा का कहना है कि यह पुनरीक्षण मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

मादुरो ने कहा- मैं निर्दोष, अपने देश का राष्ट्रपति हूं

करके लाया गया।' इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने उन्हें पकड़ने और न्यूयार्क लाने के कदम को उचित ठहराने के लिए किया था। मादुरो दोपहर के आसपास एक संक्षिप्त, लेकिन आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए, जिससे संभवतः इस बात पर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि क्या उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार तड़के ब्रुकलिन जेल से सशस्त्र सुरक्षा के तहत ले जाया गया, जहां उन्हें मनहट्टन कोर्टहाउस में हिरासत में रखा गया है।

मादुरो के वकीलों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को इस तर्क के साथ चुनौती दिए जाने की उम्मीद है कि एक संप्रभु राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें अभियोजन से छूट प्राप्त है। इससे पहले, अमेरिका ने जोर देकर कहा था कि वह वेनेजुएला के साथ औपचारिक रूप से युद्ध में नहीं है, भले ही सैन्य हमलों के बाद तनाव बढ़ गया था।

गुजरात : आइएएस अधिकारी रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

गुजरात सरकार ने रिश्वत से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी ने दो जनवरी को 2015 बैच के आइएएस अधिकारी पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें सात जनवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि हिरासत की अवधि 48 घंटे से अधिक होने के कारण पटेल को निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है, 'इसलिए अब पटेल को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम- 1969 के नियम 3 के उपनियम दो के तहत अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन दो जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।'

पटेल को दो जनवरी को सुरेंद्रनगर के जिलाधिकारी पद से उस समय बिना किसी नई तैनाती के स्थानांतरित कर दिया गया था, जब ईडी ने उनके कार्यालय में कार्यरत उप मामलतदार (राजस्व अधिकारी) चंद्रसिंह मोरी को रिश्वतखोरी के आरोपों से उपजे धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय एजंसी ने पटेल, मोरी और अन्य आरोपियों से संबंधित धनशोधन मामले की जांच शुरू की है। इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएल) के तहत एक प्रवर्तन मामला सूचना रपट (ईसीआइआर) दर्ज की गई है।

नैसकाम के सह-संस्थापक हरीश मेहता ने कहा

उद्योग जगत का लक्ष्य, अगले दशक तक 10 करोड़ नौकरियां

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

उद्योग जगत के दिग्गजों के एक समूह ने सोमवार को हंड्रेड मिलियन जाब्स (10 करोड़ नौकरियां) नामक एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य आगामी दशक में भारत में 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना है, क्योंकि देश तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद अपर्याप्त रोजगार की समस्या से जूझ रहा है।

आयोजकों ने एक बयान में कहा कि इस मुहिम की घोषणा साफ्टवेयर उद्योग निकाय नैसकाम के सह-संस्थापक हरीश मेहता, वैश्विक उद्यमी नेटवर्क 'द इंडस एंटरप्रेन्योर्स' (टीआइइ) के संस्थापक एजे पटेल और सेंटर फार इनोवेशन इन पब्लिक पालिसी (सीआइपीपी) के संस्थापक के यतीश राजावत ने की। संस्थापकों ने कहा कि भारत में कार्यशील आयु की जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 1.2 करोड़ की दर से बढ़ रही है, जबकि विनिर्माण जैसे पारंपरिक रोजगार के साधन विस्तार करने में संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नए कार्यबल को खपाने और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए देश को हर साल 80 से 90 लाख नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बाद भी भारत में रोजगार की वृद्धि दर उत्पादन विस्तार की तुलना में पीछे रही है।

स्वचालन और कृत्रिम मेधा (एआइ) व्यापार के तौर-तरीकों को बदल रहे हैं और कई क्षेत्रों में शुरुआती स्तर के पदों को कम कर रहे हैं। ऐसे में यह चिंता बढ़ गई है कि आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन से पूरी तरह कट सकती है।

नवंबर 2025 में 4.7 फीसद घटी थी बेरोजगारी दर

नवंबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 4.7 फीसद हो गई, जो अक्तूबर 2025 के 5.2 फीसद और अप्रैल 2025 (5.1फीसद) के बाद से सबसे निचला स्तर है, जो मजबूत श्रम बाजार, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और महिला भागीदारी में वृद्धि को दशार्ता है, जहां दरें भी गिरीं, जिससे मजबूत आर्थिक विकास के बीच रोजगार सृजन के अच्छे संकेत मिले हैं। यह गिरावट ग्रामीण रोजगार में वृद्धि और सेवा क्षेत्र में शहरी मांग में सुधार से प्रेरित है महिला श्रम बल भागीदारी दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक अच्छा कदम है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा

सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना आर्थिक नजरिए से जरूरी

जयपुर, 5 जनवरी (भाषा)।

ईरानी ने जयपुर में आयोजित 'राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026' को किया संबोधित।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना सामाजिक के साथ आर्थिक नजरिए से भी जरूरी है। ईरानी ने यहां आयोजित 'राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट 2026' को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को सफलता के शिखर पर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय का दायित्व संभाल चुकीं ईरानी ने स्पार्क पहल का उल्लेख भी किया जिसका उद्देश्य 300 शहरों में एक लाख महिला उद्यमियों को ऋण, औपचारिकता और संस्थागत सहयोग तक पहुंच उपलब्ध कराना है। सम्मेलन के दूसरे दिन एक अभियान की शुरुआत भी हुई, जिसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमइ) को आर्थिक वृद्धि और रोजगार के प्रमुख चालक के रूप में मजबूत करना है। टाई के मुताबिक, यह पहल अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां और 100 अरब डालर से अधिक का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है। इसके लिए सरकारों, उद्योग संगठनों, पूंजी प्रदाताओं और विश्वभर के टाई चेप्टर को जोड़ा जाएगा।

मुख्य फोकस क्षेत्रों में नियामकीय सरलीकरण, पूंजी तक पहुंच, कौशल विकास, तकनीक अपनाना और क्लस्टर-आधारित क्षेत्रीय विकास शामिल हैं। एमएसएमई पर केंद्रित एक अन्य सत्र में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने स्थिर नियमों, बेहतर ऋण उपलब्धता और प्रौद्योगिकी-आधारित क्लस्टर विकास की भूमिका पर चर्चा की।

हिमाचल सीमा पर बनेगा 'हिम चंडीगढ़' शहर : सुक्खू

शिमला, 5 जनवरी (ब्यूरो)।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ और हिमाचल की सीमा पर सोलन जिले के बद्दी इलाके के शीतलपुर में बनने वाली नई विश्व स्तरीय शहर (टाउनशिप) का नाम हिम-चंडीगढ़ होगा। सुक्खू ने बताया कि शहर बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मंत्रिमंडल की उप-समिति बनाई गई थी और उसकी रपट मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर ली है।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि 'हमने हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर एक नया शहर बनाने का फैसला किया है और इसका नाम हिम-चंडीगढ़ होगा।' तीन पंचायतें भूमि अधिग्रहण के जरिए शहर के लिए ज़मीन देने को तैयार हैं और मंत्रिमंडल ने पहले ही 3,400 बीघा जमीप आवासीय विकास विभाग को देने की की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में और जमीन अधिग्रहण की जाएगी और शहर में विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।

इससे पहले, 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उद्योग, संसदीय कार्य एवं श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा था कि चंडीगढ़ के पास शहर परियोजना के लिए और निजी या जंगल की जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी।

पंजाब : बेअदबी विधेयक की समय-सीमा होने वाली है खत्म

छह माह में भी रपट प्रस्तुत नहीं कर पाई चयन समिति

चंडीगढ़, 5 जनवरी (ब्यूरो)।

पंजाब विधानसभा की चयन समिति को सौंपा गया 'पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक-2025' (बेअदबी विधेयक) अपनी छह माह की निर्धारित समय-सीमा से चूकता दिखाई दे रहा है। समिति की ओर से अब तक रपट प्रस्तुत नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद 15 जुलाई 2025 को इस विधेयक को 15 सदस्यीय चयन समिति को भेजा गया था। समिति को हितधारकों, धार्मिक संस्थाओं और आम जनता से परामर्श कर छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें देने का दायित्व सौंपा गया था। यह अवधि जनवरी के मध्य तक समाप्त हो रही है, लेकिन अभी तक रपट सदन में प्रस्तुत नहीं की गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने के तुरंत बाद 15 जुलाई 2025 को इस विधेयक को 15 सदस्यीय चयन समिति को भेजा गया था।

चयन समिति के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं। सभी हितधारकों से बातचीत हो चुकी है। धार्मिक संगठनों, वकीलों, बुद्धिजीवियों सहित अनेक लोगों से चर्चा की गई है। अब हम नौकरशाहों के साथ बैठक करेंगे। समय-सीमा चूकने के प्रश्न पर उन्होंने कहा, 'मैं इतना ही कह सकता हूं कि रपट यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। जब तक चयन समिति अपनी रपट प्रस्तुत नहीं करती, तब तक विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा या इसे पारित नहीं किया जा सकता। चयन समिति के दायरे में पूरे राज्य में परामर्श बैठकें आयोजित कर प्रस्तावित कानून पर विचार जुटाना शामिल था। यह विधेयक पवित्र ग्रंथों की बेअदबी के मामलों में कड़े दंड का प्रावधान करता है।

रविवार को आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने कहा कि सरकार शीघ्र ही बेअदबी विधेयक लाएगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता लगातार धरना दे रहा है और सरकार से विधेयक को शीघ्र पारित कर कानून बनाने की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि बार-बार हो रही देरी से जनभावनाएं आहत हुई हैं, विशेषकर बेअदबी से जुड़े मामलों में। आप सरकार का कहना है कि वह सभी प्रमुख धर्मों के प्रति समान सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करना चाहती है।

अभ्यास जयपुर में सेना दिवस समारोह से पहले पूर्वाभ्यास करते हुए भारतीय सेना के जवान।

ईरोड में हल्दी की जांच के लिए बनेगी प्रयोगशाला : कृषि मंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जनवरी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईरोड में हल्दी की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) को निर्देश देते हुए कहा कि इससे हल्दी की गुणवत्ता जांच, प्रमाणीकरण और बेहतर विपणन में किसानों को सहायता मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इससे हल्दी किसानों की नीतिगत सहयोग, बाजार तक बेहतर पहुंच होगी और निर्यात के नए अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, ईरोड क्षेत्र में भंडारण की भी जरूरत है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत स्थापित किए जा सकते हैं।

'जी राम जी' कानून गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस पहल

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को तमिलनाडु के ईरोड में कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून, स्वावलंबी गांवों के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। कामगारों और श्रमिकों से संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून गांवों में रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में बदलाव पर विचार करे सरकार

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को 'कर्मचारी भविष्य निधि' (ईपीएफ) योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर चार महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया। याचिका के अनुसार, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' (ईपीएफओ) इस योजना में 15,000 रुपए से अधिक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा

बुनियादी ढांचे पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश

पटना, 5 जनवरी (भाषा)।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार में इस समय राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति (पीएमजी) पोर्टल पर राज्य में कुल 170 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिनमें कुल 7.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना, स्वास्थ्य तथा अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जो क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक-आर्थिक विकास में बिहार की बढ़ती भूमिका को दर्शाती हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही है।

चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, बिजली, तेल एवं गैस, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना, स्वास्थ्य तथा अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

भूमि अधिग्रहण, वैधानिक स्वीकृतियों, कानून-व्यवस्था प्रबंधन तथा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और परियोजना एजंसियों के साथ समन्वय के जरिए समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से जुड़ी लगभग 96 फीसद समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। चौधरी ने कहा कि कुल 170 परियोजनाओं में से 60 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी हैं। इनमें 1,28,095 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।

वहीं 110 परियोजनाएं, जिनमें 5,30,094 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, वर्तमान में निर्माण अथवा कार्यान्वयन के चरण में हैं। इस प्रकार लगभग 65 फीसद परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, जो राज्य में निरंतर अवसंरचना विस्तार को दर्शाता है।

सोना 960 रुपए बढ़ा, चांदी में आई 2,600 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच मजबूत वैश्विक रुख को देखते हुए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 960 रुपए बढ़कर 1,40,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को 99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 1,39,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी की कीमतों में भी सोमवार को तेजी जारी रही और यह 2,600 रुपए बढ़कर 2,44,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई। शुक्रवार को चांदी 2,41,400 रुपए प्रति किलोग्राम रही थी। व्यापारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना और चांदी दोनों में तेजी आई।

दो घंटे भर्ती रहने पर अस्पताल ने बनाया 80 हजार रुपए का बिल | अमानवीय | शिकायत पर एसएसपी ने दिलाया शव

बिल भुगतान न होने पर अस्पताल का शव देने से इनकार

हल्द्वानी, 5 जनवरी (भाषा)।

उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक निजी अस्पताल ने एक महिला को उसकी मौत से पहले केवल दो घंटे भर्ती रहने का न केवल 80 हजार रुपये का बिल बना दिया बल्कि भुगतान न होने पर परिजनों को उसका शव सौंपने से भी इनकार कर दिया । पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार अल्मोड़ा जिले की सीमा बिरोड़िया (65) को एक जनवरी को गुर्दे की बीमारी के इलाज के लिए यहां एक अस्पताल लाया गया था जहां से अगले दिन चिकित्सकों ने उसे उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे यहीं एक अन्य अस्पताल ले गए जहां दो घंटे चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने बताया कि दूसरे अस्पताल ने उन्हें दो घंटे के इलाज का 80 हजार रुपए का बिल थमा दिया और जब उन्होंने इतने पैसे न होने की बात कही तो उन्होंने उन्हें शव सौंपने से इनकार कर दिया । परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसी तरह से रिश्तेदारों से मांगकर 57,000 रुपए जुटाकर दिए लेकिन अस्पताल प्रबंधन का दिल फिर भी नहीं पसीजा। परिजनों ने दावा किया कि अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को उनकी कार तक अपने पास रख लेने की भी धमकी दी जिसके बाद उन्होंने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजूनाथ टीसी से मदद मांगी। इस संबंध में मंजूनाथ ने बताया कि उन्होंने तत्काल पुलिस टीम भेजकर महिला का शव अस्पताल से मुक्त कराया और परिजनों को मृत्यु प्रमाणपत्र दिलवाया।

परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसी तरह से रिश्तेदारों से मांगकर 57,000 रुपए जुटाकर दिए लेकिन अस्पताल प्रबंधन का दिल फिर भी नहीं पसीजा। अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित परिवार को उनकी कार तक अपने पास रख लेने की भी धमकी दी

मंजूनाथ ने कहा मानव के पार्थिव शरीर का सम्मान होता है और वह जबरन वसूली का साधन नहीं बन सकता। अस्पताल, मरीज या उसके शव को वस्तु नहीं मान सकता। यह बहुत अमानवीय और निर्मम कृत्य है। इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर मिली है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । हल्द्वानी के नगर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर, अस्पताल में मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार और असामान्य बिल बनाने के खिलाफ अल्मोड़ा में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई स्थानीय नेता और जिला पंचायत सदस्य शामिल थे।

प्रदर्शनकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर मृतका को श्रद्धांजलि दी तथा सरकार से संबंधित अस्पताल और उससे जुड़ी सभी पैथोलाजिकल लैब तत्काल बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी गई कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा।

खबर कोना

भरतपुर पक्षी अभयारण्य में सोमवार को अपने घर लौटतीं श्रमिक।

ट्रंप की चेतावनी से शेयर बाजार सतर्क, सूचकांक में 322 अंक की गिरावट

मुंबई, 5 जनवरी (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय उत्पादों पर शुल्क और बढ़ाने की ताजा चेतावनी के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। सूचकांक 322 अंक के नुकसान में रहा जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट रही। विश्लेषकों ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप की भारत पर शुल्क बढ़ाने की ताजा चेतावनी से कारोबारी धारणा प्रभावित हुई और बैंक, आइटी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक 322.39 अंक यानी 0.38 फीसद गिरकर 85,439.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 446.68 अंक फिसलकर 85,315.33 अंक के निचले स्तर पर आ गया था। बीएसई पर सूचीबद्ध 2,545 शेयर नुकसान के साथ बंद हुए जबकि 1,723 शेयरों में तेजी रही और 203 अन्य अपरिवर्तित रहे। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 26,373.20 अंक के रेकार्ड स्तर तक पहुंचने के बाद अपनी बढ़त गंवा बैठा। निफ्टी 78.25 अंक यानी 0.30 फीसद की गिरावट के साथ 26,250.30 अंक पर बंद हुआ।

रुपए में लगातार चौथे दिन गिरावट, 10 पैसे टूटकर 90.30 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, 5 जनवरी (भाषा)।

रुपए में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट आई और यह 10 पैसे टूटकर 90.30 प्रति डालर पर बंद हुआ। भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने अमेरिकी मुद्रा को मजबूत किया है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद उत्पन्न हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने विश्व स्तर पर डालर की मांग को बढ़ावा दिया। सुस्त घरेलू शेयर बाजार और विदेशी पूंजी की बाजार से निकासी ने कारोबारियों की धारणा को प्रभावित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, 90.21 प्रति डालर पर खुला। कारोबार के दौरान यह 90.50 प्रति डालर के निचले स्तर तक पहुंचा। अंत में डालर के मुकाबले 90.30 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की गिरावट है। यह 30 दिसंबर, 2025 को 89.75 प्रति डालर पर बंद हुई थी। उसके बाद से इसमें 55 पैसे की गिरावट आई है। रुपया शुक्रवार को 22 पैसे टूटकर अमेरिकी डालर के मुकाबले 90.20 पर बंद हुआ था।

भारत-इजराइल से कारोबार में रुपए को बढ़ावा देगा एसबीआइ

यरुशलम, 5 जनवरी (भाषा)।

भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों में गहराई लाने और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) रुपए में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है। एसबीआइ इजराइल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. मणिवन्नन ने कहा कि भारत के सहयोगी देशों से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार एवं वैश्विक व्यापार समुदाय में भारतीय रुपए में व्यापार करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए, हमारे बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने कारपोरेट ग्राहकों के निर्यात एवं आयात का निपटान भारतीय रुपए में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत इजराइल को भागीदार देशों में से एक के रूप में चुना गया है। एसबीआइ के अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से निर्यात/आयात करने वाली इजराइली संस्थाएं भारतीय रुपए में भुगतान प्राप्त करेंगी और देंगी जिसे इजराइली विक्रेता/खरीदार से माल या सेवाओं की आपूर्ति/खरीद के इनवाइस के बदले विशेष रुपी वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) में जमा किया जाएगा।

संपादकीय जागरण

मंगलवार, 6 जनवरी, 2026 : माघ कृष्ण - 3 वि. 2082

धैर्य भी प्रतिभा का एक आवश्यक तत्व है

बेलगाम ट्रंप

वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति का अपहरण कराने और ईरान समेत अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों को धमकाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह रूस से तेल खरीद के मामले में भारत पर टैरिफ बढ़ाने चेतावनी दी, वह उनके बढ़ते अहंकार का नया प्रमाण है। उन्होंने जिस तरह यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि रूस से तेल खरीदने के कारण मैं उनसे खुश नहीं और मुझे खुश करना जरूरी है, उससे उनकी तानाशाही मानसिकता ही प्रकट होती है। वे न केवल पूरी तरह बेलगाम दिख रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे दुनिया के थानेदार हों या फिर उन्हें विश्व को अपने हिसाब से चलाने का जनादेश मिला हुआ है। वे अपने साथ अमेरिका की भी फजीहत करा रहे हैं। यदि वे यह समझ रहे हैं कि उनके रवैये से उनकी या अमेरिका की साख बढ़ रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका केवल अपनी साख ही नहीं गंवा रहा है, बल्कि एक ऐसे गैर जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, जो विश्व व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दुनिया को अराजकता की ओर धकेल रहा है। इसके दुष्परिणाम अमेरिका को भी भोगने होंगे, क्योंकि विश्व के तमाम राष्ट्र उनसे तंग आ चुके हैं और यह एक तथ्य है कि आज अमेरिका उतना सशक्त नहीं, जितना पहले हुआ करता था।

ट्रंप अपने अहं को पूरा करने के लिए जिस तरह अपने मित्र राष्ट्रों से भी बैर मोल ले रहे हैं, वह उन्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनका मनमानापन विश्व के देशों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने को मजबूर कर रहा है। यह बहुत दिनों तक संभव नहीं कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका तो मनमानी करे और विश्व से नियम-कानूनों के हिसाब से चलने की अपेक्षा करे। वे जिस तरह अस्थिरता फैला रहे हैं, उससे विश्व शांति ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी खतरे में पड़ रही है। ट्रंप ने भारत पर पहले ही 50 प्रतिशत टैरिफ थोप रखा है। इसमें 25 प्रतिशत व्यापार समझौता न हो पाने और 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीदने के कारण है। यदि वे और टैरिफ बढ़ाते हैं तो यह एक तरह से भारत पर पाबंदी लगाने जैसा होगा। यह ठीक है कि भारत को अमेरिकी सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन उसे उसके अनुचित दबाव का प्रतिकार करना होगा। भारत को ट्रंप की शर्तों पर व्यापार समझौता करने से बचना होगा। भारत को यह भी आभास हो जाना चाहिए कि अमेरिका से व्यापार समझौता होने में और देरी हो सकती है। भारत को ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि वह उनके बेजा व्यवहार के समक्ष झुकने वाला नहीं।

संकट में भूजल

दिल्ली में केवल हवा की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि पानी की शुद्धता भी अब गंभीर चिंता का विषय बन गई है। राजधानी के कई क्षेत्रों में भूजल का तेजी से दूषित होना एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। विशेष रूप से ओखला, गाजीपुर और भलस्वा स्थित कूड़े के पहाड़ों के निकटवर्ती इलाकों में स्थिति अत्यंत भयावह है। भूजल के दूषित होने का एक बड़ा कारण अवैध औद्योगिक इकाइयां हैं। इन इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता। कई स्थानों पर जहरीला कचरा और रसायन सीधे जमीन में डाल दिए जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि कहीं पानी में टीडीएस की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है।

सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकती

दिल्ली में कई स्थानों पर लोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए भूजल पर निर्भर हैं। अवैध बोरिंग के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड भी साढ़े पांच हजार से अधिक ट्यूबवेलों से जलापूर्ति करता है। सरकार को इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला है। सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकती। जल बोर्ड के सभी ट्यूबवेलों के पानी की नियमित और कड़ी जांच सुनिश्चित की जाए। भूजल को दूषित करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो दिल्ली का जल संकट लाइलाज हो जाएगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बांग्लादेशी क्रिकेटरों को आइपीएल से दूर रखने का फैसला सही है?

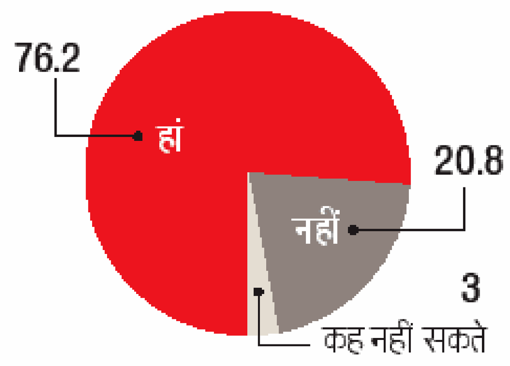

आज का सवाल

क्या टैरिफ को लेकर ट्रंप की नई धमकी भारत-अमेरिका व्यापार सौदे की राह बाधित करेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक

श्रीराम चौलिया

सभ्य विश्व व्यवस्था तभी संभव है, जब कमजोर देश एकजुटता से महाशक्तियों की मनमानी का विरोध करें। यदि साम्राज्यवाद सदियों पुराना है तो समानता और मर्यादा की चाह भी उतनी ही पुरानी है

वेनेजुएला में अमेरिकी हमला यही दर्शाता है कि हम महाशक्तियों की घातक प्रतिस्पर्धा और उनके मनमाने हस्तक्षेपों के दौर में जी रहे हैं। ऐसे दौर में जहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों और जंगल के कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारते हुए कहा, 'हमें इसे फिर से करना होगा, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता।' यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। ट्रंप का यह औपनिवेशिक दावा कि 'हम वेनेजुएला को चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए', स्पष्ट संकेत है कि शक्तिशाली ही शक्तिहीन पर राज करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन करके वहां के खनिजों को अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में लाने की खुलेआम घोषणा से सिद्ध कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के जो भी बचे-कुचे बंधन थे, वे भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने अपने मुकाबले कमजोर पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर विशेषाधिकारों का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार बड़ी शक्तियों को अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूक्रेन की सच्ची संप्रभुता तभी संभव है जब वह रूस के प्रति मित्रवत और पराधीन रहे। इनके उलट चीन ने अभी तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने या भारत, वियतनाम, फिलीपींस अथवा जापान पर सीधे हमले का प्रयास नहीं किया है, परंतु कमजोर पड़ोसियों के प्रति उसका भी औपनिवेशिक और दबंग रवैया है जो दिन-प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है। जब सभी बलशाली देश आक्रामक और लुटेरे तेवरों पर उतर आएं तो बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना सामान्यीकृत होने लगता है।

वैश्विक राजनीति के बारे में कहा जाता है कि वह सिद्धांतों एवं मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, लेकिन हालिया उदाहरण कुछ और ही संकेत करते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद ताइवान को लेकर समय-समय आक्रामकता दिखाने वाले चीन पर भी अंतरराष्ट्रीय कानून वाले तर्क बेमानी हो जाते हैं। लैटिन भाषा में 'टू कुआकवे' जैसी एक संकल्पना है, जिसके अनुसार प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों को उनके तर्क के साथ असंगत बताकर उनके तर्क को अमान्य कर दिया जाता है। वेनेजुएला में सशस्त्र हमला कर और उसकी आंतरिक राजनीति को जबरदस्ती बदलकर ट्रंप ने हर संभावित हमलावर को सुविधाजनक बहाना दे दिया है। ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित करने और एक ऐसे पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करने के लिए उन्नीसवीं सदी के 'मोनरो सिद्धांत' को समकालीन संदर्भ में लागू करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की सरकारों को अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार चलना होगा। अगर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की धौंस जायज है, तो एशिया में चीन अपने आप को बेताज बादशाह क्यों न मान ले?

अवधेश राजपूत

देखा जाए तो ताइवान का परिप्रेक्ष्य वेनेजुएला से भिन्न है, मगर जब संप्रभुता और शांतिपूर्वक बर्ताव के सिद्धांत ही लुप्त हो रहे हों तो राष्ट्रपति शी चिनफिंग जैसे आक्रामक नेता अराजकता का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? चीन निश्चित रूप से इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और अब वेनेजुएला में पश्चिमी दखलंदाजी का हवाला देकर ताइवान और अन्य एशियाई पड़ोसियों पर दबाव और हमले की योजनाओं को तेज करेगा। रूस की तरह चीन भी कहता आ रहा है कि पश्चिमी शक्तियों के पाखंड और दोहरे रवैये के कारण ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों के चिथड़े उड़ गए हैं और वे दोनों अपनी 'आत्मरक्षा' के नाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वयं को विवश बताते हैं। ताइवान को धमकाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रत्येक युद्ध अभ्यास में अनिश्चितता अंतर्निहित है और इनमें से कोई भी वास्तविक युद्ध में तब्दील हो सकता है।

अब तक अगर ताइवान पर चीन ने धावा नहीं बोला है तो यह अंतरराष्ट्रीय नियम या विधि के प्रति शी चिनफिंग की श्रद्धा के कारण नहीं है, बल्कि उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की वजह से है जब हिंद-प्रशांत में शक्ति संतुलन और भूराजनीतिक परिस्थितियां चीन के पक्ष में कहीं अधिक झुक जाएं। चीन भली-भांति जानता है की अमेरिका अब भी 'खुले एवं स्वतंत्र' हिंद-प्रशांत को अपना मूल राष्ट्रीय हित मानता है और अमेरिकी सैन्य सामग्री लगातार ताइवान तथा अन्य एशियाई मित्र देशों को बेची भी जा रही है। चिनफिंग यह चाहेंगे कि वेनेजुएला में हस्तक्षेप के बाद अगर अमेरिका उसी पड़ोसी क्षेत्र में उपनिवेशवादी मंशा से ज्यादा उलझ जाए और चीन के साथ व्यापार समझौते के चलते एशिया की तकदीर चीन के हाथों छोड़ दें तो ताइवान पर आधिपत्य का उसके पास सुनहरा मौका होगा।

आक्रामक महाशक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर किए जा रहे व्यापक आघातों के मद्देनजर छोटे देशों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने की क्या रणनीति हो सकती है? मौलिक स्तर पर उन्हें समूचे 'वैश्विक दक्षिण' में एकजुट होकर हस्तक्षेप की नितांत अस्वीकृति के सिद्धांत पर जोर देना होगा, ताकि महाशक्तियों का जंगल-राज एक सामान्य दस्तूर न बन जाए। व्यावहारिक स्तर पर उन्हें क्षेत्रीय एकीकरण और एकता को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि कोई भी महाशक्ति आसानी से उनमें भेद पैदा करके उन्हें बांट न सके। वेनेजुएला में मादुरो ने सबसे बड़ी भूल यह की कि पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देशों के साथ उन्होंने वर्षों से दुश्मनियां मोल लीं और अंत में अमेरिकी आक्रमण को टालने के लिए कोई प्रांतीय गठबंधन या संस्थान शेष नहीं रहा। स्मरण रहे कि एक सभ्य विश्व व्यवस्था का निर्माण तभी संभव है, जब कमजोर देश एकजुट होकर वर्चस्व का विरोध करें। इतिहास से हम थोड़ी बहुत सीख-समझ भी ले सकते हैं कि यदि साम्राज्यवाद सदियों पुराना है तो समानता और मर्यादा की चाह भी उतनी ही पुरानी है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान

प्रमथ राज सिन्हा

नए पाठ्यक्रम, बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़कर भारतीय संस्थान खुद को मजबूत बना सकते हैं

केवल डिग्री हासिल कर लेने को शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा वह शक्ति है, जो जीवन को दिशा देती है। सफल शिक्षा एक व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल सकती है, उसे जीवन उद्देश्य दे सकती है और अपने भीतर छिपी संभावनाएं पहचानने का अवसर दे सकती है। खासतौर पर उच्च शिक्षा वह पड़ाव है, जहां युवा अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानते हैं और भविष्य की राह खोजने की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ स्कूली शिक्षा हमें हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है, वहीं उच्च शिक्षा छात्रों को अपने विकल्प जानने की आजादी देती है। उच्च शिक्षा समय है अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों को समझने और यह तय करने का कि उन्हें जीवन में क्या करना है। यह प्रक्रिया सरल नहीं, जटिल होती है। एक छात्र के आजादी से अपनी राह चुन सकने के पीछे एक मजबूत संस्थान, संसाधन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।

भारत जैसे विशाल और विविध देश में संस्थान निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हर साल लाखों छात्र स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, लेकिन संस्थानों में इतनी सीटें ही नहीं कि सबको दाखिला मिल सके। नतीजतन प्रतिस्पर्धा और तेज होती जा रही है और परीक्षाएं और ज्यादा मानकीकृत हो रही हैं। इस सबके साथ-साथ व्यवस्था अक्सर प्रशासनिक सुविधा की सहूलियत देखती है। इस गहन माहौल में हर छात्र की अलग पहचान और क्षमता पर ध्यान दे पाना असंभव हो जाता है। आज भारत में लगभग 70,018 उच्च शिक्षा संस्थान हैं। भले ही यह उत्साहजनक लगे, लेकिन देश की जरूरतों के मुकाबले अभी भी पर्याप्त नहीं। युवावर्ग अब भी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा खोज रहा है। आपूर्ति की कमी का असर छात्र के इस निर्णय पर पड़ता है कि वह कहां पढ़े। सख्त आव्रजन नीतियों के बाद भी भारतीय छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन उनके प्रमुख गंतव्य हैं। हालांकि अब फ्रांस, आयरलैंड और इटली भी तेजी से छात्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं।

समय की आवश्यकता के अनुरूप बने शिक्षा ● फाइल

जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 12 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। इस आंकड़े से घरेलू स्तर पर आवश्यकता और सीमित विकल्प साफ उजागर होते हैं। इन चुनौतियों के बीच से ही बड़े अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

तेजी से बदलती दुनिया में पहला अवसर नवाचार में निहित है। भारत में हमें अधिक बहुविषयक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। हमें ऐसे कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा, जो तकनीक, पर्यावरण, सूचना और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हों। मैनेजमेंट, कानून और मेडिकल जैसे पारंपरिक कोर्स को भी नए ढंग से देखना होगा। नए पाठ्यक्रम, बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़ कर भारतीय संस्थान खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकते हैं। दूसरा बड़ा अवसर है, डिजिटल शिक्षा। हाइब्रिड माडल प्रभावी हो सकते हैं, जिन्हें आनलाइन और आफलाइन पढ़ाई को मिलाकर बनाया गया हो। अगर सही ढंग से लागू किए जाएं तो ये बड़े पैमाने पर लाभकारी शिक्षा का साधन बन सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां छात्र दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, डिजिटल शिक्षा एक असरदार समाधान प्रस्तुत करती है। अपने सशक्त डिजिटल ढांचे की सहायता से भारत विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। नीतिगत स्तर पर आज सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। तीन दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का बीड़ा उठाया है। बहुविषयक पढ़ाई, विषयों में लचीलापन और संस्थानों की स्वायत्तता जैसे विचारों पर अब जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के पूर्व अनुभव बताते हैं कि जब-जब सरकारें शोध, नवाचार और तकनीक को शिक्षा का केंद्र बनाती हैं, तब-तब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीसरा अहम पहलू है, प्रतिभा निर्माण। उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य केवल रुखा ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों के सोच के दायरे को विस्तार देना, कौशल को बढ़ाना और छात्रों को पेशेवर समझ देना भी है। सार्थक शिक्षा देश को ऐसा मानव संसाधन देती है, जो न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने क्षमता रखता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आत्मविश्वास के साथ अपना योगदान दे सकता है।

अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो पाएंगे कि उच्च शिक्षा की परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। अपने-अपने समय में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र विश्व भर से विद्वानों को आकर्षित करते रहे। इन सभी ने जिज्ञासा एवं शोध को शिक्षा का मूल सिद्धांत बनाया। आज भले ही समय और परिस्थितियां बदल गई हों, लेकिन हमारा लक्ष्य और भी स्पष्ट है। अगर हमें 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है और केवल डिग्री पर केंद्रित न रह कर सीखने की सामर्थ्य को प्रोत्साहित करना है तो संस्थान निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। हमारे आज के प्रयास से भारत के शिक्षा संस्थान न केवल युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा दे सकेंगे, बल्कि यही युवा आगे चलकर विकसित भारत 2047 की नींव भी मजबूत करेंगे।

(लेखक अशोका यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, बोर्ड आफ ट्रस्टी हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ईर्ष्या

दूसरों की उपलब्धि तथा वैभव देखकर जलन का भाव जागृत होना शुभ लक्षण नहीं है। यही भाव ईर्ष्या को जन्म देता है। जब मन में ईर्ष्या घर कर जाती है, तो व्यक्ति न केवल मानसिक रूप से अशांत रहता है, बल्कि भीतर ही भीतर कुढ़न भी पनपने लगती है। ऐसी स्थिति में निंदा करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जिससे हम चिढ़ रहे होते हैं, उसकी बार-बार आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि ईर्ष्या स्वभावतः निंदा को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के वैभव से हम ईर्ष्या करते हैं, वह हमें दुश्मन सा प्रतीत होने लगता है।

ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना अमूल्य समय दूसरों की आलोचना में गंवाता है। उसे यह आभास नहीं होता कि समय कितना मूल्यवान है। अपनी उन्नति पर ध्यान देने के बजाय उसे निंदा करने में ही अधिक आनंद आता है। दरअसल जब इच्छाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और उनकी तुलना दूसरों से की जाने लगती है, तभी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों के वैभव पर दृष्टि डालने के बजाय उन लोगों की ओर देखे, जो उससे कहीं अधिक कष्टपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तब उसे अनुभव होगा कि उसका जीवन बहुतों से बेहतर है और वह अपने पास उपलब्ध साधनों और सुखों को अनदेखा कर रहा है। जिस दिन दूसरों के वैभव की जगह उनके कष्ट दिखाई देने लगेंगे, उस दिन मन में सहानुभूति का भाव जागृत हो सकता है और सहायता की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है।

जब ईर्ष्या का स्थान सहयोग का भाव ले लेता है, तो वही ईर्ष्यालु व्यक्ति नेकदिल मनुष्य बन जाता है। जो लोग ईर्ष्या के कारण उससे दूरी बनाए रखते थे, वे ही उसकी सराहना करने लगते हैं। वस्तुतः ईर्ष्या से कुछ भी हासिल नहीं होता, उलटे यह समय और स्वास्थ्य, दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, ईर्ष्या नहीं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही उन्नति के द्वार खोलती है।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

जानलेवा लापरवाही

संपादकीय 'पेयजल की गुणवत्ता' में इंदौर में दूषित जल से हुई 16 लोगों की मौत से सबक सीखने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। इस दुर्घटना ने जनसामान्य के लिए आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रति पूरे सरकारी तंत्र के गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाह और असंवेदनशील रवैये को उजागर किया है। समय रहते अगर तंत्र किसी भी स्तर पर कर्तव्य के पालन में सक्रिय, जागरूक और सतर्क रहता, तो संभवतया यह घटना टल जाती। जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इसकी शुद्धता, गुणवत्ता और आपूर्ति में किसी तरह से कोई समझौता करना, मानो साक्षात बीमारियों को आमंत्रण देना है। जलजनित बीमारियों से देश में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार-जवाबदेह मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी पीड़ितों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। सीधी सी बात है अब लोकतंत्र में 'लोक' तंत्र के लिए सिर्फ वोट-बैंक बनकर रह गया है। यह स्थिति शर्मनाक, चिंताजनक और आत्मा को झकझोरने वाली है। वोट-बैंक की राजनीति ने ही अनियोजित और अवैध कालोनियों को बिना आधारभूत ढांचे के वैध बना दिया है। पेयजल की निम्न गुणवत्ता देश के लगभग सभी शहरों-गांवों की समस्या है। इसके मूल में सीवर और स्वच्छ पाइपलाइन का रिसाव है। यहां तक की भूमिगत जल भी प्रदूषण की मार से नहीं बच पाया है। जल ही जीवन है, शुद्ध जल लोगों को मिलना ही चाहिए। अतः भविष्य में फिर कभी ऐसी कोई त्रासदी न हो, इसके लिए समय रहते उचित कदम उठाए जाने चाहिए। सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों और मंत्रियों को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने रहना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि उनकी नाकामी-लापरवाही अब जनता की जान ले रही है।

mohitsonikukshi@gmail.com

दिल्ली की जहरीली हवा

दिल्ली में प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं रही है, लेकिन अब यह समस्या इस हद तक पहुंच चुकी है कि इसे केवल पर्यावरणीय संकट कहना कम होगा। यह एक मानवीय त्रासदी का रूप ले चुकी है। हालिया अध्ययन ने एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर किया है कि राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर सिर्फ दिल्ली की देन नहीं है। करीब 65 फीसदी प्रदूषण शहर के बाहर से आता है, खासतौर पर एनसीआर के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों से। दिल्ली अपने स्तर पर केवल 35 फीसदी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा बदनाम भी दिल्ली ही होती है और सबसे ज्यादा मार भी यहीं के लोगों को झेलनी पड़ती है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इसे प्रदूषण के मामले में बेहद संवेदनशील बनाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों, खेतों और शहरी इलाकों से उठे धुएं और धूल को दिल्ली में लाकर पटक देती हैं। सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि ठंडी हवा के कारण वातावरण में ऐसी परत बन जाती है, जो प्रदूषक कणों को ऊपर उठने नहीं देती।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

भारत और 2047

सन 2047 भारत के लिए केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक लक्ष्य है। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को 'विकसित भारत' के रूप में देखना हर नागरिक का सपना है। प्रश्न यह है कि क्या भारत इस लक्ष्य के लिए वास्तव में तैयार है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश को नई दिशा दी है। डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार में युवाओं की भागीदारी यह दिखाती है कि भारत भविष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। शिक्षा और कौशल विकास भी 2047 के भारत की नींव हैं। नई शिक्षा नीति, आनलाइन शिक्षा और स्किल इंडिया जैसे प्रयास युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं। साथ ही, अंतरिक्ष, रक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर निरंतर काम करना आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को कम करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। निष्कर्षतः, भारत 2047 के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चय ही सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बन सकता है।

कमल सिंह, सरोजनी नगर दिल्ली

X पोस्ट

21वीं सदी के 25 साल बीत गए। अब भी कुछ नहीं बदला। आज भी एक देश दूसरे देश में घुसकर तख्तापलट कर देता है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

क्या कुछ नोबेल पुरस्कार विजेता अपने-अपने देश में विदेशी दखल से सत्ता के तख्तापलट का माध्यम बनते हैं? मेरे हिसाब से यह सिलसिला केवल दक्षिण अमेरिका तक ही सीमित नहीं है।

स्वपन दासगुप्ता@swapan55

तेल के लिए एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेने वाले ट्रंप को दुनिया के समक्ष शांति का प्रवचन देने का कतई कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप ने जो किया, वह दुनिया की व्यवस्था को ध्वस्त करने जैसा है।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

जोहरान ममदानी की चिट्ठी के बाद देश में कुछ लोगों ने ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज ही कर दी।

अरविंद चोटिया@arvindchotia

जनपथ

लाठी जिसके पास है होगी उसकी भैंस,
ताकत के बल पर चले ट्रंप लूटने कैश।
ट्रंप लूटने कैश ढूंढ नित नया बहाना,
देखो कितने देश बनेंगे नया निशाना!
अब तो ताऊ ट्रंप बन रहे हिटलर खांटी,
दिखा रहे हैं रौब हाथ में लेकर लाठी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय :0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 172

****

प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर जाएंगे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अवसर पर सोमनाथ में वर्षभर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना है। आठ से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के एक हजार साल पूरे होने के अवसर पर लिखे 'ब्लाग पोस्ट' में पीएम मोदी ने कहा, हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। यह मंदिर गौरव के साथ खड़ा है।

पीएम नरेन्द्र मोदी

हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता : भागवत

- हिंदुओं में जातिवाद के खात्मे को पूरी ताकत लगाने की आवश्यकता
- कहा, कई राज्यों में हिंदुओं पर अत्याचार जागरूक न होने का नतीजा

मोहन भागवत ● फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, वृंदावन : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोमवार को हुई अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से हिंदुओं के पलायन पर भारी चिंता व्यक्त की गई। संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत ने कहा कि देश के कई राज्यों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसे रोकने को गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। हिंदू समाज का भी संगठित और जागृत होना बहुत जरूरी है। संघ इसके लिए मुहल्ला हिंदू बैठक से आगे बढ़ेगा। इनमें संगठित होने के फायदे और बिखराव के नुकसान बताए जाएंगे।

सात दिवसीय प्रवास के दौरान केशवधाम में सुबह 10 बजे से तीन सत्रों में बैठक चली। संघ प्रमुख ने सबसे ज्यादा चिंता हिंदुओं के बिखराव पर व्यक्त की। कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं, यह विभिन्न समाजों की एक जैसी मनोवृत्ति और स्वभाव है। हिंदू इसलिए कहा गया क्योंकि हम सभी पंथों और संप्रदायों को मानते हैं। हिंदू कहने से ही हम एक सूत्र में बंधते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू सम्मेलन और मुहल्ला हिंदू बैठकें हमारे समाज को संगठित करने में सबसे अधिक सहायक होंगी। हर हिंदू परिवार इससे जुड़ेगा और उसके अंदर खुद समाज को एकजुट करने की भावना जागृत होगी। उन्होंने बंगाल और अन्य राज्यों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और लायन पर भी चिंता व्यक्त की। पड़ोसी देशों में भी हो रही हिंसा पर शीर्ष पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर मौजूद रहे।

'ओवैसी को भागवत से प्रश्न का नैतिक आधार नहीं'

नई दिल्ली, आइएएनएस : भाजपा और शिवसेना ने सोमवार को एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने ''लव जिहाद'' पर भागवत के विचारों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी के पास संघ प्रमुख को चुनौती देने के लिए 'नैतिक और राजनीतिक अधिकार दोनों की कमी'' है। मोहन भागवत ने भोपाल में 'स्त्री शक्ति संवाद' कार्यक्रम के दौरान कहा था कि ''लव जिहाद'' के रूप में वर्णित घटनाएं मुख्यतः परिवारों में संवाद और नैतिक आधार की कमी के कारण होती हैं। उन्होंने तर्क किया कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास घर से शुरू होने चाहिए।

ओवैसी ने कहा था कि वयस्कों को अपने साथी चुनने का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। ''यदि 'लव जिहाद' हो रहा है, तो संसद में डाटा प्रस्तुत करें। इस शब्द को परिभाषित करें और पिछले 11 वर्षों के रिकार्ड दिखाएं।'' भाजपा के प्रवक्ता प्रातुल शाह देव ने कहा कि लव जिहाद तब होता है जब एक मुस्लिम युवक या किसी अन्य धर्म का व्यक्ति हिंदू लड़कियों को मतांतरण के लिए धोखा देता है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि भागवत की टिप्पणियों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रातुल शाह देव ● फाइल फोटो

'हर साल पांच लाख लड़कियां बनीं शिकार'

सूरत, एएनआइ : वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने ''लव जिहाद'' को एक राष्ट्रीय समस्या बताते हुए दावा किया कि हर साल पांच लाख से अधिक लड़कियां इसका शिकार होती हैं, जिससे भारत की जनसंख्या और जनसांख्यिकी में बदलाव आ रहा है। संघसरचालक मोहन भागवत की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपाध्याय ने आरोप लगाया कि लव जिहाद एक योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसमें घुसपैठियों का बसना और व्यवस्थित धार्मिक मतांतरण शामिल है। ''लव जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है।

एआइ के इस्तेमाल पर संसदीय समिति ने बनाई रिपोर्ट

नई दिल्ली, एएनआइ : संचार और इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी मामलों की संसद की स्थायी समिति ने सोमवार को बैठक कर आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआइ) मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट आगामी बजट सत्र में पेश की जाएगी।

एआइ के प्रभाव का आकलन करने के लिए फरवरी में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। स्थायी समिति के प्रमुख भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बजट सत्र के दौरान हम रिपोर्ट देकर सरकार से देश में एआइ ढांचा तैयार करने के संबंध में अहम सलाह देंगे। ग्रोक एआइ पर अश्लील कंटेट आने के सवाल पर दुबे ने कहा, हम पहले देश हैं जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसे हटाने को कहा है। बाकी देशों ने हमारा अनुसरण किया है।

एक नजर में

पीएम मोदी ने डा. मुरली मनोहर जोशी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी को उनके 91वीं जन्मतिथि पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कृति और भारत की सभ्यतागत मूल्यों के प्रसार में डा जोशी का आजीवन योगदान सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करता है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर डा. जोशी को सम्मानित राजनेता और प्रखर बुद्धिजीवी बता उनके दीर्घ जीवन की कामना की। (प्रेट्र)

हुमायूं कबीर के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने लगाए 'वापस जाओ' के नारे

कोलकाता: नवगठित जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने अपनी प्रस्तावित रैली के स्थल का निरीक्षण करने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड का दौरा किया। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक कबीर की यात्रा के दौरान टीएमसी समर्थकों के एक समूह ने 'वापस जाओ' के नारे लगाए और उन्हें भाजपा का एजेंट कहा। कबीर ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी डरी है। (राब्यू)

मुंबई का महापौर वंदे मातरम् बोलने वाला मराठी मानुष होगा : शिवसेना प्रवक्ता

मुंबई : शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने सोमवार को कहा कि मुंबई का महापौर वंदे मातरम् बोलने वाला मराठी मानुष होगा। महायुति की राजनीति मुंबई पहले के सिद्धांत पर आधारित है। महायुति का महापौर वही होगा, जो शहर से प्रेम करता हो और उसके विकास की कामना करता हो। महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राकांपा शामिल हैं। (प्रेट्र)

रामपुर में खुद ढहाया सरकारी भूमि पर मदरसा

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के भमरौआ स्थित श्रीपातालेश्वर मंदिर के समीप ग्राम समाज की भूमि पर चल रहा मदरसा प्रबंध कमेटी ने सोमवार को खुद ध्वस्त करा दिया। इसकी शिकायत चार दिन पहले जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से हुई थी। इसके बाद शिकायत की जांच कराई जा रही थी। सरकारी भूमि पर मदरसा चलाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सदर तहसील को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। (जासं)

'नेहरू व वामपंथी इतिहासकारों ने गजनी को सिर्फ लुटेरा बता इतिहास तोड़ा-मरोड़ा'

'डिस्कवरी आफ इंडिया' का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप

- कहा- सोमनाथ मंदिर विध्वंस करने वाले धार्मिक कट्टरपंथी गजनी को बताया था कलाप्रेमी
- मैकाले की मानसिकता से एम फैक्टर ही दिलाएगा मुक्ति, उनका आशय पीएम मोदी से था

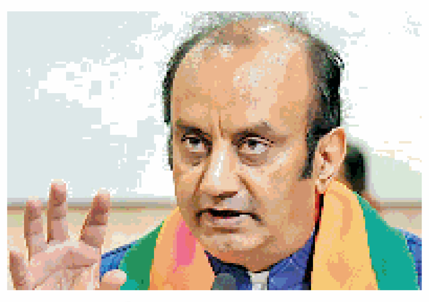
सुधांशु त्रिवेदी ● फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने सोमवार को महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पहले विध्वंस की 1,000वीं बरसी पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा- पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू व वामपंथी इतिहासकारों ने गजनी को सिर्फ लुटेरा बताकर इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा। उन्होंने गजनी को धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में पेश नहीं किया, जबकि यह हकीकत थी।

भाजपा सांसद व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू की पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इंडिया' सहित अन्य पुस्तकों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सोमनाथ और मथुरा के मंदिरों-भवनों का विध्वंस करने वाले महमूद गजनी को पंडित नेहरू ने कलाप्रेमी बताया था। उन्होंने कहा कि जो लोग देश में बैठकर मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र बनकर सोचते हैं, उनके दिमाग में 19वीं सदी का मैकाले फैक्टर और 20वीं सदी का मार्क्सिस्ट फैक्टर गहराई से बैठा हुआ है, वे इसका उत्तर भी समझ सकते हैं। इसका उत्तर भी एक 'एम' फैक्टर ही है और वह है मोदी फैक्टर। यह एम फैक्टर ही मैकाले की मानसिकता से मुक्ति दिलाएगा।

भाजपा प्रवक्ता ने गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की याद दिलाते हुए कहा कि इतिहास के ऐसे आघातों को स्मरण रखना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि इस देश की अस्मिता के साथ एक अत्यंत घिनौना मजाक किया गया। हमारी पीढ़ी और उससे पहले की पीढ़ियों ने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ पर जो कुछ किया, वह केवल धन लूटने के लिए था और उसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इसका स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक 'डिस्कवरी आफ इंडिया' है। उसमें लिखा है कि महमूद गजनी एक योद्धा था, न कि आस्था से प्रेरित व्यक्ति और अन्य कई विजेताओं की तरह उसने धर्म के नाम का उपयोग अपने आक्रमणों के लिए किया। वह कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, बल्कि केवल धन कमाने के उद्देश्य से भारत आया था। उसी पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि वह कला का कितना बड़ा प्रेमी था, जबकि गजनी के साथ ही आए उसके अपने इतिहासकार कुतबी ने अपनी किताब 'तारीख-ए-यामिनी' में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस समय महमूद गजनी ने मंदिर पर अधिकार कर लिया, तब वहां के समस्त पुरोहित और राजा उसके पास गए और प्रार्थना की कि शिवलिंग को खंडित न किया जाए। इसके बदले में वे उसे लाखों स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। उसके सलाहकार राजी थे, लेकिन गजनी ने इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि अपनी पहचान मूर्तियां तोड़ने वाले के रूप में बनाना चाहता है।

सुधांशु ने कहा कि जब सोमनाथ की पुनः स्थापना हो रही थी, तब 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन मानी जाएगी, जब भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई देगा, जिस समृद्धि से आकर्षित होकर अतीत में उस पर क्रूर और बर्बर आतंकी आक्रमण किए गए थे। 1951 में सरदार पटेल के प्रयासों से और जवाहरलाल नेहरू के पुरजोर विरोध के बावजूद वह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वही बात साकार होती हुई दिखाई दे रही है, जो डा. राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। आज देश पूर्णता की ओर बढ़ रहा है।

कुपोषण के खिलाफ बड़े राष्ट्रीय प्रयास में जुटे शाह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाते हुए कुपोषण के खिलाफ बड़ा राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कुपोषण उन्मूलन में कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी की अहम भूमिका पर मंगलवार को कान्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फार न्यूट्रिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सीएसआर कान्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। इसका मकसद बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए सहकारिता और कार्पोरेट क्षेत्र की साझेदारी को मजबूत करना है।

कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण पोषण कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। पहला, सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर योजना के तहत गिफ्टमिल्क कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के लगभग चार हजार बच्चों को विटामिन ए और डी से भरपूर फ्लेवर्ड दूध दिया जाएगा। यह दूध छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरा, आइडीबीआइ बैंक की सीएसआर पहल के तहत शिशु संजीवनी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस योजना से महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की आंगनवाड़ियों में पढ़ने वाले करीब तीन हजार बच्चों को पोषण सहायता मिलेगी। शिशु संजीवनी एक खास तरह का पोषक आहार है, जिसे एनडीडीबी ने विकसित किया है। कान्क्लेव में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और शोध संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तिरुचिरापल्ली में सोमवार को आयोजित महोत्सव के दौरान पोंगल पकवान तैयार करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे ● एएनआइ

पोंगल समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री

तिरुचिरापल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यहां मन्नारपुरम में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित भव्य पोंगल महोत्सव में भाग लिया। घी मिलाए चावल, दाल और गुड़ से बनी मीठे व्यंजन पोंगल को 1,008 सजाए गए बर्तनों में पकाया गया, जिन्हें चारों ओर गन्ने से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शाह का मन्नारपुरम में आगमन पर स्वागत किया गया और उन्होंने पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर पोंगल पकवान तैयार किया।

भाजपा के सदस्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन मध्य जनवरी के फसल उत्सव को मनाने के लिए करते हैं, जिसे ''नम्मा ऊरु मोदी पोंगल'' नाम दिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदर्भ है, ताकि जनता से जुड़ाव बढ़ सके। महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानाथी श्रीनिवासन, भाजपा के राज्य अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

टीएमसी सांसद देव और क्रिकेटर शमी को निर्वाचन आयोग का समन

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल में एसआइआर के तहत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने टालीवुड सुपरस्टार और तृणमूल कांग्रेस के सांसद देव (दीपक अधिकारी) व भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सहित कई को सुनवाई के लिए तलब किया है।

तृणमूल सांसद देव के साथ-साथ उनके परिवार के तीन सदस्यों को भी एसआइआर पर सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। देव का जन्म पश्चिम मेदनीपुर के घाटाल में हुआ था। वर्तमान में वह कोलकाता के साउथ सिटी में रहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है। वहीं, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, जो उप्र के मूल निवासी हैं पर लंबे समय से कोलकाता के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, उन्हें भी फार्म में कुछ विसंगतियों के कारण बुलाया गया है। शमी विजय हजारे ट्राफी खेल रहे हैं, वह सोमवार की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। उनके भाई को भी नोटिस जारी किया गया है।

उधर आयोग ने दक्षिण 24 परगना व पूर्व मेदिनीपुर के जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या आरोपित चार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर पूर्व और पूर्व मेदिनीपुर में मतदाता सूची में गंभीर खामियों से जुड़ा है।

मोहम्मद शमी ● फाइल फोटो

मोहम्मद शमी वर्तमान में कोलकाता के जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, फार्म में कुछ विसंगतियों के कारण बुलाया

योगी ने की मोदी-शाह से मुलाकात, मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ चुनावी रणनीति पर की चर्चा

- भाजपा अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष से भी मिले मुख्यमंत्री
- खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें हुई तेज

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली में मुलाकात की है। नए वर्ष पर उनका दिल्ली दौरा महज शिष्टाचार मुलाकातों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करीब एक घंटे की उनकी मुलाकात, शीर्ष भाजपा नेताओं से संवाद और दिल्ली में ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही बड़े निर्णय हो सकते हैं। ये मुलाकात इशारा कर रही है कि अब फोकस पूरी तरह वर्ष 2027 का उप्र विस चुनाव ही है।

सरकार, संगठन और चुनाव तीनों मोर्चों पर एक साथ तैयारी शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का यह दौरा उसी बड़े राजनीतिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की, जिसमें गुलाबी मीनाकारी का इस्तेमाल किया गया है। मुलाकात की तस्वीरें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इंटरनेट मीडिया के एक्स अकाउंट पर साझा की गईं हैं। योगी-मोदी की मुलाकात को उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि खरमास समाप्त होते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें बनारस की गुलाबी मीनाकारी से बनी राम मंदिर की आकृति भेंट की ● सौजन्य : शिल्पकार

मतदाता सूची में गैर नागरिक का नाम असंवैधानिक : ज्ञानेश कुमार

जागरण संवाददाता. देवघर: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी गैरनागरिक का नाम होना या एक मतदाता का दो जगह नाम होना असंवैधानिक है। वह सोमवार को झारखंड में देवघर में बीएलओ से संवाद के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) की शुरुआत की गई है, जिसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल पात्र भारतीय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। बिहार में एसआइआर की सफलता का जिक्र कर बताया कि आयोग झारखंड व अन्य 12 राज्यों में भी ऐसी सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है।

देवघर में पत्रकारों से संवाद करते मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार

चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक की, जहां आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सीईओ ने चुनाव तैयारियों पर चर्चा की।

ममता ने रखी गंगासागर सेतु की नींव, अनुमति न लेने का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागरद्वीप को मुख्य भू-भाग से जोड़ने के लिए मूड़ी गंगा नदी पर गंगासागर सेतु का सोमवार को शिलान्यास किया। 1,700 करोड़ रुपये खर्च कर चार लेन वाले सेतु का निर्माण किया जाएगा। यह दो साल में पूरा होगा। ममता ने कहा कि 'सब तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार' का नारा बदलकर 'सब सागर एक बार, गंगासागर बार-बार' हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगासागर के लोगों की तकलीफें दूर होंगी।

भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर गंगासागर सेतु के निर्माण के लिए केंद्र से अनुमति नहीं लेने का आरोप लगाया है। कहा कि मूड़ी गंगा राष्ट्रीय जलमार्ग है। उसपर सेतु बनाने के लिए केंद्र से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है। ममता सरकार ने ऐसा नहीं किया। मेरी इस बारे में केंद्रीय बंदरगाह, जलमार्ग व जहाजरानी राज्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल से बातचीत हुई है। यह भी दावा किया कि परियोजना के लिए कागज पर निविदाएं भी आमंत्रित नहीं की गई हैं। परियोजना का काम शुरू करने से पहले वहां की मिट्टी का परीक्षण भी नहीं किया गया है। लोगों को गंगासागर सेतु के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है।

1,700 करोड़ खर्च कर किया जाएगा चार लेन वाले सेतु का निर्माण, दो साल में होगा पूरा

ममता बनर्जी ● फाइल फोटो

> **एसआरआइ के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी : ममता**
>
> मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआइआर के दबाव में आकर बहुत से चुनाव अधिकारियों व आम लोगों की मौत हो गई। बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जरुरत पड़ने पर मैं लोगों की ओर से इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगी।

गोवा में आप को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पालकर समेत वरिष्ठ नेता अलग

पणजी, प्रेट्र : गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर, कार्यकारी प्रमुख श्रीकृष्ण परब और तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पालकर, परब और गोवा आप युवा शाखा के अध्यक्ष रोहन नाइक ने प्रेस कान्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा की। गोवा आप के दो उपाध्यक्ष चेतन कामत और सरफराज ने पुष्टि की कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि वे प्रेस कान्फ्रेंस में नहीं थे।

राज्य में जिला पंचायत चुनावों में आप के खराब प्रदर्शन के बाद पालकर को पिछले महीने गोवा आप प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। 20 दिसंबर को हुए इस चुनावों में केवल 42 सीटों में से एक सीट जीती। पालकर 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों से पहले आप में शामिल हुए।

उन्हें आप का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने 40 सदस्यीय विधानसभा में केवल दो सीटें जीतीं।

जेल से बाहर आया गुरमीत, लग्जरी गाड़ियों के काफिले से सिरसा पहुंचा

जागरण टीम हिसार: साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्या जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। रोहतक की सुनारिया जेल से सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे उसे 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। जेल से बाहर आते ही सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचा, जिसमें दो बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर, दो फर्च्यूनर सहित कई वाहन शामिल थे।

गुरमीत दोपहर करीब 2:45 बजे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंचा। यह गुरमीत सिंह की 15वीं रिहाई है। इससे पहले वह 15 अगस्त 2025 को जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था।

डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा कि पैरोल और फरलो हर कैदी का कानूनी अधिकार है। नियमों के तहत एक वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो दी जा सकती है। यह सुविधा केवल गुरमीत सिंह को ही नहीं, बल्कि प्रदेश के करीब छह हजार कैदियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि गुरमीत सिंह सिरसा डेरे में ही रहेंगे।

गुरमीत सिंह ● फाइल फोटो

2017 से जेल में बंद है गुरमीत सिंह: गुरमीत को 25 अगस्त 2017 को दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद हुई। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में अक्टूबर 2021 में सीबीआइ कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी थी।

सिरसा पहुंचकर संगत को दिया संदेश: डेरा प्रमुख ने एप के माध्यम से संगत को शाह सतनाम सिंह के जन्म माह की बधाई दी। कहा कि डेरा प्रबंधन की अनुमति के बिना कोई भी प्रेमी सिरसा न आए।

मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं हटा : थरूर

वायनाड, प्रेट्र: कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा है कि वह कभी भी पार्टी लाइन से अलग नहीं हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सुल्तान बाथरी में सोमवार को आयोजित 'लक्ष्य 2026' नेतृत्व शिविर में भाग लेने के बाद उन्होंने ये बात कही। उनके हालिया बयानों और लेख ने पार्टी को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया था।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि किसने कहा कि मैंने पार्टी की विचारधारा का उल्लंघन किया है? मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अधिकतर मामलों में पार्टी और मैं एक ही रुख पर कायम रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संसद में मंत्रियों के सामने जो सवाल उठाए थे, उनकी एक स्पष्ट दिशा थी और पार्टी को उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाद अक्सर तब शुरू होते हैं जब मीडिया की खबरें पूरी सामग्री पढ़े बिना केवल सुर्खियों पर आधारित होती हैं। शशि थरूर ने कहा कि जब मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या उन्होंने वास्तव में मैंने जो लिखा है उसे पढ़ा है, तो ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा होता है। पूरा पाठ पढ़ने के बाद, उन्हें असली मुद्दा समझ में आता है। शशि थरूर ने कहा कि वह 17 साल से पार्टी में हैं और सहयोगियों से मेरे अच्छे संबंध हैं। थरूर से पूछा गया कि क्या ये मुद्दे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुए। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ा और हार गया। बात यहीं खत्म हो गई। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का बचाव करने वाली टिप्पणी पर थरूर ने कहा यह आडवाणी की 98वीं जन्मतिथि पर शिष्टाचार था। हमारी संस्कृति हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। पीएम मोदी की प्रशंसा के रूप में देखे जाने वाले बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में कही गई बातों को उद्धृत किया था।

शशि थरूर ● फाइल फोटो

हाथरस के बूलगढ़ी प्रकरण में कोर्ट ने जारी किया राहुल को नोटिस

जागरण संवाददाता, हाथरस : बूलगढ़ी प्रकरण में न्यायालय से बरी हुए तीन युवकों को दुष्कर्मी कहने पर लोस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एमपी-एमएलए कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस मामले में अब सात फरवरी को सुनवाई होगी।

हाथरस के बूलगढ़ी में अनुसूचित जाति के परिवार की युवती पर 14 सितंबर, 2020 को हमला हुआ था। उसके भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर गांव के ही तीन युवकों के नाम और धाराएं बढ़ाई गईं। 29 सितंबर, 2020 को युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन हुए। स्थानीय न्यायालय ने तीन युवकों को निर्दोष माना और दो मार्च 2023 को बरी कर दिया। राहुल 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी आए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दुष्कर्म के आरोपितों का घूमना संविधान के खिलाफ है।

****

एक नजर में

बीसीसीएल ने तय किया आइपीओ का प्राइस बैंड

नई दिल्ली: कोल इंडिया की सब्सिड्यिरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का प्राइस बैंड 21-23 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का 1,071.11 करोड़ रुपये का आइपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 9-13 जनवरी तक खुलेगा। उच्च प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन 10,700 करोड़ रुपये होगा। इस आइपीओ में 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। (प्रेट्र)

अप्रैल-नवंबर में दोगुना से ज्यादा बढ़ा यूरिया आयात

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों यानी अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान भारत का यूरिया आयात दोगुना से ज्यादा बढ़कर 71.7 लाख टन रहा है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया (एफएआइ) के अनुसार, आयात में वृद्धि का प्रमुख कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट रही है। अप्रैल-नवंबर 2024 में 32.6 लाख टन यूरिया का आयात किया गया था। पहले आठ माह में घरेलू यूरिया उत्पादन 3.7 प्रतिशत घटकर 1.97 करोड़ टन रहा है, जबकि बिक्री 2.3 प्रतिशत बढ़कर 2.54 करोड़ टन रही है। (प्रेट्र)

भारत टैक्सी एप से चार लाख से ज्यादा लोग जुड़े

नई दिल्ली: सहकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित भारत टैक्सी सेवा को लोगों की मजबूत प्रतिक्रिया मिल रही है। सहकारिता मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि इस एप से पिछले दो दिनों में हर रोज लगभग 40-45 हजार नए यूजर्स ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही एप पर चार लाख से ज्यादा यूजर्स का पंजीकरण हो गया है। मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी को मौजूदा टैक्सी चालकों के लिए एक सहकारी विकल्प के रूप में औपचारिक रूप से लांच किया गया था। यह एक पारदर्शी और ड्राइवर-फ्रेंडली प्लेटफार्म है। (आइएएनएस)

टैरिफ फिर बढ़ा तो रुपये और निर्यात पर दिखेगा असर

अमेरिका ने पिछले साल भारतीय आयात पर लगाया था 50 प्रतिशत टैरिफ, गारमेंट और लेदर जैसे क्षेत्र हुए थे प्रभावित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक और भविष्य में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर और टैरिफ लगाने की धमकी अगर सच साबित होती है तो शेयर बाजार, डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में और गिरावट दिखाई देगी। इतना ही नहीं रोजगारपरक सेक्टर के अमेरिका को होने वाला निर्यात भी प्रभावित हो सकता है।

पिछले साल अगस्त से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क लागू है। उसके बाद से अमेरिकी बाजार में गारमेंट, लेदर आइटम, जेम्स व ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे रोजगारपरक सेक्टर के निर्यात की वृद्धि दर घटी है। पिछले साल मई-जून की तुलना में सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट दर्ज की गई। मोबाइल, फार्मा जैसे कुछ उत्पादों को ट्रंप सरकार ने शुल्क से मुक्त रखा है,

- पिछले साल मई-जून की तुलना में सितंबर-अक्टूबर में अमेरिका को होने वाले निर्यात में आई गिरावट
- पिछले साल ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया
- फिर से अमेरिकी टैरिफ बढ़ने पर भारत को उसकी भरपाई के लिए नए बाजार तलाशने होंगे

इसलिए इनके निर्यात में बढ़ोतरी से कुल निर्यात को समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में अब भी वृद्धि दिख रही है।

व्यापार समझौते को लेकर अमेरिका के उतार-चढ़ाव वाले रुख को भारत पहले ही भांप गया था, इसलिए उसने पिछले साल से ही अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश तेज कर दी थी। इसका नतीजा भी दिखने लगा और अब भारत दुनिया के 200 बाजारों में निर्यात करने लगा है। पिछले साल ब्रिटेन, ओमान व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया और इस साल इन समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा। इससे इन देशों में भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और भारत का निर्यात बढ़ेगा। अमेरिकी चुनौतियों को देखते हुए भारत निर्यात प्रोत्साहन योजना भी शुरू कर चुका है। टैरिफ की काट अब तक तो सफल रही है लेकिन फिर से टैरिफ बढ़ता है तो उसकी भरपाई के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।

एफआइआइ की भारी मात्रा में बिकवाली

अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद ही डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य में ह्रास होना शुरू हुआ और एक डालर का मूल्य 90 रुपये के पार चला गया। सरकार के अधिकारियों से लेकर बाजार विशेषज्ञ तक कई बार यह बयान दे चुके हैं कि भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बाद रुपये में मजबूती आएगी। ट्रंप की नई धमकी से रुपये में और कमजोरी आ सकती है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के नए बयान के बाद विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) भी भारतीय बाजार से निकलेंगे, जिससे शेयर बाजार प्रभावित हो सकता है। पिछले साल अगस्त के बाद से भारतीय बाजार से भारी मात्रा में एफआइआइ की निकासी हुई। वर्ष 2025 में तीन लाख करोड़ एफआइआइ की बिकवाली की गई।

शुल्क बढ़ने पर अमेरिकी आर्डर में आएगी और कमी

गारमेंट और जेम्स व ज्वेलरी के निर्यातकों ने बताया कि टैरिफ बढ़ाने की नई धमकी के बाद अमेरिकी खरीदार उन्हें थोड़े बहुत जो भी आर्डर दे रहे थे, उसे भी रोक देंगे। पिछले छह महीनों से भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने की चर्चा तो चल रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं होने से अमेरिकी खरीदार असमंजस की स्थिति में है। 50 प्रतिशत शुल्क के साथ वे भारतीय निर्यातकों को अधिक आर्डर नहीं दे रहे हैं और शुल्क बढ़ने पर इस आर्डर में और कमी आएगी।

भारत कृषि और डेरी बाजार खोलने को तैयार नहीं

सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के लिए अपने कृषि और डेरी बाजार को खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वजह से भी अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते को टाल रहा है। अमेरिका भारत में अपने जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन और मक्के को बेचना चाहता है, लेकिन भारत किसानों के हितों को देखते हुए किसी भी सूरत में इन वस्तुओं की बिक्री की इजाजत देने के पक्ष में नहीं है।

चार प्रतिशत के महंगाई लक्ष्य को बरकरार रख सकती है सरकार

नई दिल्ली, रायटर: वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार आरबीआइ के लिए चार प्रतिशत महंगाई के लक्ष्य को बरकरार रख सकती है। आरबीआइ अपना लक्ष्य प्रत्येक पांच साल में तय करता है और यह समयावधि मार्च में पूरी होनी है। ऐसे में महंगाई को सहनीय क्षमता यानी चार प्रतिशत के अंदर रखना जरूरी है।

पिछले साल सितंबर में रायटर ने बताया था कि आरबीआइ फ्रेमवर्क का समर्थन करने वाले सभी हितधारकों से मिले फीडबैक के बाद मौजूदा महंगाई लक्ष्य को लगातार तीसरी बार बनाए रखने की सिफारिश करेगा। भारत ने महंगाई लक्ष्य फ्रेमवर्क को अपनाया और 2016 में आरबीआइ को औपचारिक रूप से इसका काम सौंपा। 2021 में इसका नवीनीकरण किया गया। पिछले एक दशक में तीन-चौथाई समय महंगाई तय लक्ष्य के अंदर रही और महामारी के समय के दौरान इसमें उतार-चढ़ाव सबसे ज्यादा था।

स्पैम काल रोकने में विफल रहने पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पैम काल और मैसेज पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर दूरसंचार कंपनियों पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 2020 से 2023 की समयावधि के लिए यह जुर्माना लगाया गया है और इस पेनाल्टी को दूरसंचार कंपनियों ने चुनौती दी है। ट्राई ने पिछले साल 21 लाख से ज्यादा स्पैमर्स (स्पैम काल करने वाले) के नंबर को डिसकनेक्ट किया है और एक लाख से ज्यादा संस्थाओं को कालीसूची में डाला है।

ट्राई द्वारा 13 अगस्त, 2024 को जारी किए गए निर्देश के बाद, सितंबर 2024 में लगभग 18.8 लाख स्पैमर्स के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए और 1,150 से ज्यादा संस्थाओं को कालीसूची में डाला गया। ट्राई ने एक डीएनडी एप शुरू किया है, जिससे यूजर्स सिर्फ चार से छह क्लिक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नियामक ने शिकायत करने की समयसीमा भी तीन से बढ़ाकर सात दिन कर दी है। यानी कोई व्यक्ति काल या एसएमएस मिलने के सात दिनों के अंदर परेशान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

- दूरसंचार नियामक ट्राई ने 2020 से 2023 की अवधि के लिए लगाया यह जुर्माना
- ट्राई ने पिछले साल स्पैम काल करने वाले 21 लाख से ज्यादा नंबर को डिसकनेक्ट किया

खाद सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली, आइएएनएस: मौजूदा रबी सीजन के दौरान सरकार खाद की सब्सिडी पर 37,952 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह खरीफ सीजन के दौरान खाद पर खर्च किए गए फंड से 736 करोड़ रुपये ज्यादा है।

सरकार ने रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दामों को मंजूरी दे दी है, जो एक अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगी। इसमें डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फास्फेट और पोटाश आधारित खाद शामिल है। खेती-बाड़ी के सेक्टर के लिए केंद्र की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम की वजह से घरेलू उर्वरक उत्पादन में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2014 के 112.19 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2025 में 168.55 लाख मीट्रिक टन हो गया है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए 2022-23 और 2024-25 में 2.04 लाख करोड़ रुपये दिए गए।

पीएलआइ के तहत 50 अरब डालर के आइफोन का निर्यात

नई दिल्ली, प्रेट्र: अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एपल ने भारत की स्मार्टफोन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उद्योग जगत से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2025 तक कंपनी का आइफोन निर्यात 50 अरब डालर को पार कर गया है। यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एपल के पांच साल के पीएलआइ कार्यक्रम में पूरा होने में अभी तीन महीने बाकी हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में आइफोन का निर्यात लगभग 16 अरब डालर रहा। इसके मुकाबले, सैमसंग ने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पीएलआइ स्कीम के तहत लगभग 17 अरब डालर के डिवाइस निर्यात किए।

एपल के देश में पांच आइफोन असेंबली प्लांट हैं। इसमें से तीन टाटा ग्रुप द्वारा संचालित किए जाते हैं और दो का संचालन ताइवान की कंपनी फाक्सकान करती है। इन पांचों कंपनियों को लगभग 45 कंपनियों से सप्लाई चेन का सपोर्ट मिलता है। आइफोन की बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 75 प्रतिशत है और वित्त वर्ष 2024-25 में यह भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी में शामिल हो गया। 2015 में यह निर्यात श्रेणी में 167वें रैंक पर था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादनकर्ता बन गया है और अब देश में बिकने वाले 99 प्रतिशत से ज्यादा फोन मेड इन इंडिया हैं। स्मार्टफोन पीएलआइ स्कीम मार्च, 2026 में खत्म होने वाली है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार के विकल्प के तौर पर दूसरी योजना ला सकती है।

एपल ने 2025 के पहले 11 महीनों में 65 लाख आइफोन16 बेचे थे : एपल के सप्लायर और सैमसंग को भी इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम के तहत चुना गया था, जिसमें सैमसंग एक डिस्प्ले माड्यूल सब असेंबली यूनिट लगाएगा। इसमें लगभग 300 लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है। काउंटरपाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एपल ने 2025 के पहले 11 महीनों में लगभग 65 लाख आइफोन16 यूनिट बेचे, जिससे यह देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया।

- अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलाजी कंपनी एपल ने प्रोत्साहन योजना का खूब लाभ उठाया
- सैमसंग ने पांच वर्षों में योजना के तहत 17 अरब डालर के डिवाइस निर्यात किए

इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात में हुई आठ गुना वृद्धि: वैष्णव

केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रानिक्स का उत्पादन छह गुना बढ़ा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में निर्यात में आठ गुना की वृद्धि हुई है। एक्स पर एक पोस्ट में वैष्णव ने कहा कि भारत पूरे इलेक्ट्रानिक्स स्टैक यानी डिजाइन, मैन्यूफैक्चरिंग, आपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन, मटीरियल और इक्विपमेंट एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। मेक इन इंडिया और उत्पादक इकोनमी बनने की कोशिश का ही नतीजा है कि एपल ने 50 अरब डालर के आइफोन निर्यात किए हैं।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

पीएम मोदी को अजमेर शरीफ पर 'चादर' चढ़ाने से रोकने की याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर एक औपचारिक 'चादर' चढ़ाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि यह अदालत इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी क्योंकि यह मुद्दा न्यायालयीय नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। (प्रेट्र)

रिसार्ट में 35 अभ्यर्थियों ने की थी लीक पर्चे से तैयारी

रायपुर: रायपुर से लगभग 125 किमी दूर बारनवापारा के घने जंगलों में सीजीपीएससी (छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग) भर्ती घोटाले की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। सीबीआइ की अंतिम चार्जशीट में राजफाश हुआ है कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी ने 35 चयनित अभ्यर्थियों को जंगल के एक रिसार्ट में ठहराकर परीक्षा की विशेष तैयारी कराई। कोचिंग संचालक उत्कर्ष चंद्राकर ने इसमें सहयोग किया। इसी रिसार्ट में प्रश्नपत्र लीक करने और चयन सूची तैयार करने की योजना बनाई गई। जांच में सामने आया कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों, नेताओं और प्रभावशाली परिवारों से जुड़े अभ्यर्थियों का चयन किया गया। (राब्यू)

आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं में ड्रिलिंग के दौरान गैस रिसाव से आग लगी

मोरी (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के डा. बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले में सोमवार को ओएनजीसी के एक तेल के कुएं में गैस पाइपलाइन के रिसाव से आग लग गई। चार किमी के दायरे में स्थित तीन गांवों से लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ओएनजीसी के अधिकारी ने कहा, मोरी-5 कुएं में गैस पाइपलाइन के रिसाव के कारण आग लगी। इसे दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था। गैस रिसाव दोपहर करीब 12.20 बजे ड्रिलिंग कार्य के दौरान हुआ। दोपहर करीब 12.40 बजे कुएं से 500 मीटर के क्षेत्र में फैली गैस के रिसाव से आग लग गई। जिला प्रशासन के अनुसार, गैस के कुएं से निकली लपटें 20 मीटर ऊंची थीं। (प्रेट्र)

लालू के विरुद्ध ट्रायल पर रोक लगाने से हाई कोर्ट ने किया इन्कार

जासं, नई दिल्ली: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) घोटाला मामले में आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर उनके खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाने से सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। लालू यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि सीबीआइ का जवाब सुने बिना अदालत रोक लगाने वाली अर्जी पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। पीठ ने सीबीआइ को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि सीबीआइ द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद 14 जनवरी को इस अर्जी पर विचार करेगा। ट्रायल कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को लालू यादव, उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे।

सुप्रीम कोर्ट एनसीएलटी की केस ट्रांसफर करने की शक्ति जांचेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले की जांच करने पर सहमत हो गया, जिसमें कहा गया था कि नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) किसी लंबित याचिका को राज्य के बाहर किसी दूसरी एनसीएलटी पीठ में स्थानान्तरित नहीं कर सकता।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ एनसीएलटी अध्यक्ष की अलग-अलग राज्यों में स्थित एनसीएलटी की पीठों में केस स्थानान्तरित करने की शक्ति की जांच करने पर सहमत हो गई। यह विवाद एनसीएलटी नियम, 2016 के नियम 16(डी) से शुरू हुआ है, जो एनसीएलटी अध्यक्ष को परिस्थितियों के अनुसार किसी भी मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह शक्ति सिर्फ राज्य के भीतर के पीठों में स्थानान्तरित करने की है। हाई कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी के अध्यक्ष केंद्र द्वारा स्थापित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को बदल या बढ़ा नहीं सकते। शीर्ष अदालत ने पहली नजर में इस रुख पर संदेह जताया और एक काल्पनिक उदाहरण दिया कि अगर किसी सदस्य को ऐसी जगह पर खुद को अलग करना पड़ता है जहां सिर्फ एक पीठ है, तो कार्यवाही को ठप होने से रोकने का एकमात्र तरीका केस को राज्य के बाहर ट्रांसफर करना हो सकता है। अहमदाबाद में एनसीएलटी की दो पीठों ने आर्सेलरमित्तल से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद दिल्ली में एनसीएलटी अध्यक्ष ने एक आदेश पारित कर मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया था।

- गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था, ट्रिब्यूनल को अधिकार नहीं
- अध्यक्ष को है केस दूसरी पीठ में ट्रांसफर करने का अधिकार

पढ़ाई पूरी कराने अब उद्योग और आइटीआइ में भी लगेगी कक्षाएं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पढ़ाई बीच में छोड़कर किसी कंपनी में काम कर रहे या फिर आइटीआइ में प्रशिक्षण ले रहे लोगों को पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर उद्योगों, आइटीआइ या फिर ऐसे परिसरों में एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) केंद्र खोलने की अनुमति देने की तैयारी में है, जहां 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी एनआइओएस केंद्रों को सिर्फ शैक्षणिक परिसरों में खोलने की अनुमति है।

मंत्रालय के अनुसार, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, जो12वीं तक पढ़ाई पूरी किए बिना काम कर रहे हैं। इनको पढ़ाने के लिए काम के बाद अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएंगी। पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी उद्योगों में एक बड़ी श्रम शक्ति पांचवीं, आठवीं या दसवीं तक की पढ़ाई के बाद काम कर रही है।

मोबाइल में रील देखते समय 10 वर्षीय बच्चे की मौत

जासं, अमरोहा : स्मार्टफोन में रील देखते-देखते अमरोहा के 10 वर्षीय मयंक ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम कराए बिना ही स्वजन ने अंतिम संस्कार करा दिया। ऐसे में जान किस वजह से गई, यह स्पष्ट नहीं हो सका। हां, मृत घोषित करने वाले चिकित्सक डा.अवनीश गिल हार्ट फेल होने को ही मौत का कारण मान रहे हैं। पिता दीपक कुमार के मुताबिक मयंक पूरे दिन में महज दो घंटे ही मोबाइल फोन चलाता था, ऐसे में अंदेशा है कि कोई चौंकाने या डराने वाली रील मयंक ने देख ली और उसका हार्ट फेल हो गया।

उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले के जुझैला चक में किसान दीपक कुमार पत्नी पुष्पा देवी व दो बेटे मयंक व शिवम के साथ रहते थे। 10 वर्षीय बड़ा बेटा मयंक कक्षा चार का छात्र था। रविवार शाम लगभग पांच बजे वह घर में पलंग पर बैठकर स्मार्टफोन में रील देख रहा था। करीब 15 मिनट बाद वह बेसुध होकर गिर पड़ा। स्वजन उसे गिल अस्पताल ले गए। यहां मयंक को मृत घोषित कर दिया। पिता दीपक कुमार ने बताया कि मयंक सामान्य रूप से स्वस्थ था। डा. अवनीश गिल ने बताया कि मयंक के स्वजन ने पूछताछ में बताया था कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में हार्ट अटैक से ही मौत होने की आशंका है।

रेडिएशन का भी पड़ता दिल-दिमाग पर असर

जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा. ए. कुमार ने बताया कि बच्चों का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसके अलावा वह बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन सीधे दिमाग को प्रभावित करता है। इसका असर हृदय पर भी पड़ता है।

ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा संशोधन पर विचार करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए वेतन सीमा के संशोधन पर चार महीने के भीतर निर्णय लेने पर विचार करे।

जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने नवीन प्रकाश नौटियाल द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जोकि कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है, वर्तमान में उन लोगों को कवरेज से बाहर रखता है जिनकी वेतन राशि 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने कहा कि वेतन संशोधन पिछले एक दशक से नहीं हुआ है, जबकि केंद्र और कई राज्यों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन ईपीएफओ की 15,000 रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा से अधिक है।

शीर्ष कोर्ट न्यायिक अधिकारियों पर आरोपों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद कर दिया, जिन पर एक्साइज एक्ट के तहत आरोपितों को जमानत देने में भिन्न मापदंड अपनाने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप था। पीठ ने ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोपों की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीरता से ध्यान दिया और ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी को 27 वर्षों की ''दाग रहित'' सेवा के बाद उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त किया गया। शीर्ष अदालत ने अवलोकन किया, ''यह कारण है कि ट्रायल कोर्ट के अधिकारी जमानत देने में हिचकिचाते हैं और उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट पर जमानत याचिकाओं का बोझ बढ़ता है।'' हालांकि, उसने भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई समेत कठोर कार्रवाई करने का समर्थन किया ताकि न्यायपालिका से ''काली भेड़'' को बाहर निकाला जा सके। पीठ ने यह भी बताया कि बार के सदस्य भी न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने में लिप्त हैं और चेतावनी दी कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

जस्टिस पार्डीवाला ने निर्णय से सहमति जताते हुए जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखित निर्णय की सराहना की, इसे ''बहुत साहसी निर्णय'' बताते हुए कहा कि यह ईमानदार न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया को उनकी सेवा से सेवानिवृत्ति तक पूर्ण मौद्रिक लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया और सितंबर 2015 के बर्खास्तगी आदेश और उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद कर दिया जिसने उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा।

- मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद किया
- जमानत देने में भिन्न मापदंड अपनाने का था आरोप

विकसित भारत के लिए करने होंगे नए सुधार : प्रो. विकास

जागरण विमर्श

रवि पाल • जागरण

नोएडा: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती और रफ्तार के साथ आगे लेकर जाना होगा। 12 लाख रुपये तक आय कर मुक्त करने और जीएसटी दरें घटाने के बाद अब नए सुधारों की जरूरत है। अगले पांच वर्षों में देश के आम आदमी को स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना होगा। देश के करीब 70 प्रतिशत कर्मचारियों समेत गिग वर्कर्स का करीब 95 प्रतिशत खर्च रोजमर्रा की जरूरतों पर हो रहा है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर आनलाइन चर्चा के दौरान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आइआइपीए) के प्रोफेसर व अर्थशास्त्री विकास सिंह ने ये बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती, टैरिफ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने जैसे विषयों पर विचार रखे। कहा कि भारत में युवाशक्ति की कमी नहीं है। वर्ष 2035 तक देश के युवाओं का अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान हो सकता है।

फिलहाल, देश की इकोनमी लोअर इनकम इकोनमी है, इसे मिडिल इनकम इकोनमी तक ले जाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन, ब्राजील जैसे देश भी मिडिल इनकम इकोनमी तक ही पहुंच पाए हैं। वर्ष 2025 से चीन की जनसंख्या में कमी होने के साथ ही उसकी विकास दर में भी कमी आई है, लेकिन भारत के पास अगले 10 वर्षों तक सुनहरा अवसर है। हाई इनकम इकोनमी भी भारत बन सकता है। विकास सिंह ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में नए सुधार करने पर जोर दिया।

भूमि सुधारों से बढ़ सकती है जीडीपी : प्रो. सिंह ने बताया कि देश में भूमि सुधारों के जरिये किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सकता है। मौजूदा वक्त में किसानों का अर्थव्यवस्था में योगदान 16 प्रतिशत है। सुधारों के जरिये इसे बढ़ाकर 22 से 23 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इससे भारत की विकास दर सात प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत तक हो सकती है। नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिल सकता था, उसे समझने की जरूरत है। फरवरी में पेश होने वाले बजट पर सरकार इस मुद्दे पर जरूर ध्यान देगी।

ट्रंप टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं : प्रो. विकास सिंह ने बताया कि भारत पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। देश का निर्यात यूएस में 2.5 प्रतिशत है, लेकिन टैरिफ की बढ़ी दरों को देशहित में कम करने के लिए अमेरिका से बातचीत जारी रखनी होगी। टैरिफ दरें कम होने से भारत का निर्यात और बढ़ेगा। देश की करीब 60 फीसदी इकोनमी डोमेस्टिक है। ट्रंप के टैरिफ का चीन और पश्चिमी देशों पर ज्यादा प्रभाव है।

एमएसएमई को और बढ़ावा देना होगा : देश में करीब सात करोड़ एमएसएमई उद्यमी हैं। करीब 99 प्रतिशत छोटे उद्यमों में एक या दो कर्मी ही काम कर रहे हैं। जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 29 से 30 प्रतिशत है, जबकि एक्सपोर्ट में 25 से 30 प्रतिशत योगदान है। प्रो. सिंह ने इसे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि एमएसएमई और देश की बड़ी कंपनियों के बीच बड़ा खालीपन है। एमएसएमई को बढ़ावा देकर इस खालीपन को भरकर बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करानी होगी। जिससे एमएसएमई क्षेत्र में 70 प्रतिशत नौकरियों को बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक किया जा सके।

- अर्थशास्त्री बोले, जीएसटी और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद नए सुधार की जरूरत
- कहा- अगले पांच वर्षों में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में आम आदमी को निवेश बढ़ाना होगा

प्रोफेसर विकास सिंह

देश में नए क्षेत्रों को संगठित तौर पर आगे लाना होगा

प्रो. सिंह ने बताया कि देश में मैन्यूफैक्चरिंग से अब ज्यादा नौकरी नहीं मिल पा रही हैं। पहले एक करोड़ रुपये के निवेश से सात नौकरी मिल रही थी, अब ये घटकर चार रह गई हैं। इसलिए नए क्षेत्रों को आगे लाना होगा। देश में कंस्ट्रक्शन कंपनियों, टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक भी बड़ी कंपनी निफ्टी में लिस्टेड नहीं है। इन क्षेत्रों को संगठित तौर पर आगे लाना होगा।

रेयर अर्थ मटीरियल पर निवेश का समय अच्छा

रेयर अर्थ पर चर्चा करते हुए प्रो. सिंह ने बताया कि देश ने रेयर अर्थ पर निर्भरता को कम करने के लिए सही समय पर कदम उठाए हैं। ट्रंप टैरिफ और चीन से फिलहाल किसी भी मोर्चे पर उलझने की बजाय सरकार इसमें निवेश पर फोकस कर रही है। इसका अच्छा प्रभाव अगले चार से पांच वर्षों में देखने को मिल सकता है।

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

ढाका का रवैया

आज विश्व में नाना प्रकार के तनाव हावी हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे निकटतम तनाव की वजह बांग्लादेश बना हुआ है। तनाव की सबसे ताजा कारण क्रिकेट जैसा खेल बन गया है। पड़ोसी देश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्रसारण व स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। बेशक, पड़ोस की कार्यवाहक सरकार अपने तमाम फैसले आवेश में ले रही है और खासकर भारत संबंधी फैसलों में पड़ोसी सरकार को न तो अपना तात्कालिक हित दिख रहा है और न दूरगामी हित। इससे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कोई खास घाटा नहीं होगा, मगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को जरूर निराशा होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बोर्ड है, इसका लाभ दूर देश के खिलाड़ी तो उठा रहे हैं, पर दो पड़ोसी देशों के खिलाड़ी वंचित हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी मुंबई हमले के बाद से आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है और अब हालात ऐसे ही रहे, तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए भी आईपीएल में खेलना दूर की कौड़ी हो जाएगा।

यह बहुत अफसोस की बात है कि हमारा यह पड़ोसी देश हमारी चिंताओं को समझने में नाकाम हो रहा है। बांग्लादेश की ताजा प्रतिक्रिया भी इसी ओर इशारा कर रही है।

जब पड़ोसी बांग्लादेश से लेकर वेनेजुएला तक दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही हो, तब भारत में लिए जा रहे तमाम फैसलों में परिपक्वता और बढ़ जानी चाहिए।

कार्यवाहक सरकार यह समझना नहीं चाहती कि बीसीसीआई ने यह फैसला क्यों लिया है? आज बांग्लादेश के लोगों को ठेस पहुंची है, वे दुखी और आहत हैं। हालांकि, सवाल तो यह है कि क्या बांग्लादेश के तल्ख बर्ताव से भारत को मुसलसल ठेस नहीं पहुंच रही है? यहां भी लोग दुखी और आहत हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, उसे लेकर भारत में स्वाभाविक ही नाराजगी है। लोग यह पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश को भारत की कोई परवाह नहीं है, तब बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका देकर 9.20 करोड़ रुपये क्यों दिए जाएं? यहां यह भी देखना वाजिब होगा कि बांग्लादेश के स्थानीय प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे खिलाड़ियों को भी पचास लाख रुपये के आसपास ही मिल पाते हैं। लगे हाथ, पाकिस्तान सुपर लीग की भी चर्चा कर लें, तो वहां सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 2.7 करोड़ रुपये मिले हैं। कमाई और खर्च के मामले में आईपीएल बहुत आगे है, उसकी तुलना किसी भी दूसरे लीग से नहीं हो सकती। यह बहुत अफसोस की बात है कि अच्छे संबंध बनाकर दोनों देशों को भारत की संपन्नता का लाभ लेना चाहिए, लेकिन दोनों ही अपनी संकीर्ण सोच की वजह से अपने ही खिलाड़ियों या लोगों का नुकसान कर रहे हैं।

यह तो और भी ज्यादा अफसोस की बात है कि रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीसी) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह टी-20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करे। संभव है, बीसीसीआई इसके लिए तैयार हो जाए, मगर इससे भी बांग्लादेश को नुकसान होगा। जहां तक भारत का सवाल है, वैश्विक मोर्चे पर व्यावहारिकता को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। जब पड़ोस से लेकर वेनेजुएला तक दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही हो, तब भारत में लिए जा रहे तमाम फैसलों में परिपक्वता और बढ़ जानी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 06 जनवरी, 1951

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हो गया है। यह सम्मेलन दस दिन तक जारी रहेगा। उसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, लंका, दक्षिण रोडेनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों में केवल पाकिस्तान ही ऐसा है, जिसके प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने अभी तक लंदन सम्मेलन में भाग लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। श्री लियाकत अली ने यह आग्रह किया था कि लंदन सम्मेलन के विचारणीय विषयों की सूची में काश्मीर के प्रश्न को भी शामिल किया जाये। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन की मर्यादाओं को सभी जानते हैं। राष्ट्रमंडल एक ढीला-ढाला संगठन है। उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह अपने किन्हीं निर्णयों को मानने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाध्य कर सके। वह एक ऐसा मंच है, जहां सदस्य राष्ट्र विचार-विनिमय के लिए एकत्र होते हैं और समान हित से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर पारस्परिक सहयोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों ने यह परम्परा डाल ली है कि ऐसे मतभेद के विषयों पर, जो दो देशों से संबंध रखते हों, प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा न की जाये। यह परम्परा व्यावहारिक और बुद्धिमानी की सूचक है। यह सब जानते-बूझते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काश्मीर के प्रश्न को लंदन सम्मेलन की विषय सूची में बाकायदा शामिल करने का आग्रह किया और आग्रह भी इस हद तक कि यदि उसे न माना जाये, तो वह लंदन सम्मेलन का बहिष्कार कर देंगे, आश्चर्य का ही विषय हो सकता है।

काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सिपुर्द है। राष्ट्रमंडल संगठन विधिवत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न भारत को ही यह मंजूर हो सकता है कि वह इस प्रकार हस्तक्षेप करे। यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रमंडल के देश बहुमत के जोर पर भारत पर दबाव डाल कर हल कर सकें। भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई हल उस पर नहीं थोपा जा सकता। राष्ट्रमंडल के देशों की यह स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि मौजूदा नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान लंदन सम्मेलन से अपने को अलग न रखे और उसकी महत्वपूर्ण चर्चाओं में उचित भाग ले।

जंगों के नए दौर में उलझती दुनिया

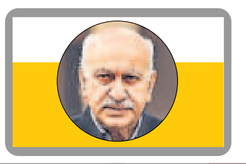

यहां स्कैन करें

एम जे अकबर | पूर्व विदेश राज्य मंत्री व वरिष्ठ पत्रकार

वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई से उन तमाम देशों का दुस्साहस बढ़ेगा, जिनका साम्राज्यवादी एजेंडा अब तक अधूरा है। ऐसे देश आक्रामक रुख अपना सकते हैं।

पिछले ही हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई थी कि यदि रूस-यूक्रेन जैसे संघर्ष जल्द खत्म नहीं किए गए, तो दुनिया तीसरे महायुद्ध में फंस सकती है। मगर उन्होंने खुद वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सपत्नी बंधक बना लिया और वहां नई सरकार के गठन का एलान कर दिया, जिसे अमेरिका चलाएगा। यह एक देश का 'कॉरपोरेट टेकओवर' है, क्योंकि खुद ट्रंप के ही शब्द हैं, 'उन्हें वेनेजुएला का तेल चाहिए'।

इस घटना से उन देशों को साहस मिलेगा, जिनका एजेंडा अब तक 'अधूरा' है। यूक्रेन के कई इलाकों पर अधिकार जमाने का एलान रूस ने किया है, जबकि चीन की मंशा 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने की है। अब अमेरिका किस मुंह से इनको रोकने के लिए आगे आएगा? पहली झलक में तो यही लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ यूरोप की है, मगर क्रीमिया और यूक्रेन के पूरब में चेचन्या है। चेचन्या से कॉकेशस होते हुए हम सीरिया और पश्चिम एशिया में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं, यानी यह यूरेशियाई युद्ध है।

वास्तव में, इस समय भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर के बीच जितने भी इलाके हैं, वे सभी युद्ध में फंसे हुए हैं। यहां इजरायल-हमास जंग, इजरायल-लेबनान तनाव, काकेशस संघर्ष (खासकर आर्मेनिया, अजरबैजान से ईरान का तनाव), वेनेजुएला के घटनाक्रम से ऐन पहले यमन पर सऊदी अरब का हमला, फ्रांस व ब्रिटेन की इराक व सीरिया के आईएस ठिकानों पर बमबारी (वेनेजुएला हमले के दिन) के रूप में तनाव के मोर्चे खुले हुए हैं। उत्तर कोरिया और जापान की ताजा तनातनी को भी इसमें गिन सकते हैं।

सवाल उठता है, क्या यह तीसरे विश्व-युद्ध की आहट है? मेरी नजर में यह 'वर्ल्ड वार' नहीं, 'वर्ल्ड वाइड वार' है, यानी हर महाद्वीप में जंग वाले हालात।

इसकी वजह भी है।

दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में शांति व स्थिरता लाने के लिए जितने भी संस्थान बने, वे सभी बेमानी साबित हो रहे हैं। सन् 1945 में दूसरे महासमर का अंत ही नहीं हुआ था, बल्कि औपनिवेशिक देशों में आजादी का आगाज भी हुआ था। इसकी शुरुआत भारत से हुई थी, जब महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आंदोलन ने बरतानिया हुकूमत का झंडा झुका दिया। उन दिनों अंग्रेज और अंग्रेजीदां हंसते थे कि क्या धोती पहनकर भी कोई 'महान ब्रिटिश साम्राज्य' को झुका सकता है? वे अगले 300 वर्षों तक उस हुकूमत के चलने की भविष्यवाणी किया करते थे। मगर 1920 के बाद वह साम्राज्य 30 साल भी नहीं चला और 1947 के बाद तो अगले तीन दशकों में दुनिया के हर कोने से ही उपनिवेशवाद खत्म हो गया। प्रायः सभी देशों को आजादी अहिंसा के रास्ते ही मिली।

उस वक्त संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे तमाम संस्थान गढ़े गए और इनमें हरेक मुल्क का होना यह आश्वासन था कि उनकी संप्रभुता और आजादी अक्षुण्ण रहेगी, बेशक वे अमीर हों अथवा गरीब। मगर 1990 के बाद, खास तौर से 21वीं सदी की शुरुआत से ये तमाम संस्थान बेअसर होने लगे, क्योंकि ताकतवर देशों ने अपने लिए या विश्व-हित में उस नीति को तोड़ना शुरू किया, जिसमें किसी दूसरे देश में दखल न देने की बात कही गई थी। वि-उपनिवेशीकरण से हुए बदलाव को बड़ी ताकतें मानने को तैयार नहीं हुईं, जैसे- चीन ने तिब्बत की आजादी नहीं मानी; वियतनाम विभाजन मानने को तैयार नहीं हुआ और सूडान में जो कुछ हुआ, वह तो जगजाहिर ही है।

वेनेजुएला घटनाक्रम इस सच्चाई को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप उसी 'मोनरो नीति' का पालन कर रहे हैं, जिसे साल 1823 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने उस वक्त की भौगोलिक हकीकत के आधार पर तैयार किया था। उस जमाने में पूरा दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका का अधिकतर हिस्सा यूरोप का उपनिवेश था। मोनरो ने दावा किया था कि उत्तरी हिस्सा तो अमेरिका का है ही, दक्षिणी अमेरिका पर भी अब विदेशी हित स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वह उनका 'आंगन' है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 19वीं सदी की नीति क्या 21वीं सदी में प्रासंगिक साबित होगी?

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें अगर कुछ चाहिए, तो वह साम-दाम-दंड-भेद, सबका इस्तेमाल करके उसे अपने कब्जे में लेना पसंद करेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और कानून निरर्थक हैं। वेनेजुएला में जो हुआ है, वह इसी संदेश को पुख्ता कर रहा है। 'अमेरिका ही असल संयुक्त राष्ट्र है' यह बात राष्ट्रपति ट्रंप कहते भी रहे हैं। अब क्या वह ग्रीनलैंड जाएंगे? यूरोपीय देशों के सामने यह दुविधा भी खड़ी हो गई है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात ट्रंप मजाक में कहते रहे हैं या वाकई उनकी यह मंशा है? नया घटनाक्रम यूक्रेन को भी एक संदेश है। अगर अमेरिका पड़ोस में अपने हित संभालने को स्वतंत्र है, तो रूस भी यह अधिकार रखता है। इससे कीव की हिम्मत और पस्त हो सकती है।

दूसरी बात। वेनेजुएला की एक सच्चाई यह है कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 300 अरब बैरल। इसके बाद सऊदी अरब (लगभग 265 अरब बैरल) का स्थान आता है। अमेरिका के पास बमुश्किल 35 अरब बैरल तेल है। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अमेरिका के पास तेल बाजार को नियंत्रित करने की ताकत आ जाएगी। अब तेल ही नहीं, खनिज भी काफी महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से सेमीकंडक्टर और चिप के लिए, तो जाहिर सी बात है कि तेल व खनिज की राजनीति अधिक परवान चढ़ेगी। पिछले 100 साल में आधे से अधिक जंग तेल के कारण ही हुए हैं।

रही बात भारतीय नीति की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी यह समझते हैं कि आंतरिक ताकत जुटाए बिना कोई भी देश आजाद नहीं रह सकता। आज कई सारे देश स्वतंत्र तो हैं, लेकिन 'आजाद' नहीं हैं। हमें आजाद भी रहना है और संप्रभु भी, जो बिना सामरिक ताकत और राजनीतिक इच्छाशक्ति के संभव नहीं है। 'टैरिफ जंग' में ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से टकराने की कुव्वत रखते हैं। वह मौजूदा विश्व-व्यवस्था को समझ रहे हैं।

यह घटनाक्रम बता रहा है कि 2026 में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। दिक्कत यही है कि जिन संस्थानों पर इसे संभालने की जिम्मेदारी थी, वे खत्म कर दिए गए हैं। इस कारण यदि यह सदी का सबसे खतरनाक साल बन जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अपनी आंतरिक खींचतान से परेशान तमिल पार्टियां

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह पिछले सप्ताहांत तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक गठबंधन के खिलाफ मजबूत चुनावी मोर्चा खड़ा करने की कोशिशें कीं। असल में, मोदी-शाह के लिए तमिलनाडु आज भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है, जिसे वे सुलझा नहीं पा रहे हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर असंतोष जताया था। इसलिए तमिलनाडु की इस मुश्किल पहेली को सुलझाने का जिम्मा अब अमित शाह के कंधों पर आ गया है। शाह वहां एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह एक ऐसा बड़ा गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिसमें भाजपा, अन्नाद्रमुक व इसके सभी बागी गुट, पीएमके, डीएमडीके, एएमएमके और कुछ ऐसे छोटे दल शामिल हों, जो पिछले एनडीए सरकार में साथ थे। दुर्योग से, साल 2024 के संसदीय चुनावों के तुरंत बाद राज्य में टूटा एनडीए फिर से एकजुट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एकमात्र राहत की बात रही कि अन्नाद्रमुक पार्टी वापस शामिल हो गई है, लेकिन भाजपा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पार्टी को अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की बलि देनी पड़ी, जो सत्तारूढ़ द्रमुक के मुखर आलोचक के रूप में उभर रहे थे।

साल 2021 में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच वोटों का अंतर 20.39 लाख या 4.41 प्रतिशत का था, इस बार जीत का अंतर कम हो सकता है।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ द्रमुक एक मजबूत गठबंधन तो बनाए हुए है, पर उसे अपने सहयोगियों की ओर से अधिक सीटों व चुनाव बाद सत्ता में हिस्सेदारी की मांग का दोहरा दबाव झेलना पड़ रहा है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में 97.37 लाख वोटरों के नाम सूची से कट चुके हैं। इससे अन्नाद्रमुक व द्रमुक में तहलका मचा हुआ है। उधर अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी की जोरदार धमक ने स्थिति को और उलझा दिया है। एक हालिया चुनाव सर्वे के अनुसार, द्रमुक गठबंधन सत्ता में वापसी कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर एम के स्टालिन के बाद विजय दूसरी सबसे बड़ी पसंद बन गए हैं, अन्नाद्रमुक के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ए पलानीसामी तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं। सर्वे से यह भी पता चला है कि द्रमुक के वोट बैंक में टीवीके ने बड़ी सेंध लगा दी है।

इस स्थिति ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि वह साल 2029 के संसदीय चुनाव से पहले इस राज्य में एक अनुकूल सरकार चाहती है।

वैसे, चिंता लगभग सभी पार्टियों में है। अन्नाद्रमुक पार्टी अंदरूनी कलह का सामना कर रही है। पलानीसामी ने हाल ही में अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने बूथ स्तर की गतिविधियों में शिथिलता और भाजपा के साथ तालमेल न बनाने के लिए उन्हें फटकार लगाई। जिला प्रमुखों ने उनकी तो बात सुनी, पर बिना कोई आश्वासन दिए चुपचाप चले गए। भाजपा टीटीवी दिनाकरन और अन्नाद्रमुक में उपेक्षित पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को भी फिर से साथ लाने की कोशिश कर रही है। पन्नीरसेल्वम को पलानीसामी एनडीए का हिस्सा तो मानते हैं, पर उन्हें अन्नाद्रमुक में लेना नहीं चाहते। इस बीच द्रमुक और टीवीके ने दोनों नेताओं को न्योता दिया और आश्वस्त किया है कि उन्हें टिकट बंटवारे के समय पर्याप्त हिस्सा मिलेगा, जिससे भगवा पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। एनडीए की पूर्व सहयोगी पीएमके दो गुटों में बंटी है। इनमें अंबुमणि रामदास का गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है। इसी तरह, पी विजयकांत की पार्टी डीएमडीके इस महीने गठबंधन पर फैसला करेगी।

उधर, द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन संकट में दिख रहा है। कांग्रेस ने इस बार 38 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जबकि 2021 में उसे सिर्फ 25 सीटें मिली थीं। इसके अलावा दूसरी छोटी पार्टियां भी हैं। नई पार्टी टीवीके के साथ कुछ वरिष्ठ अन्नाद्रमुक नेता जुड़े हैं, पर मजबूत गठबंधन अभी दूर की कौड़ी है। 2021 में द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच वोटों का अंतर 20.39 लाख या 4.41 प्रतिशत का था। इस बार जीत का अंतर कम हो सकता है। एसआईआर ने इसमें और तड़का लगा दिया है। गठबंधन के बारे में तस्वीर साफ न होने से तमिलनाडु के नेता परेशान हैं, लेकिन उम्मीद है कि 15 जनवरी को पोंगल के बाद स्पष्टता आएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जहां संचय, वहीं भय

भय कई तरह के होते हैं। एक भय पीड़ा का होता है। शारीरिक पीड़ा एक स्नायुगत प्रतिक्रिया है, लेकिन मानसिक पीड़ा तब होती है, जब हम संतोष देने वाली चीजों से चिपके रहते हैं, क्योंकि तब हम हर उस व्यक्ति या चीज से डरे हुए होते हैं, जो उनको मुझसे छीन सकती है। जब तक मनोवैज्ञानिक रूप से संचित अनुभवों को किसी तरह छेड़ा नहीं जाता, वे मानसिक पीड़ा को रोकने का काम करते हैं। इसलिए हम हर उस व्यक्ति से डरे रहते हैं, जो उन संचित अनुभवों को हिला सकता है।

हमारा भय जानी हुई चीजों का होता है; हम शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से संचित उन अनुभवों से डरे होते हैं, जिन्हें हमने दुख से बचने के लिए एकत्रित किया है, परंतु दुख तो उस प्रक्रिया में ही है, जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा को अपने से दूर रखने के लिए आवश्यक अनुभवों के संचय में होती है।

जानकारी कष्ट को दूर रखने में सहायक होती है। जैसे, चिकित्सा संबंधी ज्ञान शारीरिक पीड़ा को दूर करने में सहायक होता है, वैसे ही विश्वास मानसिक पीड़ा को दूर करने में सहायक होते हैं और इसीलिए हम अपने विश्वासों को खो देने से भयभीत रहते हैं। हालांकि, हमें इन विश्वासों की सच्चाई का न तो पूरा ज्ञान है और न इसके लिए हमारे पास कोई ठोस प्रमाण ही है। हम अपने ऊपर लादे गए किन्हीं परंपरागत विश्वास का परित्याग तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव हमें शक्ति, भरोसा और समझ प्रदान करता है; लेकिन वैसे विश्वास और जो ज्ञान हमने हासिल किया है, मूलतः एक ही बात है- कष्ट को दूर रखने के उपाय।

जब तक ज्ञात का संचय होता है, उसके खो जाने का डर भी बना रहता है, इसलिए जो अज्ञात का भय है, वह वास्तव में संचित हुए ज्ञात के खो जाने का भय है। संचय है, तो भय का होना निश्चित है और भय के साथ कष्ट का होना; और जिस क्षण हम यह कहते हैं कि हमें इस संचय को खोना नहीं चाहिए, भय पैदा हो जाता है। हालांकि, संचय करने के पीछे हमारी मंशा कष्ट को दूर करने की होती है, फिर भी इसकी प्रक्रिया में कष्ट समाया रहता है।

आत्मरक्षा की भावना के बीज से ही आक्रामकता उपजती है। हम भौतिक सुरक्षा चाहते हैं और इसके लिए

जब तक ज्ञात का संचय होता है, उसके खो जाने का डर भी बना रहता है, इसलिए जो अज्ञात का भय है, वह वास्तव में संचित ज्ञात के खो जाने का भय है और भय से ही पीड़ा है।

एक संप्रभुता संपन्न सरकार चुनते हैं, जिसे सेनाओं की जरूरत होती है, जिसका अर्थ होता है युद्ध और अंत में सुरक्षा ही नष्ट हो जाती है। जहां कहीं भी व्यक्ति आत्म-सुरक्षा चाहता है, वहीं भय होता है। जब हम सुरक्षा की मांग की भ्रामकता को देख लेते हैं, संचय करना बंद कर देते हैं। यदि आप कहते हैं कि आप इसे समझते तो हैं, फिर भी आप बिना संचय किए नहीं रह सकते, तो इसका कारण यही है कि आपने वास्तव में इस बात को नहीं देखा कि संचय में ही पीड़ा निहित है।

जे कृष्णमूर्ति

निर्मला सीतारमण | केंद्रीय वित्त मंत्री

हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। हजार साल बाद भी सोमनाथ में समुद्र उसी तीव्रता से गरजता है और किनारों से टकराती इसकी लहरें एक अनूठी कहानी कहती हैं।

क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाए

क्रिकेट को लंबे समय तक सज्जनों का खेल माना गया, परंतु हाल की घटनाएं इसकी बदलती तस्वीर दिखाती हैं। आईपीएल-2026 की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की खरीद के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद उभर आया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर भारत में विरोध, बहिष्कार अभियान और दबाव तेज हुआ। परिणामस्वरूप बीसीसीआई ने खिलाड़ी को मुक्त करने का निर्देश दिया। यह प्रकरण बताता है कि खेल अब कूटनीति और राजनीति से प्रभावित हो रहा है। आवश्यक है कि क्रिकेट को इन प्रभावों से अलग रखा जाए, ताकि वह सद्भाव और खेल भावना का प्रतीक बना रहे।

दुखद है कि जो क्रिकेट कभी पड़ोसी देशों के बीच संवाद और सौहार्द का माध्यम माना जाता था, आज उसी के मैदान पर राजनीतिक कटुता की गहरी लकीरें खींची जा रही हैं। मुस्तफिजुर रहमान प्रकरण ने खेल की सीमाओं को लांघते हुए भारत-बांग्लादेश संबंधों को विवाद के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब क्रिकेट भी कूटनीति और आक्रोश का उपकरण बन चुका है? मैदान पर गेंद नहीं, बल्कि अविश्वास और नाराजगी उछलती दिखाई दे रही है। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल बहिष्कार की याद दिलाता है, जब कूटनीतिक तनाव ने खेल के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस बार भी सोशल मीडिया पर दबाव, राष्ट्रवादी भावनाएं और राजनीतिक बयानबाजी निर्णायक भूमिका में दिखी हैं। इससे क्रिकेट की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।

इन सबसे आगे की राह और अधिक धुंधली होती दिखाई दे रही है। द्विपक्षीय शृंखलाएं, खिलाड़ियों का आदान-प्रदान और संयुक्त क्रिकेट आयोजन सभी गंभीर सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। फिलहाल आईसीसी के हस्तक्षेप की संभावना भले मौजूद हो, लेकिन ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना किसी स्थायी समाधान की उम्मीद कमजोर है। ये हालात वैश्विक क्रिकेट के लिए चेतावनी हैं कि बढ़ता राजनीतिक दखल अंततः खेल की आत्मा को खोखला कर देगा। मुस्तफिजुर रहमान की रिहाई एक गहरे प्रतीक के रूप में उभरी है। यह घटना संकेत है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक भावनाओं और राजनीतिक सोच का विस्तार बन चुका है। लिहाजा समय रहते संतुलन नहीं साधा गया, तो क्रिकेटीय आत्मा, जो कभी सीमाओं को जोड़ती थी, धीरे-धीरे धुंध में खो सकती है।

आरके जैन 'अरिजीत', शिक्षाविद

अनुलोम-विलोम

क्रिकेट और राजनीति

जनभावना का ख्याल तो रखना ही होगा

बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 'रिलीज' करने के बाद उनके समर्थन में कई लोग आ गए हैं। एक नामचीन हस्ती ने लिखा है कि इससे ढाका और पाकिस्तान करीब आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इस निष्कासन से बांग्लादेश की रणनीति तय होगी? यानी, भारत तो क्रिकेट और राजनीति को अलग-अलग रखे, लेकिन यह बाध्यता बांग्लादेश पर नहीं है। यही है दोमुंहापन! दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं, जो बीसीसीआई को कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान तो क्रिकेटर है। उसने थोड़े ही हिंसा फैलाई है। इस तर्क पर तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भी यह भूलकर मौका दे देना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट मैदान पर 'विमान गिरनेवाले' और अन्य 'एक्शन' किए थे। अगर किसी मैच में मुस्तफिजुर भी कोई ऐसी ही शारीरिक संकेत करते दिखें, तो आप क्या करेंगे? भारत की जनता में आक्रोश है और ये तथाकथित बुद्धिजीवी अलग-अलग मत देकर बेचैनी दिखा रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि आप बांग्लादेशी क्रिकेटर की जिम्मेदारी लेंगे क्या? कल यदि वे झूठा आरोप लगा दें कि उनके साथ ड्रेसिंग रूम में गलत हरकत हुई या पक्षपात हुआ, तो फिर यही बुद्धिजीवी इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी बना देंगे।

मकरंद हिरवे, टिप्पणीकार

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया जाना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भरा और सही फैसला है। सोशल मीडिया पर भले ही इसको लेकर अलग-अलग बातें की जा रही हों, लेकिन सच्चाई यही है कि हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर भारत में लोगों के बीच भारी गुस्सा और चिंता है। जब ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं, तो उनका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खेल और समाज तक भी पहुंचता है। और भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। यह करोड़ों लोगों की भावना, सम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में, अगर किसी खिलाड़ी की मौजूदगी से देश के भीतर असंतोष, विरोध या तनाव पैदा होता है, तो क्रिकेट बोर्ड का फर्ज बनता है कि वह देश की भावनाओं को प्राथमिकता दे। कुछ लोग कहते हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। यह बात सही है, पर जब लोग आहत हों, जब किसी समुदाय पर अत्याचार की खबरें हों, तब खेल भी उस असर से अछूता नहीं रह सकता। लिहाजा, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करना नफरत नहीं, बल्कि देश की भावनाओं का सम्मान है! बीसीसीआई ने दिखा दिया कि वह देश की आवाज भी सुनता है।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

अपने जीवन में नयापन लाएं

उपनिषद् में कहा गया है कि वास्तव में समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। हम इस नए वर्ष में नए गुण, नई सोच, नई विधा, नया चिंतन और अच्छे कर्म अपने जीवन में ले आएं। किसी नादान की तरह नहीं जिएं। जिएं तो एक जाग्रत व्यक्ति की तरह जिएं। जब हम जाग्रत होकर जिएंगे, तो बाहर-अंदर सब कुछ नया होगा। आइए हम जाग्रत जीवन जीने का संकल्प लें और अपने जीवन में नयापन लाएं।

अध्यात्म

आनंदमूर्ति गुरुमां

अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का यही सही समय है। शुरुआत इस चिंतन से करें कि अब तक आपने कितनी साधना की है? मन के कितने दोष दूर किए हैं? मन का कितना अज्ञान दूर किया है? बीते समय में क्या किया? पिछला साल तो यही सोचते निकल गया कि साधना आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे।

मन को अच्छी बातों से जोड़ें

नए साल में संकल्प करने की परंपरा है। बहुत-से लोग बहुत प्रकार के संकल्प करते हैं, जैसे- वजन कम करेंगे, मीठा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे संकल्प करना भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे भी आपके मन की शक्ति बढ़ जाती है और मन की कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत-से लोग संकल्प तो करते हैं, परंतु उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन बेईमान हो जाता है। जरूरी है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करें। उसके गुलाम नहीं बने। यह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है ईमानदारीपूर्वक निरंतर प्रयास करने की।

जैसे पानी के लिए नीचे गिरना आसान और सहज होता है, परंतु अगर उसे ऊपर उठाना हो, तो मोटरपंप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे मन के लिए नीचे गिरना आसान और सहज है। मन को ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल है। मन के लिए अच्छी बातों से जुड़ना बहुत मुश्किल है, उनको छोड़ देना सहज है।

कल की नहीं, आज की करें चिंता

मन की आदतें ऐसी होती हैं कि उन्हीं आदतों में मन को सुविधा महसूस होने लगती है। हमारा मन कुछ आदतों को पाल लेता है और उन्हीं में खुश रहता है। अगर आप अपनी दिनचर्या में साधना को बढ़ाने का संकल्प करते हैं, तो उसको बिना किसी अटकाव के सालभर चलाते रहना बहुत जरूरी है। भूतकाल बीत चुका है, परंतु वर्तमान आपके हाथ में है, इसलिए आनेवाले कल में क्या होगा, यह आपके आज पर निर्भर करता है। अगर आप अपने आज को साधनापूर्ण, शांतिपूर्ण और सुंदर बना लोगे, तो निश्चित रूप से आपका कल भी वैसा ही होगा। आनेवाले कल की चिंता आज नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज की चिंता अवश्य करनी चाहिए। समस्या यह है कि लोग आनेवाले कल की चिंता तो बहुत करते हैं, पर आज की जरा भी नहीं करते।

नई सोच, नया चिंतन

मैं आपको कुछ संकल्प करने को कहूंगी, तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। जब आप खुद संकल्प करोगे कि मैं यह करूंगा, तो आप उसे खुशी से कर लोगे। आपका अहंकार और अपने प्रति प्यार आपको उस संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा, इसलिए यह विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अपने जीवन की नैया को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। नहीं तो सच बात यह है कि समय भागा जा रहा है। उपनिषद् में कहा है कि वास्तव में समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। साल नहीं बीता, हम बीत गए हैं।

जाग्रत मन से जिएं

इस नए वर्ष में कुछ नए गुण, नई सोच, नई विधा, नया चिंतन और कुछ अच्छे कर्म आप अपने जीवन में ले आएं। किसी नादान की तरह मत जिएं। जिएं तो एक जाग्रत व्यक्ति की तरह होशपूर्वक जिएं। जाग्रत व्यक्ति की तरह जीने के लिए आपको जाग्रत व्यक्ति के साथ होना पड़ेगा। जाग्रत व्यक्ति के साथ होने का मतलब है कि वे जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के साथ रहना।

सत्संग के साथ, विचार के साथ, चिंतन के साथ जिएं। हमारे विचार ऐसे उत्तम होने चाहिए कि हमारे हाथ से कभी कुछ गलत हो ही नहीं। हमारी जीभ कुछ गलत बोले ही नहीं, हमारी आंख कुछ गलत देखे ही नहीं, हमारे कान कुछ गलत सुनें ही नहीं।

मैं आपको कुछ संकल्प करने को कहूंगी, तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। जब आप खुद संकल्प करोगे कि मैं यह करूंगा, तो आप उसे खुशी से कर लोगे। आपका अहंकार और अपने प्रति प्यार आपको उस संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूर करेगा।

इंद्रिय कामनाओं से बचें

याद रखना इस बात को कि जो कुछ आप अपने अंदर डालोगे, वही आपसे बाहर आएगा। वही देखें और सुनें, जिससे मन में प्रेम, करुणा, दया इत्यादि भावनाएं निर्मित हों। वही सुनें, जिससे साधना, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति बढ़ती जाए। जिनसे मन में क्रोध, लोभ, कामना, दुविधा बढ़े, ऐसी चीजों से अपनी इंद्रियों को बचाएं। इंद्रिय जनित ये तात्कालिक सुख पहले तो इंसान को लुभाते हैं, फिर भरमाते हैं और फिर खूब भटकाते हैं। अंत में यही तात्कालिक सुख उसके समस्त दुखों का कारण बनते हैं।

अगर आप भक्ति और ज्ञान की राह पर चलना चाहते हैं, तो आपको यह बात समझनी ही होगी कि आप बेहोशी में जीवन को नहीं जी सकते। समझदारी, सूझ-बूझ और होशपूर्वक जीवन जीने से आप अपने मन को अशांत होने से बचा सकते हैं।

मन शांत, सात्विक और शुद्ध रहेगा, तो फिर प्रभु उस मन में बड़ा सुंदर आसन जमाकर बैठ जाएंगे, इसलिए स्वयं को नया करना जरूरी है।

सप्ताह के व्रत-त्योहार

06 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक

06 जनवरी (मंगलवार): माघ कृष्ण तृतीया तिथि प्रातः 08.02 मिनट तक पश्चात चतुर्थी रात्रि 06.53 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक तदनंतर पंचमी तिथि। श्रीगणेश (अंगारकी) संकष्ट चतुर्थी व्रत। चतुर्थी तिथि का क्षय। गंडमूल विचार।

07 जनवरी (बुधवार): माघ कृष्ण पंचमी तिथि रात्रि 06.34 मिनट (सूर्योदय पूर्व)। गंडमूल प्रातः 11.57 मिनट तक।

08 जनवरी (गुरुवार): माघ कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 07.06 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक पश्चात सप्तमी तिथि। भद्रा रात्रि 07.06 मिनट (सूर्योदय पूर्व) से।

09 जनवरी (शुक्रवार): माघ कृष्ण सप्तमी तिथि (दिन-रात)। भद्रा सायं 07.45 मिनट तक।

10 जनवरी (शनिवार): माघ कृष्ण सप्तमी तिथि प्रातः 08.24 मिनट तक पश्चात अष्टमी तिथि।

11 जनवरी (रविवार): माघ कृष्ण अष्टमी तिथि प्रातः 10.21 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि।

12 जनवरी (सोमवार): माघ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 12.43 मिनट तक। भद्रा रात्रि 02.01 मिनट से। विवेकानंद जयंती

-पं. ऋभुकांत गोस्वामी

भौतिकता से ऊपर उठकर ही उन्नति

विवेकानंद जयंती (12 जनवरी)

ऐसा कहा जाता है कि अधिक आध्यात्मिक होने पर सांसारिक व्यवहारों में कठिनाइयां हो सकती हैं। कन्फ्यूशस के युग में कहा गया था, 'पहले हम इस संसार की चिंता करें, जब इससे छुट्टी मिले, तो दूसरे लोकों की चर्चा करें।'

स्वामी विवेकानंद

यदि हमारी आध्यात्मिकता से हमारे लोकाचार में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो सांसारिकता पर अत्यधिक ध्यान देने से तो इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। सांसारिकता हमें पूर्णतः भौतिकवादी बनाकर छोड़ेगी। मनुष्य का उद्देश्य 'प्रकृति' नहीं है, वरन कुछ उससे ऊपर की वस्तु है।

'मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है, जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है।' यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। इस प्रकृति के भीतर केवल वे ही नियम नहीं हैं, जिनसे हमारे शरीर के तथा उसके बाहर के परमाणु नियंत्रित होते हैं, वरन ऐसे सूक्ष्म नियम भी हैं, जो वस्तुतः बाह्य प्रकृति को संचालित करनेवाली अंतःस्थ प्रकृति का नियमन करते हैं।

बाह्य प्रकृति को जीत लेना अच्छा और भव्य है। उससे असंख्य गुना अच्छा और भव्य है, अभ्यंतर प्रकृति पर विजय पाना। ग्रहों और नक्षत्रों का नियंत्रण करने वाले नियमों को जान लेना बहुत अच्छा है, परंतु उससे अनंत गुना अच्छा है, उन नियमों को जानना, जिनसे मनुष्य के मनोवेग और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं।

इस आंतरिक मनुष्य पर विजय पाना, मानव-मन की जटिल सूक्ष्म क्रियाओं के रहस्य को समझना, पूर्णतया धर्म के अंतर्गत आता है। मनुष्य का स्वभाव, साधारण मनुष्य का स्वभाव है। वह बृहत भौतिक तथ्यों का अवलोकन करना चाहता है। साधारण मनुष्य किसी सूक्ष्म वस्तु को नहीं समझ सकता। ठीक ही कहा गया है कि संसार तो उस सिंह का आदर करता है, जो हजारों मेमनों का वध करता है। लोगों को यह समझने का अवकाश कहां है कि सिंह की इस क्षणिक विजय का अर्थ है- हजारों मेमनों की मृत्यु! इसका कारण यह है कि मनुष्य शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से प्रसन्न होता है।

हर समाज में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं, जिन्हें इंद्रिय विषयक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं मिलता। वे इनसे ऊपर उठना चाहते हैं और यदा-कदा सूक्ष्मतर तत्वों की झांकी पाकर उन्हें ही पाने के लिए सदा संघर्षरत रहते हैं।

जब हम विश्व-इतिहास का मनन करते हैं, तो पाते हैं कि जब-जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या वृद्धि हुई है, तब-तब किसी राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है। आध्यात्मिकता ही किसी भी जाति की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन से इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है।

आस्था-अनास्था

समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद्

पंचग्रही योग दिलाएगा संघर्षपूर्ण सफलता

नव वर्ष का प्रारंभ पंचग्रही योग में होने पर बारह राशियों पर इसके क्या प्रभाव होंगे?
-लक्ष्य जैन, सोनीपत

नव वर्ष 2026 का प्रारंभ गोचर में धनु राशि में चार ग्रहों- सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति और इनसे सप्तम स्थान में मिथुन के वक्री गुरु का इनसे दृष्टि संबंध हो चुका है। यह पंचग्रही योग के समान परिणाम देगा। ज्योतिष शास्त्र में पंचग्रही योग को महत्वपूर्ण माना गया है। इस योग में मंगल, बुध एवं शुक्र अस्त और गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। इस पंचग्रही योग का आपकी राशि पर पड़नेवाला प्रभावः

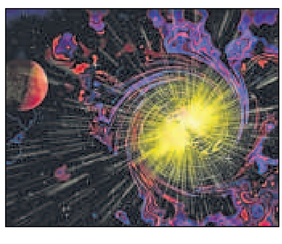

मेषः आर्थिक लाभ। घर में मांगलिक कार्य। लाभकारी परिवर्तन। तरक्की के अवसर बनेंगे।

वृषः कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त प्रभार। नए कार्य में पूंजी निवेश।

मिथुनः कुछ नए संबंध-संपर्क बन सकते हैं। छात्रों को विशेष सफलता। संतान संबंधी मांगलिक कार्य।

कर्कः आय के साथ खर्च की अधिकता। अतिरिक्त प्रयास से लाभ।

सिंहः घर में मांगलिक कार्य। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति। कुछ कार्यों में आधी-अधूरी सफलता।

कन्याः चल संपत्ति की खरीदारी। परिवार में मांगलिक कार्य।

तुलाः घर एवं कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्ति। तरक्की। आर्थिक लाभ। अधिकांश रुके काम बनेंगे।

वृश्चिकः परिवार एवं कार्य स्थल में सुखद स्थिति। भौतिक सुख-सामग्री एवं चल संपत्ति बढ़ेगी। आर्थिक लाभ।

धनुः वैवाहिक जीवन में मधुरता। अचानक परिवर्तन। विवादित मामलों में सफलता। विरोधी पर भारी पड़ेंगे।

मकरः अचानक धन प्राप्ति एवं हानि। थोड़ी स्वास्थ्य समस्या। कार्यक्षेत्र में बदलाव संभव।

कुंभः संतान पक्ष से शुभ समाचार। पुरानी समस्या का समाधान। तरक्की। घर में मांगलिक कार्य होंगे।

मीनः चल-अचल संपत्ति में वृद्धि। भाग्य का साथ। आमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति।

भेजें अपने सवाल

स्वर्ग-नरक की कल्पना का आधार क्या है?

पाप क्या है, पुण्य क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? ईश्वर की आराधना कैसे करें? ऐसे सवाल अकसर हमारे मन में उठते हैं, पर इनका जवाब हमारे पास नहीं होता। मन-मस्तिष्क में आने वाले ऐसे ही सवालों के जवाब हमारे पैनल में शामिल धर्माचार्य आपको देंगे।

अपने सवाल हमें इस पते पर भेजें:
धर्मक्षेत्रे, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301 (उत्तर प्रदेश)

सत्यकाम ने शिष्य उपकोशल को दिया ब्रह्मज्ञान

(छांदोग्य उपनिषद् से)

ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात सत्यकाम विवाह करके जीवन व्यतीत करने लगा। वह आश्रम स्थापित करके विद्यार्थियों को विद्या प्रदान किया करता था। उसके आश्रम में दूर-दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे।

सत्यकाम की विद्वत्ता की कहानी कमल के पुत्र उपकोशल के कानों में भी पड़ी। वह भी विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से सत्यकाम के आश्रम में जा पहुंचा।

सत्यकाम की अनुमति से उपकोशल ब्रह्मचारी के रूप में विद्याध्ययन करने लगा। कई वर्षों के पश्चात जब अध्ययन समाप्त हो गया, तो सत्यकाम ने दूसरे विद्यार्थियों का तो समावर्तन संस्कार करके उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी, पर उन्होंने उपकोशल का न तो समावर्तन किया, न उसे घर जाने की आज्ञा दी। उपकोशल मन-ही-मन दुखी हुआ। वह सोचने लगा, आचार्य ने उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया?

गुरु-पत्नी उपकोशल को दुखी देखकर द्रवित हो उठीं।

उन्होंने आचार्य से कहा, 'उपकोशल ने आपके यज्ञ की अग्नि की बड़ी सेवा की है। अध्ययन में भी इसने कुछ उठा नहीं रखा है। फिर आपने उसका दीक्षा-संस्कार क्यों नहीं किया? उसे घर जाने की आज्ञा क्यों नहीं प्रदान की?'

आचार्य ने पत्नी की बातें सुनीं तो, पर उन पर ध्यान नहीं दिया। वे मौन ही रहे। उपकोशल ने विद्या तो पढ़ ली थी, पर ब्रह्मज्ञान का अधिकारी वह अभी नहीं बन सका था, क्योंकि उसके मन में कामनाएं शेष रह गई थीं। वे ब्रह्मज्ञान देकर उसके जीवन को धन्य बनाना चाहते थे।

कुछ दिनों पश्चात आचार्य यात्रा पर चले गए। आचार्य के चले जाने पर भी वह आश्रम में ही रहा। उपकोशल ने दुखी होकर अन्न-जल का परित्याग कर दिया।

उसे ऐसा करते देख गुरु-पत्नी के मन में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने उपकोशल के पास जाकर उससे कहा, 'वत्स, तुमने अन्न और जल का परित्याग क्यों कर दिया? इससे क्या लाभ होगा?'

उपकोशल ने उत्तर दिया, 'माता, मैंने सोचा था, विद्या प्राप्त करने के पश्चात घर जाऊंगा, विवाह करूंगा और आश्रम बनाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा, पर आचार्य ने मेरा दीक्षा-संस्कार ही नहीं किया। मेरी कामनाएं मिट्टी में मिल गईं।' गुरु-पत्नी उत्तर देतीं, तो क्या देतीं? वे मौन रह गईं। उपकोशल के अनशन का क्रम नहीं टूटा।

उपकोशल ने यज्ञ की अग्नियों की सेवा बड़ी निष्ठा से की थी। अतः उसके अनशन को देखकर अग्नि के मन में भी दया उत्पन्न हो गई। उसने प्रकट होकर कहा, 'उपकोशल, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। अतः हम तुम्हें ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं।' अग्नियों ने बारी-बारी से उपकोशल को ज्ञान का उपदेश दिया। अग्नियों के उपदेश से उपकोशल का मुखमंडल ही नहीं, हृदय भी आलोकित हो उठा।

कुछ दिनों पश्चात आचार्य जब यात्रा से लौटकर आए, तो वे उपकोशल के मुखमंडल को देखकर चकित हो गए। उन्होंने उससे पूछा, 'वत्स, तुम्हारे मुखमंडल पर अपूर्व तेज है। प्रतीत होता है, तुम्हें किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया है।'

उपकोशल ने अपने अनशन और अग्नियों के उपदेश की कहानी आचार्य को सुना दी! आचार्य अतीव प्रसन्न हुए। वे विचारों में डूबकर सोचने लगे।

कुछ क्षणों पश्चात आचार्य ने सोचते हुए कहा, 'मैं यही चाहता था, उपकोशल कि अग्नि तुम्हें उपदेश दें। उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई। अब मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान प्रदान करूंगा।'

आचार्य ने उपकोशल को ब्रह्मज्ञान देकर उसका समावर्तन संस्कार किया और उसके बाद उसे घर जाने की अनुमति दे दी।

श्री व्यथितहृदय
(साभार : उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां, सुनील साहित्य सदन, नई दिल्ली)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। लेखनादि-बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे।

वृष: आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

मिथुन: पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।

कर्क: मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है।

सिंह: मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

कन्या: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे।

तुला: धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी मित्र के साथ किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृश्चिक: मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। संतान की सेहत का ध्यान रखें।

धनु: आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

मकर: मन प्रसन्न रहेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कुंभ: किसी अज्ञात भय से मन परेशान हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है। बौद्धिक कार्यों से आय वृद्धि हो सकती है।

मीन: आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शैक्षिक व शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए साक्षात्कारादि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

06 जनवरी, मंगलवार, **शक संवत्:** 16 पौष (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 23 पौष मास प्रविष्टे 2082, **इस्लाम:** 16 रज्जब, 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ कृष्ण तृतीया तिथि प्रातः 08.02 मिनट तक। आयुष्मान योग, विष्टि (भद्रा) करण प्रातः 08.02 मिनट तक। चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर 12.18 मिनट तक उपरांत सिंह राशि में। **सूर्य दक्षिणायन।** अपराह्न 03 बजे से सायं 04.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.02 मिनट तक। श्रीगणेश (अंगारकी) संकष्ट चतुर्थी व्रत। गौरी वक्रतुंड चतुर्थी। चतुर्थी तिथि का क्षय। गंडमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

यह बताएं कि सपने में इन चीजों के दिखाई देने का क्या अर्थ है? **-स्वप्नदर्शी,** बरेली

- **परीक्षा छूट जाना-** यह इस बात का संकेत है कि आप में आत्मविश्वास में कमी है।
- **कपड़े धोना-** यह संकेत है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है।
- **रुद्राक्ष देखना-** यह इस बात का संकेत है कि आपका शुभ समय आने वाला है।
- **गाय देखना-** यह संकेत है कि आपके जीवन में खुशियां एवं समृद्धि बढ़ने वाली है।
- **भोजन करना-** यह इस बात का संकेत है कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
- **गर्भवती महिला-** यह इस बात का संकेत होता है कि या तो आपको संतान सुख प्राप्त होगा या फिर कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी।

वर्ग पहेली : 8201

1	■	2		3		4	5	■
	■		■		■	6		
7						■		■
	■		■		■	8		
■	9			■	10			■
11			■	12	■		■	13
■		■	14					
15		16	■		■		■	
■	17						■	

बाएं से दाएं
2. उत्पीड़ित करना; कष्ट देना; क्षतिग्रस्त करना; घायल करना (3,3)
6. उलझन वाली स्थिति; टेढ़ा मामला; विकट प्रसंग; कठिनाई (3)
7. असफल करना; विफल करना (3,3)
8. अतीत; बीता हुआ; रहित (3)
9. लोहे को सोने में बदलने वाला पत्थर; स्पर्शमणि (3)
10. अलग रखना; छिपाना; बचाव करना; रक्षा करना; शरण देना; जोड़ना (3)
11. रोकना; ग्रस्त करना; घेरे में लाना; हांका करना (3)
14. अर्जित करना; कारोबार करना; कमाना (3,3)
15. होश में लाना; सोते से उठाना; चेताना (3)
17. कीर्ति फैलाना; ख्याति पाना; नाम फैलाना; यश फैलाना (2,4)

ऊपर से नीचे
1. संज्ञावाचक शब्द के स्थान पर प्रयुक्त शब्द (4)
2. आराम में होना; विश्राम करना; सोना (3,3)
3. गरम पानी से धोना; धार मार कर धोना (4)
4. मजा; सुख; स्वाद; अमृत; सुधा; नीर; सार (2)
5. कलंक लगना; माथे मढ़ा जाना (2,3)
8. सोचना; ध्यान करना; मनन करना (3,3)
9. उद्धार करना; दूसरे पार पहुंचाना; संकट से उबारना (2,3)
12. आगमन; लोगों का उद्देश्यपूर्वक संबद्ध होना; सम्मेलन (4)
13. अधिनायकत्व; निरंकुशता; स्वेच्छाचारिता; स्वैराचार (4)
16. इज्जत; कीर्ति; ख्याति; धाक; प्रतिष्ठा (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8200

■	1 सो	2 म	वा	3 र	■	4 सु	ले	5 ख
6 अं	■	न	■	7 सा	मा	न	■	ब
8 ग	रि	मा	म	य	■	ना	■	र
अं	■	र	■	न	■	■	9 अ	दा
ग	■	10 ना	ता	■	11 मां	12 द	■	र
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सुडोकू : 8183

*मध्यम

						3		
4		8		6				
	2	6		1			7	
	1	2			5	7	6	
				3				
	6	7	9			5	4	
	5			7		6	3	
				5		8		1
		9						

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8182

8	5	7	6	9	4	3	1	2
9	4	3	1	5	2	8	6	7
1	6	2	7	3	8	9	4	5
5	3	9	4	6	1	2	7	8
2	8	6	9	7	3	1	5	4
4	7	1	2	8	5	6	3	9
6	9	5	3	2	7	4	8	1
3	1	8	5	4	9	7	2	6
7	2	4	8	1	6	5	9	3

आधार सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल, 50 लाख से अधिक डाउनलोड

सुविधा : नए आधार ऐप के जरिये अपना पता, ई-मेल जोड़ सकेंगे

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। आधार से जुड़ी सेवाओं को सरल, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा तैयार ऐप जल्द ही लांच होने जा रहा है। आधारधारकों को अब नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नया आधार मोबाइल ऐप 27 से 30 जनवरी के बीच आधिकारिक रूप से लॉन्च किए जाने की तैयारी है।

ऐप का ट्रायल फेज लगभग पूरा हो चुका है और शुरुआती प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है। ट्रायल के दौरान ही एंड्रॉयड फोन पर ऐप को 50 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप को आईओए पर भी बड़ी संख्या में डाउनलोड किया जा रहा है।

देश में आधार आज बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन, सरकारी योजनाओं, पेंशन, सब्सिडी और कई अन्य सेवाओं की पहचान का अहम माध्यम बन चुका है, लेकिन समय के साथ लोगों का मोबाइल नंबर बदलना, पता बदलना या नाम में सुधार जैसी जरूरतें सामने आती हैं। 12 भाषाओं में उपलब्ध आधार में बदलाव की सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा।

अभी तक मोबाइल नंबर और पता बदलने की सेवा शुरू की गई है। जल्द ही ऐप के जरिए नाम और मेल आईडी बदलने की भी सुविधा दी जाएगी, जिसका ट्रायल हो चुका है। अब ऐप आधिकारिक तौर पर लांच होने को तैयार है। जल्द ही तिथि निर्धारित होनी है। उसके बाद ऐप के जरिए सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

फोन नंबर में बदलाव नए आधार ऐप की बड़ी सुविधा

इस माह के अंत में जारी होने वाले नए आधार ऐप की सबसे अहम सुविधा मोबाइल नंबर बदलने की प्रक्रिया है। अब आधारधारक फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सीधे अपने मोबाइल से नंबर अपडेट कर सकेंगे।

इसके लिए 75 रुपये का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा, जो मोबाइल से ही यूपीआई के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यूआईडीएआई से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अब फेस ऑथेंटिकेशन की उन्नत तकनीकी आ गई है, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मोबाइल नंबर बेहद संवेदनशील मामला है। आधार में दर्ज मोबाइल नंबर से ही सारी सेवाएं जुड़ी हैं।

अन्य सेवाएं भी मिलेंगी ऐप के जरिए

- ऐप से पता, नाम और ई-मेल अपडेट करना भी आसान।
- वर्तमान में आधार में दर्ज मोबाइल नंबर व पता बदलने की सुविधा भी ऐप के जरिए उपलब्ध है।
- नाम सुधार, ई-मेल आईडी अपडेट जैसी सेवाएं भी ऐप के माध्यम से जल्द उपलब्ध होंगी।
- नए आधार ऐप में कॉन्टैक्ट कार्ड जनरेट करने की सुविधा भी दी गई है।
- क्यूआर कोड शेयर करने या स्कैन कराने पर नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी साझा कर सकेंगे।

क्यों जरूरी था नया आधार ऐप जारी करना

अभी तक इन बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र जाना अनिवार्य था, जिससे लोगों को लंबी कतारों और समय की बर्बादी का सामना करना पड़ता था। सबसे अधिक दिक्कत मोबाइल नंबर बदलने में थी, जिसके लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी था। यूआईडीएआई ने पाया कि सेवा केंद्र आने वाले काफी लोगों अपना मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं। उन्होंने आधार बनवाते समय परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया था ऐसे में मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सेवाओं में दिक्कत आती थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यूआईडीएआई ने मोबाइल-फर्स्ट अप्रोच की नीति को अपनाते हुए यह नया आधार ऐप विकसित किया है।

फोन में सीधे टीवी चलाने की तकनीक पर आपत्ति

फोन कंपनियों की एसोसिएशन ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। मोबाइल फोन पर बिना इंटरनेट और सिम कार्ड के सीधे लाइव टीवी देखने की तकनीक को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। इसे डायरेक्ट-टू-मोबाइल ब्रॉडकास्ट तकनीक कहा जाता है।

हाल ही में सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा कराए गए तकनीकी परीक्षण पर टेलीकॉम उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

एसोसिएशन का कहना है कि यह परीक्षण पारदर्शी और परामर्श आधारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि यह पूरा परीक्षण टेलीकॉम ऑपरेटरों, डिवाइस निर्माताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के बिना किया गया।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, इस तकनीक का सीधा असर उन स्पेक्ट्रम बैंड्स पर पड़ता है, जिनका इस्तेमाल फिलहाल या भविष्य में 5जी और मोबाइल सेवाओं के लिए किया जाना है।

एक ऐसी ब्रॉडकास्ट तकनीक है, जिसके जरिए मोबाइल फोन पर सीधे टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा सकता है। इसके लिए न तो मोबाइल डेटा की जरूरत होगी और न ही वाई-फाई या सेल्युलर नेटवर्क की। सरल शब्दों में कहें तो जैसे रेडियो बिना इंटरनेट के चलता है, उसी तरह इस तकनीक के जरिए मोबाइल फोन पर लाइव टीवी देखा जा सकेगा।

सरकार और प्रसार भारती का मानना है कि यह तकनीक आपदा के समय, दूर-दराज इलाकों और सार्वजनिक सूचनाओं के प्रसारण के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है।

बड़े आयोजनों या आपात स्थितियों में लाखों लोगों तक एक साथ सूचना पहुंचाने में यह कारगर साबित हो सकती है।

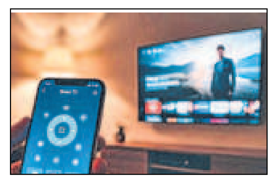

उपभोक्ता को इससे क्या फायदा होगा

1. बिना इंटरनेट और सिम के टीवी
2. भीड़ या आपदा में भी निर्बाध सेवा
3. फोन की बैटरी अपेक्षाकृत कम खर्च होगी
4. डेटा खर्च में सीधी बचत
5. सस्ते या मुफ्त चैनल संभव
6. सस्ते मोबाइल रिचार्ज प्लान से मासिक खर्च पर नियंत्रण

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स 85,439 -322.39

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
बीईएल	413.80	2.65
अल्ट्राटेक सीमेंट	12081.65	1.57

टॉप लूजर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एचडीएफसी बैंक	977.70	-2.35
इंफोसिस	1606.40	-2.09

निफ्टी 26,250 -78.25

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
नेस्ले इंडिया	1315.00	2.76
बीईएल	413.35	2.53

टॉप लूजर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एचडीएफसी बैंक	978.50	-2.31
विप्रो	263.00	-2.23

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,40,400	+960
चांदी	2,44,000	+2,600

करेंसी

डॉलर/रुपया 90.30 -0.10

10 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य

नई दिल्ली। उद्योग जगत के दिग्गजों के एक समूह ने हंड्रेड मिलियन जॉब्स (10 करोड़ नौकरियां) नामक एक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इस मुहिम की घोषणा सॉफ्टवेयर उद्योग निकाय नैसकॉम के सह-संस्थापक हरीश मेहता, वैश्विक उद्यमी नेटवर्क द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के संस्थापक ए जे पटेल और ससीआईपीपी) के संस्थापक के यतीश राजावत ने की।

सेल ने बनाया दिसंबर की बिक्री का नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली। सेल की बिक्री दिसंबर 2025 में 37 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख टन पर पहुंच गई। महारत्न कंपनी की यह किसी भी दिसंबर महीने में सबसे अधिक बिक्री है। पिछले साल दिसंबर में उसने 15 लाख टन इस्पात की बिक्री की थी। दिसंबर महीने के शानदार प्रदर्शन ने सेल को वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने के दौरान अपनी विकास गति बरकरार रखने में मदद की है।

रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ

मुंबई। रुपये में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट आई और यह आठ पैसे टूटकर 90.30 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मजबूत अमेरिकी मुद्रा और घरेलू शेयर बाजारों में सुस्ती से रुपये पर दबाव पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के बाद उत्पन्न हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने विश्व स्तर पर डॉलर की मांग को बढ़ावा दिया।

रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं

मुंबई। रिजर्व बैंक ने सोमवार को खुले बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं। केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों के तहत यह खरीद की है। यह चार समान किस्तों में दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के तहत दूसरी किस्त है। रिजर्व बैंक ने सात तरह की प्रतिभूतियों की खरीद की है।

1,500 करोड़ रुपये से अधिक का किया निवेश

नई दिल्ली। वैश्विक निजी इक्विटी कंपनी एपैक्स पार्टनर्स ने बेंगलुरु स्थित आईडी फ्रेश फूड्स में महत्वपूर्ण अल्पांश हिस्सेदारी के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एपैक्स पार्टनर्स ने इस निवेश से कंपनी में 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

निसान ने रिकॉर्ड वाहनों का निर्यात किया

नई दिल्ली। वाहन विनिर्माता निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर महीने में रिकॉर्ड 13,470 वाहनों का निर्यात किया जो पिछले 10 वर्षों में किसी भी महीने का सर्वाधिक आंकड़ा है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि दिसंबर, 2025 में उसने घरेलू बाजार में 1,902 वाहनों की बिक्री की। इस तरह पिछले महीने निसान की कुल बिक्री 15,372 इकाई रही।

कच्चा तेल 50 डॉलर पर आने का अनुमान

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में इस साल महत्वपूर्ण कमी आ सकती है और जून 2026 तक इसके 50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। सोमवार को जारी एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में गिरावट की रफ्तार तेज हो सकती है, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति निश्चित रूप से 3.4 प्रतिशत से नीचे रहेगी।

ओएनजीसी जहाजों में 50% हिस्सेदारी लेगी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ओएनजीसी दो संयुक्त उद्यम कंपनियों में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगी। ये इकाइयां जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स (एमओएल) के साथ साझेदारी में बहुत बड़े एथेन वाहक (वीएलईसीएस) को लेंगी और उसका संचालन करेंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने विशेष एथेन पोत परिवहन क्षेत्र में प्रवेश किया है।

आईईएक्स का बिजली कारोबार 11 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। बिजली खरीद-बिक्री बाजार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) का अक्टूबर-दिसंबर में कुल कारोबार 11.9 प्रतिशत बढ़कर 34.08 अरब यूनिट रहा। आईईएक्स ने बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में एक्सचेंज ने 18.63 लाख नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) का कारोबार किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.8 प्रतिशत की गिरावट है।

ट्रंप की चेतावनी से सेंसेक्स फिसला

मुंबई, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय उत्पादों पर शुल्क और बढ़ाने की ताजा चेतावनी के बीच सोमवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 322 अंक के नुकसान में रहा जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट रही।

विश्लेषकों ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप की ताजा चेतावनी से धारणा प्रभावित हुई और बैंकिंग, आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा।

सेंसेक्स 322.39 अंक गिरकर 85,439.62 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 446.68 अंक फिसलकर 85,315.33 अंक के निचले स्तर पर आ गया था।

बड़ी उपलब्धि है 50 अरब डॉलर का आईफोन निर्यात

नई दिल्ली, एजेंसी। एप्पल ने 2025 में भारत से 50 अरब डॉलर के आईफोन निर्यात किए, जो देश के एक बड़ी उपलब्धि है। रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की और इसका श्रेय 'मेक इन इंडिया' पहल और उत्पादक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बदलाव को दिया।

वैष्णव ने कहा, पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उत्पादन छह गुना बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़ गया है। इस प्रगति ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को शीर्ष तीन निर्यात होने वाली चीज़ों में शामिल कर दिया है। बता दें कि वित्त वर्ष 21 से 25 तक अपने पांच साल की पीएलआई अवधि के दौरान, सैमसंग ने लगभग 17 अरब डॉलर के उपकरण निर्यात किए थे।

उत्पादक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हो रहे बदलाव

उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब 25 लाख नौकरियां उपलब्ध करा रहा है।

इंटर्नशिप योजना और आकर्षक होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट में जल्द ही कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, योजना के तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी के मध्य होने की संभावना है और इसमें इंटर्नशिप की अवधि सहित कुछ नियमों में संशोधन किया जा सकता है। इन बदलावों का मकसद युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और योजना को ज्यादा आकर्षक बनाना है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में ऑफर स्वीकार करने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटी है। पहले चरण में जहां लगभग 28 हजार युवाओं ने इंटर्नशिप ऑफर स्वीकार किए थे, वहीं दूसरे चरण में यह संख्या घटकर करीब 24 हजार रह गई।

अधिकारियों का मानना है कि 12 महीने की लंबी इंटर्नशिप अवधि और कई मामलों में प्रोफाइल व उम्मीदवार की रुचि के बीच तालमेल न होना इसकी बड़ी वजह है। सरकार अब कुछ क्षेत्रों, खासकर सेवा क्षेत्र, में इंटर्नशिप की अवधि को कम करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों से जुड़े छात्रों के लिए आयु सीमा में ढील देने की मांग पर भी मंथन चल रहा है।

वित्तीय सहायता में फिलहाल कोई बदलाव नहीं

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता में फिलहाल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। चयनित इंटर्न को जॉइनिंग पर ₹6,000 की एकमुश्त राशि, हर महीने ₹5,000 का स्टाइपेंड (जिसमें सरकार और कंपनी का योगदान शामिल है) और बीमा कवर की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देना है। प्रस्तावित बदलावों से उम्मीद है कि योजना की स्वीकार्यता बढ़ेगी और ज्यादा युवा इससे जुड़ पाएंगे।

एनबीएफसी ऋण मानक मजबूत रखें : आरबीआई

- शिकायतों के तेजी से समाधान पर जोर दिया
- परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाए

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऋण देने के मानकों को मजबूत रखने और परिसंपत्ति गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने पर जोर दिया। उन्होंने सोमवार को चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह बात कही।

विनियामक संस्थाओं के साथ रिजर्व बैंक के लगातार जुड़ाव के तहत गवर्नर ने सरकारी एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित चुनिंदा एनबीएफसी के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि गवर्नर ने अपने शुरुआती संबोधन में ऋण प्रवाह को आसान बनाने में एनबीएफसी और एचएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। मल्होत्रा ने इस क्षेत्र में भरोसा बनाए रखने के साथ ही शिकायतों के तेजी से समाधान पर जोर दिया।

रिजर्व बैंक ने इससे पहले 13 फरवरी, 2025 को एनबीएफसी के साथ इसी तरह की बैठक की थी। जो कुल मिलाकर एनबीएफसी क्षेत्र की लगभग 53 प्रतिशत परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

तनाव में बढ़ोतरी से सोना-चांदी में तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत रुझानों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोने का भाव 960 बढ़कर 1,40,400 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना इससे पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को 1,39,440 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

व्यापारियों ने कहा कि भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोना और चांदी दोनों में तेजी आई।

चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल जारी रहा। सोमवार को चांदी 2,600 चढ़कर 2,44,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई।

इजराइल से व्यापार रुपये में करने को तैयार स्टेट बैंक

- भारतीय स्टेट बैंक रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा

यरुशलम, एजेंसी। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक संबंधों में गहराई लाने और मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी चर्चाओं के बीच इजराइल में उपस्थित एकमात्र भारतीय ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक रुपये में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहा है।

एसबीआई इजराइल के सीईओ वी. मणिवन्नन ने कहा, भारत के सहयोगी देशों से होने वाले महत्वपूर्ण व्यापार एवं वैश्विक व्यापार समुदाय में भारतीय रुपये में व्यापार करने की बढ़ती रुचि को देखते हुए, हमारे बैंकिंग नियामक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के निर्यात एवं आयात का निपटान भारतीय रुपये में करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस व्यवस्था के तहत इजराइल को भागीदार देशों में से एक के रूप में चुना गया है।'

एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से निर्यात/आयात करने वाली इजराइली संस्थाएं भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करेंगी और देंगी। उन्होंने कहा, 'एसबीआई तेल अवीव के पास इन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां मौजूद हैं।'

बीमा में भी 'सिबिल' जैसी रेटिंग की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। अस्पतालों, क्लिनिक आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया की एक इकाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिए बीमाकर्ताओं तथा टीपीए के लिए 'सिबिल' जैसी रेटिंग प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया है।

सिबिल-जैसी रेटिंग रूपरेखा से आशय ऐसी प्रणाली से है जो किसी इकाई की साख या जोखिम स्तर को आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है।

एएचपीआई की पश्चिम उप्र की इकाई के अध्यक्ष डॉ. अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, 'बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में 'सिबिल स्कोर' पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं।

कारपोरेट कॉर्नर

हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने नए साल का स्वागत सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया। एमडी डॉ. एस. पी मोहंती ने वृद्धाश्रम का दौरा कर बुजुर्गों के साथ सौहार्द और गर्मजोशी बांटी। सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर यूनिटों में स्थ्य और आवश्यक वस्तुएं वितरित कर समाज के कमजोर वर्गों की मदद की गई।

भारत मंडपम में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 43वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मौजूद थे। इस वर्ष एसपीए से 373 विद्यार्थियों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिनमें 20 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने भारत सरकार का कैलेंडर 2026 जारी किया। भारत@2026 : सेवा, सुशासन और समृद्धि थीम पर आधारित यह कैलेंडर देश की विकास यात्रा, शासन की प्राथमिकताओं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को दर्शाता है।

डीजी एनसीसी कैंप में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर देशभर से आए 2,406 कैडेट्स ने परेड में भाग लिया। इनमें 25 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि एनसीसी अब देश के 90 प्रतिशत से अधिक जिलों तक पहुंच चुकी है।

दिल्ली में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय नृत्य-संगीत महोत्सव का आयोजन होगा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 16 से 18 जनवरी 2026 तक इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय महोत्सव बांसरा पार्क में शाम 4 बजे से शुरू होगा और आम लोगों के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। इसमें आठ देशों के 174 कलाकार हिस्सा लेंगे। उद्घाटन प्रस्तुति में डॉ. एल. सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति मुख्य आकर्षण होंगे। नृत्य, संगीत और लोक कला की विविध प्रस्तुतियां दर्शकों को वैश्विक संस्कृति से रूबरू कराएंगी।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर कस्टम्स सुपरिंटेंडेंट, अशोक कुमार ने इंटर-मिनिस्ट्री बेस्ट फिजीक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर कस्टम्स विभाग का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

फर्जी कॉल और संदेश न रोकने पर जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, एजेंसी। दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी कॉल और संदेशों को रोकने में विफल रहने के कारण दूरसंचार परिचालकों पर 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। वर्ष 2020 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए लगाए गए इस जुर्माने को दूरसंचार परिचालकों ने चुनौती दी है।

सूत्र ने बताया कि ग्राहकों की शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने और फर्जी कॉल करने वाले दूरसंचार कनेक्शनों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर 150 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।

ट्राई उन दूरसंचार परिचालकों पर जुर्माना लगाता है, जो वित्तीय दंड से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं। ये नियम एक दूरसंचार परिचालक के लिए प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र में प्रति माह 50 लाख रुपये तक के वित्तीय दंड का प्रावधान करते हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर वित्तीय दंड इसलिए नहीं लगाया जाता है कि किसी ने उनके नेटवर्क के माध्यम से स्पैम भेजा है, बल्कि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वे नियमों के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहते हैं।

ट्राई ने 21 लाख से अधिक कनेक्शन काटे

ट्राई ने पिछले एक साल में 21 लाख से अधिक 'स्पैमर्स' के कनेक्शन काट दिए हैं और एक लाख से अधिक संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया है। नियामक ने एक डीएनडी ऐप पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को केवल 4-6 क्लिक में शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। सूत्र ने बताया कि जहां पंजीकृत दूरसंचार विपणनकर्ता सख्त नियमों के अधीन हैं, वहीं अब ज्यादातर स्पैम 10 अंकों के मोबाइल नंबरों से अपंजीकृत व्यक्ति भेजते हैं।